3 राजधानी
पुराने वाहन को कबाड़ करें, नया छूट में खरीदें

6 अभिमत
दीर्घकालीन विकास को लक्षित बजट

10 राष्ट्रीय
कर्नाटक सरकार ने बदला रामनगर जिले का नाम

11 विदेश
जयशंकर मिले रूसी विदेश मंत्री से

RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 12 अंक 258
नई दिल्ली, शनिवार, 27 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

मुझे नेतृत्व करना अच्छा लगता है

स्पोर्ट्स-12

ओलंपिक से चंद घंटे पहले फ्रांस में रेलवे लाइन नेटवर्क पर हमला

पीटीआई। पेरिस

ओलंपिक खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले फ्रांस के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को निशाना बनाकर की गई तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से देश तथा यूरोप के विभिन्न हिस्सों से राजधानी पेरिस तक संचालित की जाने वाली ट्रेन सेवा शुक्रवार को प्रभावित हुई। अधिकारियों ने इन हमलों को आपराधिक कृत्य करार दिया। फ्रांस के प्रधानमंत्री गेब्रियल अट्टल ने कहा कि ओलंपिक की पूर्व संध्या पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने देश के मुख्य हिस्सों में फैले हाई स्पीड रेल नेटवर्क को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क को बाधित करना था। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के उद्घघाटन समारोह से महज कुछ घंटों पहले पेरिस की ओर जाने वाले उत्तर, पूर्व और पश्चिम के मुख्य मार्गों को चरणबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। अट्टल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इन घटनाओं के गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि हजारों लोग ओलंपिक या छुट्टियों के लिए पेरिस जाने की कोशिश करते समय बीच रास्ते में ही फंस जाएंगे।

पेरिस में रेलवे लाइन नेटवर्क में तोड़फोड़ के बाद गेर डू नोर्ड स्टेशन पर फंसे यात्री।

अधिकारियों के मुताबिक, ओलंपिक खेलों के मद्देनजर पूरी दुनिया की नजरें पेरिस पर थीं, ऐसे में इन हमलों से अकेले शुक्रवार को ढाई लाख यात्रियों के प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि रेल लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से ट्रेन परिचालन सप्ताहांत और इससे अधिक समय तक प्रभावित रहने की आशंका है। फ्रांस के परिवहन मंत्री पैट्रिस वर्गीते ने बताया कि जिन जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुईं, वहां से लोगों को भागते देखा गया और इन स्थानों पर आग लगाने के लिए इस्तेमाल चीजें भी बरामद की गईं। वर्गीते ने कहा, हर चीज इंगित करती है कि ये आपराधिक घटनाएं हैं। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं के कारण पेरिस को फ्रांस के अन्य हिस्सों और पड़ोसी देशों से जोड़ने वाली हाई-स्पीड ट्रेन का परिचालन ठप पड़ गया।

बीएफएम टेलीविजन से बातचीत में उन्होंने कहा कि ओलंपिक उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पेरिस की यात्रा की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा छुट्टियां मनाने निकले कई पर्यटकों की भी पेरिस और अन्य जगहों की यात्रा करने की योजना थी। पेरिस में अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच सीन नदी और इसके किनारे एक शानदार परेड निकालने की तैयारियों में जुटे थे कि तभी अटलांटिक, नॉर्ड और एस्ट में हाई-स्पीड लाइनों पर पटरियों के पास गोलीबारी की सूचना मिली। गोलीबारी की इन घटनाओं से पेरिस के प्रमुख मॉन्टपर्नासे स्टेशन पर ट्रेन परिचालन खासतौर पर प्रभावित हुआ। सोशल मीडीया पर साझा किए गए वीडियो में मॉन्टपर्नासे स्टेशन का हॉल यात्रियों से खचाखच भरा हुआ देखा जा सकता है। पेरिस के पुलिस के प्रमुख लॉरेंट नुनेज ने फ्रांस इन्फो टेलीविजन को बताया कि टीजीवी हाई-स्पीड नेटवर्क पर ट्रेन परिचालन ठप करने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए हमलों के बाद पेरिस पुलिस ने अपने कर्मियों को पेरिस के रेलवे स्टेशनों की ओर भेज दिया। यूरोप के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक गारे डु नॉर्ड पर कई यात्री शुक्रवार सुबह से ही डिस्प्ले बोर्ड पर नजर टिकाए हुए थे, क्योंकि उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को जाने वाली अधिकतर ट्रेन देरी से चल रही थीं। लंदन की ट्रेन का इंतजार कर रही सारा मोसले नाम की यात्री ने कहा, यह ओलंपिक की मेजबानी की बहुत घटिया शुरुआत है। (शेष पेज 9)

पाक ने अतीत से सबक नहीं सीखा: प्रधानमंत्री

मोहित कंधारी। जम्मू

द्रास में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के अवसर पर पड़ोसी देश को एक संक्षिप्त संदेश भेजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सैनिक पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा। तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद लद्दाख की अपनी पहली यात्रा में मोदी ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि उसने अतीत से कुछ नहीं सीखा है। बिना कोई लांछन लगाए प्रधानमंत्री ने कहा, कारगिल में हमने न केवल युद्ध जीता, बल्कि सच्चाई, संयम और शक्ति का अविश्वसनीय उदाहरण भी पेश किया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के धोखे पर उस समय प्रकाश डाला जब भारत शांति बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, सच्चाई से झूठ और आतंक को घुटनों पर ला दिया गया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अतीत में हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा है और प्रासंगिक बने रहने के लिए आतंकवाद और छद्म युद्ध की आड़ में युद्ध छेड़ रखा है।

कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आका सीधे मेरी आवाज सुन सकते हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आतंकवाद के संरक्षकों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। हमारे सैनिक पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दोहराया, भारत विकास के रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पा लेगा, चाहे वह लद्दाख हो या जम्मू-कश्मीर। 26 जुलाई, 1999 को, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफल परिणति की घोषणा की, जिसमें लगभग तीन महीने की लंबी लड़ाई के बाद कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष पर पाकिस्तानी घुसपैठियों/सेना के नियमित लोगों द्वारा कब्जा किए गए स्थानों को पुन: प्राप्त कर लिया गया। अग्निपथ योजना पर बढ़ रही राजनीतिक ताकत का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युवा और लगातार युद्ध के लिए तैयार रखना है।

प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील विषय के घोर राजनीतिकरण का जिक्र करते हुए कहा, सच्चाई तो यह है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश को सक्षम युवा भी मिलेंगे। निजी क्षेत्र और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है। अग्निपथ योजना के पीछे पेंशन का बोझ बचाने की मंशा को मुख्य कारण बताए जाने वाले दुष्प्रचार को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि आज भर्ती होने वाले सैनिकों की पेंशन का बोझ 30 साल बाद आएगा, इसलिए इसके पीछे का कारण यह नहीं हो सकता। योजना। उन्होंने कहा, हमने सशस्त्र बलों द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान किया है क्योंकि हमारे लिए देश की सुरक्षा राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के युवाओं को गुमराह करने वालों को अतीत में सशस्त्र बलों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। वन रैंक वन पेंशन पर पिछली सरकारों द्वारा किए गए झूठे वादों को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि यह वर्तमान सरकार थी जिसने इस योजना को लागू किया जहां पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए गए। उन्होंने आगे पिछली सरकारों की उपेक्षा की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी शहीदों (शेष पेज 9)

कांवड़ मार्ग पर नेमप्लेट मामले में कोर्ट ने अंतरिम रोक बढ़ाई

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी उन निर्देशों पर रोक लगाते हुए 22 जुलाई के अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखने का निर्देश दिया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने के दौरान शिवलिंगों पर जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में भक्त गंगा से पवित्र जल की कांवड़ लेकर आते हैं। कई श्रद्धालु इस महीने में मांस खाने से परहेज करते हैं, जिसे वे पवित्र मानते हैं। कई लोग तो प्याज और लहसुन युक्त भोजन भी नहीं खाते।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि वह 22 जुलाई के आदेश पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करेगी, क्योंकि हमने अपने 22 जुलाई के आदेश में जो कुछ कहा जाना था, वह कह दिया है। हम किसी को नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पीठ ने मध्य प्रदेश और

उत्तराखंड सरकारों से उनके संबंधित निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकारों के जवाबों पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी और मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त के लिए तय की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन में भाजपा शासित नगर निकाय ने भी दुकान मालिकों को इसी तरह का निर्देश जारी किया था। उज्जैन में भगवान शिव का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने (शेष पेज 9)

सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर बंगाल, केरल के राज्यपालों के सचिवों व केंद्र से जवाब मांगा

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत विपक्षी दलों द्वारा शासित केरल और पश्चिम बंगाल की उन अलग-अलग याचिकाओं पर विचार करने पर शुक्रवार को सहमत हो गया जिनमें आरोप लगाया गया है कि संबंधित विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दी गई। केरल ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे थे और उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और केरल के राज्यपाल खान एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस के सचिवों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस नीत पश्चिम बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया कि वह याचिका में गृह मंत्रालय को भी पक्ष बनाए। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाम (शेष पेज 9)

नीति आयोग की बैठक में ममता होंगी शामिल

- कई गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शामिल होने से किया इनकार

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नई दिल्ली स्थित बंग भवन पहुंची।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में शनिवार को नीति आयोग की पहली बैठक का कई गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा बहिष्कार का आह्वान किया जाएगा। हालांकि मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी, जिन्होंने नीति आयोग को खत्म करने और उसकी जगह योजना आयोग लाने का आह्वान किया है। कांग्रेस और उसके गठबंधन शासित राज्यों जैसे झारखंड जैसे राज्यों ने, जो इंडिया गुट का हिस्सा हैं, राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, दिल्ली, पंजाब और केरल ने भी बैठक का हिस्सा नहीं बनने की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि वे केंद्रीय बजट में अपने राज्यों के प्रति कथित पूर्वाग्रह को लेकर बैठक में शामिल नहीं होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एम के स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) नेता पिन्नाराय विजयन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली और पंजाब सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने का आह्वान किया।

बनर्जी ने कहा, नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए और योजना आयोग को वापस लाना चाहिए। मैंने सोचा कि साझा मंच पर हमारी आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, भले ही मैं जानता हूं कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। उन्होंने भाग लेने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वह इस अवसर का उपयोग 'भेदभावपूर्ण बजट' और 'बंगाल और अन्य विपक्षी शासित राज्यों को विभाजित करने की साजिश' के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बैठक से सात दिन पहले अपना लिखित भाषण भेजने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने किया और यह केंद्रीय बजट पेश होने से पहले था।

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा, मैं कुछ देर के लिए बैठक में रुकूंगी। अगर मुझे बैठक में अपना भाषण देने और बजट में विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव और राजनीतिक पूर्वाग्रह के अलावा रची जा रही साजिश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का मौका मिला तो मैं ऐसा करूंगी, अन्यथा मैं बैठक से बाहर चली जाऊंगी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मोदी नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीति आयोग की शीर्ष संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बयान के अनुसार, बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

एनटीए ने घोषित किए नीट-यूजी के अंतिम परिणाम

पीटीआई। नई दिल्ली

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी के अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भौतिकी के एक प्रश्न के अंकों को ध्यान में रखते हुए परिणाम घोषित किए गए। एनटीए ने कहा था कि इस प्रश्न के दो सही उत्तर हैं। एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुन: संशोधित स्कोर कार्ड को अब घोषित कर दिया गया है। पहले टॉपर घोषित किए गए 67 उम्मीदवारों में से 44 ने उस विशेष भौतिकी प्रश्न के लिए दिए गए अंकों के कारण पूरे अंक प्राप्त किए थे। बाद में टॉपर की संख्या घटाकर 61 कर दी गई थी, क्योंकि एजेंसी ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय के नुकसान की भरपाई के लिए छह उम्मीदवारों को दिए गए कृपांक वापस ले लिए थे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि परीक्षा की विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) नीट-यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है।

क्रिकेट पिच पर बेटियों ने फिर दिखाया दमखम

- गत एशिया कप चैंपियन भारत फिर फाइनल में, एकतरफा सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया, स्मृति और रेणुका चमकीं

पीटीआई। दाम्बुला

तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने शुरूआती ओवरों में तीन विकेट चटकाकर बांग्लादेश की पारी को झकझोरा तो वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर महिला टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट की शानदार जीत दिलाई। भारत ने बांग्लादेश को आठ विकेट पर 80 रन

पर रोकने के बाद 11 ओवर में बिना किसी नुकसान के 83 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की। मंधाना ने 39 गेंद में नौ चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 55 और शेफाली वर्मा ने 28 गेंद में दो चौके की मदद से नाबाद 26 रन का योगदान दिया। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी से भारत को 54 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

भारतीय टीम के सामने रविवार को खेले जाने वाले फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता की चुनौती होगी। लक्ष्य का पीछा करते हुए मंधाना और शेफाली ने मैदान के चारों ओर मन मुताबिक शॉट लगाए। टीम ने पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 46 रन बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। शेफाली को 21 रन के स्कोर पर राबिया खान ने कैच टपकाकर जीवनदान दिया तो वहीं जहांआरा आलम की गेंद पर मंधाना के 35 रन के स्कोर पर कैच आउट होने के बाद गेंद नो बॉल करार दी गई। इस वामहस्त बल्लेबाज ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए जिसमें मारुफा अख्तर की गेंद पर खेला गया शॉट दिलकश था। उन्होंने जहांआरा के खिलाफ डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का भी जड़ा। भारत की जीत पर लगभग उसी समय मुहर लग गई थी जब गेंदबाजों ने बांग्लादेश को महज 80 रन पर रोक दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका को स्पिनर राधा यादव (14 रन पर तीन विकेट) का शानदार साथ मिला। रेणुका ने पारी की शुरुआत में लगातार चार ओवर (शेष पेज 9)

असम के मोइदम को यूनेस्को का विश्व धरोहर टैग

अर्चना ज्योति। नई दिल्ली

असम के ऐतिहासिक खजाने चराइदेव मोइदाम शाही दफन परिसर और लगभग 600 वर्षों तक पूर्वोत्तर राज्य पर शासन करने वाले अहोम राजवंश द्वारा निर्मित मंदिरों को प्रतिष्ठित यूनेस्को टैग प्राप्त हुआ है, जो इस सम्मान को प्राप्त करने वाला क्षेत्र का पहला सांस्कृतिक स्थल है। इसकी घोषणा भारत में 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान की गई। इस अतिरिक्त के साथ, भारत अब गर्व के साथ 43 विश्व धरोहर स्थलों की मेजबानी करता है। असम के चराइदेव जिले में मोइदाम अपनी आकर्षक पिरामिड जैसी संरचनाओं के साथ राज्य के शाही अतीत को दर्शाता है, और साथ ही ताई-अहोम राजवंश के इतिहास, वास्तुकला और लोककथाओं का एक आकर्षक मिश्रण पेश करता है। यूनेस्को टैग

ताई-अहोम राजवंश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक योगदान की वैश्विक सराहना को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोइदम्स के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए, शामिल किए जाने पर गर्व और खुशी व्यक्त की। जबकि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फैसले को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित दिन कहा।

मोइदम्स को वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चराइदेव में मोइदाम गौरवशाली अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जो पूर्वजों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखता है। मुझे उम्मीद है कि अधिक लोग महान अहोम शासन और संस्कृति के बारे में सीखेंगे। खुशी है कि मोइदाम विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया है। मोइदम एक टीला दफन प्रणाली है जो अहोम राजाओं और रानियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती थी। इनका निर्माण ईंटों, पत्थर या मिट्टी से बनी खोखली तिजोरी के ऊपर मिट्टी का आवरण प्रदान करके किया गया था।विश्व धरोहर समिति के सलाहकार निकाय, आईसीओएमओएस के एक प्रवक्ता ने कहा, निर्दिष्ट साइट में विभिन्न आकारों के 90 मोइदाम हैं, जो 600 वर्षों की अवधि में बनाए गए थे, और इसमें औपचारिक रास्ते और पानी की निकासी जैसी अन्य सांस्कृतिक विशेषताएं शामिल हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि वास्तव में 150 से अधिक मोइदाम हैं, (शेष पेज 9)

कांवड़ यात्रा के लिए रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई

नोएडा डिपो से 60 बसें हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए आरक्षित, आज से डायवर्जन लागू

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

कांवड़ यात्रा में यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रोडवेज और परिवहन निगम ने बसों की संख्या में बढ़ोतरी की है। ये बस नोएडा से हरिद्वार, ऋषिकेश की तरफ जा रही है। परिवहन निगम ने 60 बसों की फ्लीट को कांवड़ यात्रियों के लिए लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। वहीं कांवड़ शिविर के पास से यातायात रूट को बंद किया गया है।

नोएडा बस डिपो के एआरएम एनपी सिंह ने बताया कि शहर में पिछले चार दिन में लगातार कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सामान्य दिनों में नोएडा से उत्तराखंड के लिए आठ बस जाती थी। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पिछले दस दिनों बस की संख्या को बढ़ाया गया है। इस समय कुल 60 बस उत्तराखंड जा रही हैं।

कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है। बस को अपने गंतव्य तक जाने के लिए लंबे रास्तों से होकर जाना पड़ा रहा है। ऐसे में रोडवेज बस के किराये में बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ोतरी मेरठ, हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाली बसों के किराए में की गई है। रूट डायवर्जन होने से किराये में 20-30 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है।

पांच अगस्त को डायवर्जन खत्म होने के बाद पहले वाला किराया लागू कर दिया जाएगा। सेक्टर 14ए स्थित शनि मंदिर के पास बने कांवड़ शिविर को आज से शुरू कर दिया गया। इसका संचालन शनि शक्तिपीठ बीते 13 सालों से लगातार करता आ रहा है। इस बार 1000 कांवड़ियों के लिए विश्राम की व्यवस्था की गई है। मेडिकल सुविधा के साथ 24 घंटे खाने-पीने की व्यवस्था रहेगी। नोएडा से कालिंदी कुंज जाने वाले मार्ग की एक लेन आज से माल वाहक वाहनों के लिए बंद रहेगी।

फाइल फोटो

गाजियाबाद में लगे पोस्टर- गर्व से कहो हम हिन्दू हैं

गाजियाबाद। कांवड़ मार्ग के दुकानदारों की नेमप्लेट को लेकर घमासान जारी है। इस बीच गाजियाबाद में शुक्रवार को हिन्दू युवा वाहिनी ने कुछ दुकानों पर पोस्टर चिपकाए। इन पोस्टरों पर लिखा था- गर्व से कहो हम हिन्दू हैं। इन पोस्टरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भगवान महादेव का फोटो भी छपा हुआ था। पोस्टरों का मकसद साफ था कि इन्हें देखकर कांवड़िए हिन्दू दुकानदारों की पहचान कर सकें। इस तरह के पोस्टर फिलहाल गाजियाबाद के प्रमुख दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर के आसपास दुकानदारों के यहां लगाए गए हैं। दरअसल, पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों को अपने नाम वाली नेमप्लेट लगाने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। यूपी की तर्ज पर ये आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और सुनवाई जारी है।

डीसीपी सिटी जोन ने डाला दूधेश्वरनाथ मंदिर पर डेरा

गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से सुगम, सरल, सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं बाधारहित बनाने के लिये डीसीपी सीटी जोन राजेश कुमार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही दूधेश्वरनाथ मंदिर में लाखों कांवडियों/श्रद्धालुओं के द्वारा अपने अराध्य देव महादेव को जलाभिषेक की व्यवस्था को फुल प्रूफ सेफ व सिस्टेमेटिक बनाने के क्रम में श्री कुमार ने इस शिवालय में ही डेरा डाल दिया है। गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ उनकी कुशलक्षेम भी पूछ रहे हैं। इसके अलावा श्री कुमार कांवड़ मार्गों पर स्थापित किये गये कांवड़सेवा शिविरों और दूधेवरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले कांवडि ?ों के बनाये गये अस्थाई प्रवासस्थलों का भी निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं।

साथ ही, चिल्ला लाल बत्ती से ओखला पक्षी विहार के प्रवेश द्वार तक सभी तरह के वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ यात्रा के चलते यह निर्णय लिया गया है। डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

लोगों से अपील है कि डायवर्जन का पालन करें। चिल्ला लालबत्ती से ओखला पक्षी विहार गेट तक मार्ग पर वाहनों का आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

गाजियाबाद में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी

कांवड़ यात्रा

● जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जारी किया आदेश

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 29 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है।

जिले में पहले ही 22 अगस्त से यातायात विभाग ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया था। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जनपद गाजियाबाद के विद्यालयों में बच्चों, बसों के आवागमन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित सभी स्कूल 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे।

जिलाधिकारी की तरफ से यह पत्र सभी स्कूलों को भेजा जा चुका है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सूचना जारी करते हुए निर्देश दिया है कि यह आदेश सभी स्कूलों तथा शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी बोर्ड के हों। सीबीएसई, आईसीएसई, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं मदरसा, संस्कृत बोर्ड के प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों को उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस कमिश्नरेट ने कांवड़ मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। श्रावण मास 22 जुलाई से प्रारंभ होने तथा मुख्य जलाभिषेक शिवरात्रि 2 अगस्त को होने के कारण गाजियाबाद सीमा से होकर बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों और जनपदों में जाते हैं। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात कमिश्नरेट-गाजियाबाद ने 22 जुलाई की रात से भारी वाहनों और 26 जुलाई की रात से छोटे एवं हल्के वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।

अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या

● भांजे के साथ मिलकर गला दबाकर मारने का आरोप

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा के थाना फेज-3 में व्यक्ति ने अपने भांजे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। उसके शव को कमरे में छिपाकर फरार हो गया। कमरे से बदबू आने पर आस पास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। महिला की पहचान रेखा गुप्ता हुई है। गले पर निशान मिले है जाहिर है, गला घोटकर महिला की हत्या की गई है। महिला के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। दोनों की शादी के 13 साल हुए थे।

कमरे के अंदर बंद कर चले गए बाहर एडीसीपी हृदेश कठेरिया ने बताया कि थाना फेज-3 क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव में रहने वाली रेखा गुप्ता पति सर्वेश गुप्ता के साथ गढ़ी चौखंडी गांव में किराए के मकान में रहती थी। पुलिस को सूचना मिली कि सर्वेश और उसके भांजे पवन गुप्ता ने रेखा को मारकर कमरे के अंदर छिपा रखा है।

बदबू भी आ रही थी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। टीम गठित की और सर्वेश को हिरासत में लिया। कैसे दिया वारदात को अंजाम मंगलवार को सर्वेश ने अपने भांजे पवन गुप्ता को गड़ी चौखंडी घर बुलाया। रात दस बजे के करीब दोनों शराब पी। इसके बाद सर्वेश ने भांजे से रेखा के अफेयर के बारे में बताया। दोनों आग बबूला हो गए। इसके बाद भांजा और सर्वेश दोनों नीचे आए। भांजे से रेखा का हाथ पकड़ा और सर्वेश ने उसका गला दबा दिया। इसके बाद रेखा को कमरे बंद कर दिया।

दोनों वापस छत पर आए सो गए। बुधवार को सर्वेश पवन को शनि मंदिर के पास छोड़ आया। वापस घर आकर पड़ोस में सोने के लिए चला गया। मकान मालिक को शक होने पर उसने सर्वेश से रेखा के बारे में पूछा तो वो घबरा गया और भाग गया। इस दौरान कमरे से बदबू भी आ रही थी। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। रेखा के कैरेक्टर पर था शक पुलिस ने बताया कि पति को शक था कि रेखा उसके पीठ पीछे किसी और से बातचीत करती थी। कई बार इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। सर्वेश ने प्लान करके अपने भांजे के साथ मिलकर रेखा की हत्या की।

बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली

गाजियाबाद। क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र अंतर्गत तिगरी गोल चक्कर के पास बीती रात नौ बजे के आस-पास हुए वारदात के दौरान बाइक पर सवा होकर आये दो बदमाशों ने पहले तो खोड़ा निवासी अनिल के साथ लूटपाट का प्रयास किया और फिर लूट का विरोध होने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। उक्त वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची क्रासिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने बदमाशों की गोली लगने से घायल हुए अनिल को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाकर उक्त अपाधिक मामले की गुत्थी सुलझाने के प्रयास शुरू कर दिये। इस संदर्भ में पुलिस का कहना है कि गोली मारने वाले बाइक सवार बदमाशों को आईडेंटीफाई करने के लिये जहां सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है वहीं इस वारदात की तह तक जाने के लिये हर एंगिल पर जांच की जा रही है।

कोबरा का वीडियो वायरल करने पर सिपाही लाइन हाजिर

● मधुबन बापूधाम थाने में मिली था सांप

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में एक कांस्टेबल मंगल को सिर्फ इसलिए लाइन हाजिर कर दिया गया, क्योंकि उसने थाने के लॉकअप में घुसे कोबरा सांप की वीडियो बनाया।

इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह वीडियो धीरे-धीरे वायरल होने लगा। अफसरों ने माना है कि ऐसा करके पुलिसकर्मी ने थाने की गोपनीयता भंग की। पूरा मामला 11 जुलाई को मधुबन बापूधाम थाने का है। यहां लॉकअप में एक कोबरा सांप घुस आया। गनीमत ये रही कि उस वक्त लॉकअप में कोई व्यक्ति बंद नहीं था। पुलिस के फोन करने पर वन विभाग की टीम आई और कोबरा सांप को पकड़कर ले गई। उस वक्त थाने के वॉट्सएप ग्रुप में ये वीडियो डाला था और वहां से वायरल होता चला गया। 14 जुलाई को अफसरों ने इस सिपाही को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी कर दिया गया। 24 जुलाई को थानेदार ने सिपाही को रिलीव कर दिया है।

ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुलिस अफसरों ने जांच कराई कि लॉकअप के अंदर का वीडियो कैसे वायरल हुआ। पता चला कि एक कांस्टेबल मंगल ने

राजकुमार हत्याकांड ने पकड़ा तूल, एसीपी को हटाने की मांग

● परिजन बोले, आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

एसीपी मोदीनगर ज्ञानप्रकाश राय को हटने और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर परिजनों ने 12 घंटे बाद भी शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जानें दिया है। दलित समाज के लोग जीवन अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं। एसीपी अंकुर विहार व थाना प्रभारी परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।

सीकरी मार्ग रेलवे फाटक के पास गुरुवार रात को पिता रामकुमार जाटव व सौरभ को गोली मार दी गई थीं। पिता की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पुत्र की हालात गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ही यह हत्या हुई है। एक साल पहले हुए झगड़े में यदि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर लेती तो यह हत्या नहीं होती है। मौके पर पीएसी की दो बटालियन सहित कई थानों का फोर्स बुला लिया गया है। सीकरी खुर्द रेलवे क्रासिंग बाजार नगर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में है। यहां देर रात तक चहल पहल रहती है। शाम के समय कई रेल गाडियों के आवागमन के दौरान फाटक काफी देर तक बंद रहता है,इससे यहां वाहनों की भी लंबी कतार लगी रहती है। घटना से कुछ समय पहले ही रेलवे फाटक खुला था। रामकुमार अपने पुत्र सौरभ के साथ बाइक पर जैसे ही रेलवे क्रासिंग पार कर सीकरी खुर्द की तरफ बढ़े तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने ब्रेकर पर बाइक धीमी होते ही उन्हे घेरकर फायरिंग कर दी। गोली लगते रामकुमार बाइक सहित नीचे गिए गए। इसके बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर रामकुमार की हत्या कर दी।

संक्षिप्त समाचार

फैक्ट्री में चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

नोएडा। थाना फेस-2 क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री से चोरी करने वाले दो चोरो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने सोने के जेवरात और एक लाख 12 हजार रुपए नगद बरामद किये है। थाना फेस-दो के प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी ने बताया कि बीती रात को एक सूचना के आधार पर थाना पुलिस ने शेखर तथा प्रशांत नामक दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इन बदमाशों ने बीते सप्ताह थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री से साढे पांच लाख रुपये नगद और लाखों रुपए कीमत के जेवरात चोरी किये थे। इनके गैंग के दो बदमाशों को कुछ दिन पूर्व थाना बीटा-दो पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार दोनों आरोपी तभी से फरार चल रहे थे।

फ्लैट से गायब हुई किशोरी, मुकदमा दर्ज

नोएडा। नोएडा से एक किशोरी की लापता होने की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि नोएडा के थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के सर्फाबाद गांव के पास बने जनता फ्लैट से एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। किशोरी के भाई की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सेक्टर-73 सर्फाबाद गांव के पास बने जनता फ्लैट में रहने वाले विनोद (काल्पनिक नाम) ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट बताया कि, उनकी (16 वर्षीय) बहन 8 जुलाई को सुबह 8 बजे घर से बाहर गई थी इसके बाद में वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। किशोरी के गायब होने के बाद से परिजनों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों के शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है और किशोरी की जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है।

उत्तम स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा

गाजियाबाद। शास्त्रीनगर स्थित उत्तम फॉर गर्ल्स स्कूल के खिलाफ गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन की बुद्धिशुद्धि के लिए स्कूल गेट पर हवन किया। एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने कहा कि इस स्कूल में आरटीई के तहत 15 बच्चों का आंवटन हुआ था, लेकिन चार महीनों से स्कूल दाखिले नहीं कर रहा था। 24 जुलाई को एडीएम सिटी गंभीर सिंह, बीएसए और अभिभावकों की मौजूदगी में पांच बच्चों के दाखिले पर सहमति बनी। एडीएम सिटी ने सभी बच्चों के नाम भी एनाउंस किए। 25 जुलाई को जब अभिभावक दाखिला कराने पहुंचे तो दाखिला देने के नाम पर टालते रहे। मामले की जानकारी मिलने पर एडीएम सिटी के निर्देश पर खंडशिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन स्कूल ने दाखिला नहीं दिया। इसके विरोध में अभिभावक गुरुवार से ही स्कूल के अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए।

तीन हजार वर्गमीटर जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाया

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण को हटाने का अभियान लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह प्राधिकरण की टीम ने सेक्टर-44 में अभियान चलाकर करीब 3 हजार वर्गमीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया।

जमीन के चारो ओर बाउंडरी वॉल बनाकर कब्जा किया जा रहा था। ये जमीन प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 में शामिल है। ये जमीन आवासीय श्रेणी में आती है। प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-44 के सदरपुर गांव में करीब 3 हजार वर्गमीटर जमीन प्राधिकरण अधिसूचित और कब्जा प्राप्त जमीन है। भू माफियाओं ने इस जमीन के चारो ओर बाउंडरी करवाकर गेट लगा दिया था। प्राधिकरण को जानकारी मिली।

नियमानुसार पहले नोटिस जारी किया गया कि इसे तत्काल हटा लिया जाए। अन्यथा प्राधिकरण इस बाउंडरी को ध्वस्त कर देगा। ऐसे में शुक्रवार सुबह प्राधिकरण 50 लोगों की टीम और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची।

जब तक अतिक्रमण कर्ता कुछ समझता प्राधिकरण ने बाउंडरी वॉल और गेट को तोड़ते हुए जमीन पर कब्जा कर लिया। इस जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आकी जा रही है।

27 बिल्डरों को मिलेगा जीरो पीरियड का फायदा

पायनियर समचार सेवा। नोएडा

एनजीटी के आदेश से प्रभावित कई बिल्डरों की मांग पर प्राधिकरण पहले भी अल्प समय के लिए करीब 27 दिन के आसपास का जीरो पीरियड मिला है। अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि को दो साल की समय से घटा दिया जाएगा। इसके बाद ही बकाया की दोबारा से गणना की जाएगी। नई गणना के अनुसार ही बिल्डर को पैसा जमा करना होगा। 27 के अलावा जिन बिल्डरों ने अमिताभ कांत सिफारिश पर सहमति दी लेकिन पैसा जमा नहीं किया।

अमिताभ कांत की सिफारिश में कहा गया जो बिल्डर बकाया का 25 प्रतिशत जमा करेगा उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अमिताभ

कांत समिति की सिफारिश के आधार पर नोएडा में 57 बिल्डरों ने सहमति दी। इन सभी बिल्डर को कोविड के दो साल जीरो पीरियड का लाभ दिया गया। इनमें से 27 बिल्डरों ने ही सिफारिश के तहत कुल बकाया का 25 प्रतिशत यानी 270 करोड़ रुपए जमा कराया। इससे 1035 बायर्स की रजिस्ट्री हुई। ये बिल्डर एनजीटी के आदेश से भी प्रभावित थे। ऐसे में केस टू केस बेस पर इनको 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015

● 8 हजार करोड़ का था बकाया, अमिताभ समिति की सिफारिश पर दी थी सहमति

तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जा सकता है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि 57 बिल्डरों पर करीब 8273.78 हजार करोड़ रुपए बकाया था। अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के बाद इन बिल्डरों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड का फायदा दिया गया। यानी कुल बकाया राशि में 1866 करोड़ रुपए कम हो गए। जनवरी में अलग-अलग समूह में 57 बिल्डरों को बुलाकर उन्हें बकाया की जानकारी दी गई। शासनादेश के तहत सहमति होने के बाद 60 दिन के अंदर कुल बकाया में से 25 प्रतिशत धनराशि बिल्डरों को जमा करने थे। इसमें सिर्फ 27 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत के हिसाब से रुपए जमा कराए। अब इन बिल्डरों को ही केस टू केस के आधार पर लाभ दिया जाएगा।

नोएडा में एनजीटी ने ओखला पक्षी विहार के 10 किमी के अंदर निर्माण रोकने का आदेश दिया था, जिसके बाद करीब दो साल तक बिल्डर परियोजनाओं का काम प्रभावित रहा। इस दौरान कई बिल्डरों ने प्राधिकरण से जीरो पीरियड की डिमांड की थी। जिसके तहत 77 दिन का लाभ दिया गया। इसके बाद बिल्डरों को राहत नहीं मिली।

सड़क के किनारे लहूलुहान पड़ा मिला युवक का शव

नोएडा। नोएडा शहर से एक दर्दनाक घटना की सामने आई है। दरअसल नोएडा के थाना फेस 2 क्षेत्र के कचहरी कट के पास सड़क के किनारे एक युवक का शव लहुलुहान अवस्था में बरामद हुआ। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस युवक की मौत का कारण कोई दुर्घटना बता रही है, इधर युवक का शव मिलने के बाद लोगों का मानना है किसी हत्या कर शव को फेंका है। बता दें गुरुवार की रात करीब 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कचहरी कट के पास एक युवक लहु लुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिसकर्मियों ने युवक को तुरंत भंगेल स्थित सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके।

एआरटीओ ऑफिस पहुंचे डीएम, गंदगी देखकर भड़के

● दलालों के सक्रिय होने की मिली थी शिकायत

● लर्निंग लाइसेंस सेंटर पर फाइलों को चेक किया

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

दलालों पर अंकुश लगाने के लिए गौतमबुद्धनगर के एआरटीओ ऑफिस पहुंचे जिलाधिकारी।

डीएम मनीष वर्मा और डीसीपी राम बदन सिंह शुक्रवार दोपहर में अचानक एआरटीओ ऑफिस और रजिस्ट्री विभाग पहुंच गए। ये देख वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई।

दरअसल डीएम को शिकायत मिली थी कि एआरटीओ विभाग में दलालों द्वारा काम कराया जा रहा है। डीएम ने यहां आए लोगों से बातचीत की। इसके बाद काउंटर पर जाकर काम कर रहे कर्मचारियों और लाइन में लगे लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि यहां पर समय से काम हो रहा है। हालांकि कुछ एक जगह विलंब होने पर लोगों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में डीएम ने एआरटीओ सिया राम को निर्देशित किया कि किसी प्रकार से आम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां लर्निंग लाइसेंस सेंटर पर भी गए। कई फाइलों को देखा। लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए जो स्लॉट मिला था उस हिसाब से काम हो रहा था कि नही ये भी देखा गया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग में वाहनों की व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने के लिए भी कहा। इसके बाद दोनों अधिकारी रजिस्ट्री विभाग गए। यहां रजिस्ट्री कराने आए लोगों से बातचीत की। साथ ही उनसे भी दलाल के बारे में जानकारी हासिल की।

उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी नियम के विरुद्ध काम करे तो उसकी शिकायत की जाए। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निबंधन विभाग में फैली गंदगी को देखकर निर्देश दिए कि यहां तत्काल साफ-सफाई कराई जाए। यहां आम लोगों से लेकर खास सभी आते है। परिसर को साफ सुथरा रखना हमारा काम है। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्किंग शैली को देखा। दोनों ही अधिकारी करीब एक घंटे तक एआरटीओ और रजिस्ट्री विभाग में रुके।

पुराने वाहन को कबाड़ करें, नया छूट में खरीदें

दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रदूषण की गंभीर समस्या से पार पाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक आसान मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे के तहत पुराने वाहन को कबाड़ कर नए वाहन खरीदने पर दिल्ली सरकार खरीददार को वाहन कर में 50 हजार रुपये तक की छूट दे सकती है। सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास भेजा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, आम आदमी पार्टी के अनुसार, नए पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी परिवहन वाहनों के लिए कर में 15फीसदी की छूट, डीजल परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 10 फीसदी की छूट मोटर वाहन कर रियायतें अधिकतम स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत तक ही होंगी इस कदम का मकसद पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए, स्वच्छ ईंधन वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से, उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।

गहलोत ने बताया कि दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।

इस कदम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस प्रस्ताव को एलजी से मंजूरी मिलने के बाद, नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 फीसदी की होगी। नए पेट्रोल, सीएनजी या

● नए पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी के लिए मोटर वाहन कर में 20 फीसदी, डीजल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की मिलेगी छूट

एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15 प्रतिशत की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालाँकि, दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक खरीद-फरोख्त किया जा सकता है

मालूम हो कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में क्रमशः 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें कहा गया था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वर्ष 2014 के एक आदेश में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगा दिया था। इस बीच आम आदमी पार्टी की सरकार ने करीब 55 लाख ओवर एज वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। कहा गया है कि ऐसे वाहनों के मालिकों के पास पंजीकरण रद्द करने की तिथि के एक वर्ष के भीतर वाहन को दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने का विकल्प है। एक वर्ष के बाद एनओसी जारी नहीं की जाएगी। वाहन मालिक किसी भी नजदीकी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पर या https://vscrap.parivahan.gov.in/ पर स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग एप्लिकेशन के माध्यम से वाहनों को स्क्रैप करा सकते हैं।

कारगिल विजय रजत जयंती के मौके पर भाजपा मुख्यालय से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इसे जेपी नड्डा ने झंडी दिखाई।

उमस से राहत, जलभराव से आफत

● जाम से लोगों को दफ्तर और काम पर पहुंचने में हुई देरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली में एक बार फिर भारी बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली, लेकिन सड़कों पर जलभराव और जाम से हर जगह यातायात बाधित हुआ। इसके चलते शुक्रवार सुबह लोग अपने दफ्तर और काम पर काफी देर से पहुंचे।

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार तड़के से लेकर सुबह तक जमकर बारिश हुई। घंटों तक हुई झमाझम बारिश की वजह से एक बार फिर दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई। जगह-जगह जलभराव और ट्रैफिक में लोग फंसे दिखे। धौला कुआं, दिल्ली कैंट, मायापुरी, राजा गार्डन, पंजाबी बाग, करोल बाग, कनाट प्लेस, इंडिया गेट, चाणक्यपुरी, मोती बाग, लाजपत नगर, सफदरजंग, लोधी रोड, बारापुला, आईटीओ, प्रगति मैदान, पीतमपुरा, रोहिणी, नांगलोई, शाहदरा, वसंत कुंज, आरके पुरम, हौजखास में जमकर बारिश हुई। दिल्ली यातायात पुलिस ने अलर्ट जारी कर जलभराव और नालों का पानी बाहर आने के कारण प्रभावित सड़कों के बारे में यात्रियों को सूचित किया और उन्हें अन्य रास्तों से जाने के लिए कहा। पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मदर टेरेसा क्रीसेंट, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास

इंडिया गेट के पास पानी भरने पर निकासी करते कर्मचारी। फोटो: रंजन डिमरी

न्याय मार्ग, सर एम. विश्वेश्वरैया मोती बाग मेट्रो स्टेशन, शांति पथ, भीकाजी कामा प्लेस और मोतीबाग रिंग रोड बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुंडका इलाके में बारिश के बाद नालों में भरा पानी सड़कों पर आ रहा है और गड्ढों के कारण रोहतक रोड के दोनों मार्गों पर यातायात प्रभावित हो गया है।

बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हिस्सों में से एक मिंटो रोड पर सुबह-सुबह जलभराव हो गया। हालांकि, बाद में पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि सड़क पर भरा पानी बह गया और उसे यातायात के लिए भी खोल दिया गया है। पुलिस ने यात्रियों से तदनुसार अपनी यात्रा करने के लिए कहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राजधानी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.1 डिग्री कम है।

पानी भरने से छोटी कॉलोनियों वाले परेशान : देवेंद्र यादव

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि केजरीवाल ने 2021 में दिल्ली ड्रेनेज सिस्टम मास्टर प्लान 2021 को धरातल पर उतारकर नालियों में जल निकासी के लिए बदलाव लाने के लिए टेक्नीकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। लेकिन 30-35 साल पुरानी 3740 किलोमीटर लम्बाई की 2846 नालियां व नालों के लिए अलग-अलग प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कागजों में ही दबकर रह गई है। यादव ने कहा कि एमसीडी की नाकामियों के कारण दिल्ली वालों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मानसून में जल भराव के कारण परेशान दिल्ली वालों को राहत देने में असफल एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार के पीडब्लूडी और बाढ़ विभाग बहाने बनाना बंद करके एक स्वस्थ और सुचारु ड्रेनेज सिस्टम देने के लिए काम करें।

तुगलकाबाद क्षेत्र में घर की छत गिरने से नवजात बच्ची की मौत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● जर्जर था मकान, परिवार के पांच लोग घायल

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक घर की छत का एक हिस्सा गिरने से एक नवजात बच्ची की मौत हो गई और परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए।

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना तुगलकाबाद इलाके के चुरिया मोहल्ला में तड़के तीन बजे हुई और तब घर में सभी लोग सो रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जानकारी मिली है कि छत का एक हिस्सा गिर गया था। उन्होंने बताया कि एक मंजिला मकान एक संकरी गली में स्थित है और काफी पुराना है। हादसे में सोनू भूरे खान उनकी पत्नी और उनके तीन बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों की उम्र क्रमशः नौ, पांच और चार साल है। पुलिस ने बताया कि हादसे में उनकी दो महीने की पुत्री की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि घायलों का इलाज किया जा रहा है।

डीयू में बनेगा रैगिंग रोधी नियंत्रण कक्ष

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों पर इस वर्ष से 12 अगस्त को रैगिंग रोधी दिवस मनाया जाएगा

दिल्ली विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले रैगिंग की शिकायतों के समाधान के लिए दो संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा। दिल्ली पुलिस के समन्वय से छात्रों का विश्वविद्यालय में परिचय कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी परिसरों के लिए एक-एक नियंत्रण कक्ष एक से 10 अगस्त के बीच चालू रहेंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए विश्वविद्यालय और प्रत्एक कॉलेज परिसर के बाहर सामान्य कपड़ों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसार, इस वर्ष से 12 अगस्त को रैगिंग रोधी दिवस मनाया जाएगा, उसके बाद 12 से 18 अगस्त तक रैगिंग रोधी सप्ताह मनाया जाएगा। बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में ए उपाय तय किए गए। उसने कहा कि विश्वविद्यालय ने दोनों परिसरों में अंग्रेजी और हिंदी में रैगिंग रोधी पोस्टर लगाए हैं।

बयान में कहा गया है, अनुशासनहीनता, रैगिंग के किसी भी कृत्य से विश्वविद्यालय के नियमों और अध्यादेशों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास (चाहने वाले) छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पीजी का स्थानीय पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया है, क्योंकि ऐसे सभी पीजी की उचित सुरक्षा और संरक्षा के लिए क्षेत्रीय पुलिस द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

संपत्ति कर जमा नहीं करने 4 प्रॉपर्टी सील

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में कर-निर्धारण एवं समाहरण विभाग ने सम्पत्ति कर जमा नहीं करने पर 4 संपत्तियों पर बडी कार्रवाही की है।

इस कार्रवाई के तहत कर निर्धारण एवं समाहरण विभाग ने कल्याणपुरी, में 4 संपत्तियो को अटैच किया। इस संदर्भ में निगम के शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के उप-कर निर्धारक एवं समाहर्ता कुंवर बलवंत राव ने बताया कि जिन संपत्तियों पर कार्यवाही की गई उन संपत्तियों पर लगभग 62 लाख रुपये की संपत्तिकर राशि बकाया है। संपत्तिकर एक वैधानिक कर है जिसका भुगतान करना सभी संपत्तिधारकों के लिए अनिवार्य है।

कांवड़ियों की सुविधाएं सुनिश्चित करें अधिकारी : राय

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● पर्यावरण मंत्री ने खिचड़ीपुर में कांवड़ शिविर का किया उद्घाटन

शिव भक्त कांवड़ियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को खिचड़ीपुर में खिचड़ीपुर शिव कांवड़ सेवा समिति शिविर का उद्घाटन किया गया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 185 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए हर जरूरी कदम सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यह शिविर कैंप पूरी तरह से वाटर प्रूफ हैं। इसके अलावा इन कैंपों के अंदर मेडिकल से लेकर पानी, सोने के लिए बेड, कूलर और शौचालय समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है।

खिचड़ीपुर में कांवड़ शिविर का उद्घाटन करते पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ।

सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जल लेने जाते है। इसके बाद लोग अपने-अपने शहर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर दिल्ली सरकार राजधानी में जगह-जगह कांवड़ शिविर लगाती है। जहां कांवड़ियों के रुकने और आराम करने के लिए हर जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। वहीं इस साल उनकी सुविधा के लिए स्थानीय डिस्पेंसरियों को शिविरों से जोड़ा गया है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति के लिए कैट्स एंबुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पतालों को कांवड़ियों के इलाज के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि बारिश की अधिक संभावना है।

कचरा निपटान की स्थिति पर एमसीडी को फटकार लगी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति दयनीय है।

न्यायालय ने एनसीआर में ठोस अपशिष्ट के निपटान से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 3,000 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट अनुपचारित रह जाता है जो जनस्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति का कारण बन सकता है। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने कहा कि राजधानी में प्रतिदिन 11 हजार टन से अधिक ठोस अपशिष्ट पैदा होता है लेकिन एमसीडी द्वारा प्रसंस्करण संयंत्रों की दैनिक क्षमता केवल 8,073 टन है।

पीठ ने कहा, हम न्यायमित्र से सहमत हैं कि इससे जनस्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति पैदा हो सकती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन के मामले में स्थिति दयनीय है। इसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे का तत्काल समाधान निकालने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाएं।

आप का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल 30 को

नई दिल्ली। आम आमदी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गुट 30 को जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा।

आप के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने जानकारी देते हुए कहा कि तनाशाह शासकों की प्रवृत्तियां जग-जाहिर हैं कि वो अपने राजनैतिक द्वेष के कारण किसी को बंदी बना लेते हैं। आज केजरीवाल भी एक राजनैतिक बंदी हैं और उनको डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। संदीप पाठक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की व्यवस्था का मामला है।

पुलिस-वन विभाग ने पक्षियों को कराया आजाद

● काबूतर मार्केट की दो बंद दुकान में की गई छापेमारी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के वन विभाग और पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के कबूतर मार्केट से 1000 पक्षियों को मुक्त कराया गया है जिनमें कुछ विदेशी प्रजातियों के पक्षी भी शामिल हैं।

पशु-पक्षियों के लिए काम करने वाले संगठन पीपुल्स फोर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमल्स (पेटा) की भारतीय शाखा ने शुक्रवार को बताया कि उसने इस बाजार की दो बंद दुकानों में पक्षियों को छिपाकर रखे जाने की शिकायत की जिसके बाद एलेक्ज़ेंड्रिन तोते, फिंच और अन्य प्रजातियां समेत हजारों पंछियों को आजाद कराया गया। उसने पूर्व पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व सांसद मेनका गांधी के दखल की भी मांग की। पेटा की शिकायत पर जामा मस्जिद थाने और वन विभाग के संयुक्त दल ने दुकानों पर छापा मारा और इन पक्षियों को बरामद किया। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की पुष्टि की और कहा कि कथित अपराधियों के खिलाफ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। पेटा इंडिया ने कहा कि मुक्त कराए गए पंछियों को स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं अस्थाई पुनर्वास के लिए भेजा गया है। उसने कहा कि पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। एलेक्ज़ेंड्रिन तोते वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत संरक्षित जीव हैं। इन प्रजातियों के पक्षियों की खरीद-बिक्री और उन्हें रखना अपराध है जिसके लिए एक लाख रुपए तक जुर्माना या तीन साल तक की कैद हो सकती है।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले एमबीबीएस छात्र को मिलेंगे 25.55 लाख

● उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने दी मंजूरी, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले अक्षित व अक्षिता से मुलाकात भी की

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केजरीवाल सरकार से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले एमबीबीएस छात्र अक्षित शर्मा को 25.55 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसे मंजूरी दी। साथ ही छात्र अक्षित और अक्षिता से मुलाकालत भी की है। दोनों को साल 2017 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला था और पिछले सालों में भी केजरीवाल सरकार अपने स्कीम के तहत इन दोनों छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देती आई है।

इस मौके पर आतिशी ने कहा कि, उनकी सरकार देश-समाज के लिए बहादुरी दिखाने वाले बच्चों के साथ खड़ी है। इन बच्चों की बहादुरी पूरे देश के लिए मिसाल है। केजरीवाल सरकार अपने स्कीम के तहत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले दिल्ली निवासी छात्रों को उनके उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले छात्रों को जो देश के किसी उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे है, उन्हें उनके कोर्स का शत प्रतिशत ट्यूशन फीस अनुदान में मिलता है ताकि वो बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सके। साथ ही इन छात्रों को सालाना स्टेशनरी के लिए 5000 रुपये भी मिलते है। साथ ही इस स्कीम में उन छात्रों को एक स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस के तहत प्रतिमाह 2500 दिए जाते है, जिनके पेरेंट्स की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।

केजरीवाल सरकार के दिल्ली हायर एजुकेशन एड ट्रस्ट के तहत छात्रों को ये अनुदान दिया जाता है। इसी के अंतर्गत दिल्ली निवासी अक्षित शर्मा, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था।

उन्हें एमबीबीएस की फीस और स्टेशनरी के लिए 25.55 लाख रुपये का अनुदान देने को मंजूरी मिली है। साथ ही हाल ही में एलएलएम पूरा करने वाली उनकी बहन अक्षिता शर्मा को भी केजरीवाल सरकार ने ट्यूशन फीसद के लिए पिछले सालों में अनुदान देते आई है।

विश्व धरोहर समिति के समक्ष पेश किया देश की अनूठी विरासत

रंग बिरंगी रोशनी से नहाए पुराना किला के परिसर में, भारत की उस विरासत को दिखाया गया, जो किसी भी क्षेत्र, धर्म और भाषा से परे है

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। समिति के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के भारत की विविध और अनूठी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश किया। इस सांस्कृतिक उत्सव का मुख्य आकर्षण, भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्यों का अनूठा मिश्रण था, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश भर से आए लगभग 100 कलाकारों ने एक ही मंच पर, देश के विभिन्न नृत्योंको सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें ओडिशा का ओडिसी, गुजरात का गरबा, मणिपुर का मणिपुरी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, जम्मू-कश्मीर का रउफ, राजस्थान का

घूमर, असम का बिहू और पंजाब का भांगड़ा नृत्य शामिल था। इस प्रस्तुति को मशहूर कलाकार मैत्रेयी पहाड़ी ने कोरियोग्राफ किया था। रंग बिरंगी रोशनी से नहाए पुराना किला के परिसर में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारत की उस विरासत को दिखाया गया, जो किसी भी क्षेत्र, धर्म और भाषा से परे है, और जो देश की राष्ट्रीय राजधानी की एक समृद्ध विरासत को भी प्रदर्शित करता है। इस मौके पर मौजूद विदेशी प्रतिनिधियों और अन्य अतिथियों ने कलाकारों के सांस्कृतिक प्रदर्शन और दिल्ली की समृद्ध विरासत की जमकर सराहना की। गौरतलब है कि दिल्ली में पहली बार विश्व विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

इस अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास भी, विरासत भी के दृष्टिकोण के अनुरूप, दिल्ली में विरासत स्थलों और स्मारकों को संरक्षित और इनका जीर्णोद्धार करने की लगातार कोशिश की जा रही है, ताकि दिल्ली को सही मायने में एक ग्लोबल हेरिटेज सिटी के रूप में स्थापित किया जा सके। दिल्ली की मूर्त और अमूर्त विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इससे देशी और विदेशी पर्यटकों का इनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और उन्हें भारत की सांझी विरासत को जानने और अपनी जानकारी को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर लोग इसके लिए आगे आएं और इन्हें संरक्षित करने में सहभागी बनें।

भारत की विविध और अनूठी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगी, भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने अपने संबोधन में देश की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि भारत सदियों से सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में स्थापित रहा है। इस अवसर पर कई देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, 160 से अधिक देशों के लगभग 250 प्रतिनिधि, यूनेस्को के वरिष्ठ अधिकारी समेत केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

कारगिल युद्ध में शहीद होकर अमर हो गए बिजेंद्र

गुरुग्राम के इस जांबाज ने दुश्मन के छक्के छुड़ाकर मात्र 17 साल, 9 माह की उम्र में शहादत को लगाया था गले

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

युद्ध में चोटी नंबर-5685 को पाकिस्तान के सैनिकों से मुक्त कराने के बाद तिरंगा लहराते सैनिकों में शामिल बिजेंद्र कुमार।

वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध की विजयगाथा को शुक्रवार को देश ने याद किया। इस विजय गाथा के लिए हमारे जांबाज सैनिकों ने बलिदान दिया। उनके बलिदान को देश नमन कर रहा है। इन बलिदानी जांबाजों में शामिल रहे गुरुग्राम के बिजेंद्र कुमार, जो मात्र 17 साल 9 महीने की उम्र में देश पर बलिदान हो गए। कारगिल विजय दिवस पर गुरुग्राम ने बिजेंद्र कुमार को नमन किया।

गुरुग्राम के गांव दौलताबाद कूणी के रहने वाले बिजेंद्र कुमार की जांबाजी के किस्से गांव व आसपास के क्षेत्रों में लोगों से सुने जा सकते हैं। बचपन से ही सेना में जाकर देश सेवा करने का जज्बा बिजेंद्र में था। इसलिए वह हमेशा सेना में भर्ती होने की तैयारी करते रहते थे। आखिरकार उन्होंने सेना में भर्ती होकर ही दम लिया। दुश्मन का खात्मा करने की सोच रखने वाले बिजेंद्र कुमार को 13 कुमाऊं रेजीमेंट में प्रशिक्षण मिला। इसके के बाद तुरंत वर्ष 1999 में भारत-पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग छिड़ गई। उन्हें कारगिल युद्ध में भेजा गया। हजारों फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर दुश्मन से जंग लडऩा आसान नहीं था। क्योंकि दुश्मन ऊंचाई से वार कर रहा था तो हमारे सैनिक नीचे से जवाब दे रहे थे। जिस मई-जून के महीने हम यहां गर्मी से त्रस्त होते हैं, उस समय में कारगिल में भयंकर बर्फ गिरती है। ऐसे में सैनिकों को ठंड से भी एक तरह से युद्ध ही करना था। पाकिस्तानियों से युद्ध करते हुए बिजेंद्र कुमार ने अकेले ही चार दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था।

देश सेवा के लिए शादी का प्रस्ताव भी ठुकराया: बिजेंद्र कुमार सेना में अपना प्रशिक्षण पूरा करके 28 दिन के लिए गांव आए थे। सरकारी नौकरी लग जाने पर घर-परिवार में बिजेंद्र कुमार के लिए रिश्ते भी आने लगे। इस दौरान परिवार ने बिजेंद्र के समक्ष शादी करने का प्रस्ताव रखा। इस पर बिजेंद्र कुमार ने परिजनों से साफ कह दिया था कि वे देश सेवा करना चाहते हैं। अभी वे शादी नहीं करेंगे।

कारगिल विजय दिवस पर परिवार हुआ भावुक: कारगिल विजय दिवस पर बिजेंद्र के जीवन का संघर्ष और उनकी बातें परिवार ने साझा कीं। उनके भाई राजेंद्र कुमार कहते हैं कि अपने भाई पर उन्हें गर्व है। समाज में बिजेंद्र कुमार के नाम से उनके परिवार को जो सम्मान मिलता है, वह गौरवान्वित करता है। राजेंद्र कुमार ने कहा कि बिजेंद्र में बचपन से ही देश के प्रति जो भावना थी, वह उसी भावना से आगे बढ़ते गए। सेना में भर्ती होकर उसे जीवन की सारी खुशियां मिल गई थीं। हमेशा देश के लिए ही कुछ करने की बातें किया करते थे। परिवार शादी करना चाहता था, लेकिन वे देश सेवा की जिद पर अड़े थे। शहादत के बाद ऐसा लगता है कि वे देश के लिए ही आए थे।

ऑपरेशन में सबसे आगे रहे बिजेंद्र कुमार

कारगिल में सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर ऑपरेशन मेघदूत व ऑपरेशन विजय में बिजेंद्र कुमार अग्रिम पंक्ति में शामिल रहे। बिजेंद्र कुमार ने अपनी बटालियन के साथ चोटी नंबर-5685 को पाकिस्तान के सैनिकों से मुक्त कराने के लिए हमला कर दिया। वहां दुश्मनों को मारकर चोटी पर तिरंगा फहराया। इस जश्न के बीच पहाड़ी पर छिपे बैठे पाकिस्तानियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में बिजेंद्र कुमार भारत माता पर कुर्बान हो गए। बिजेंद्र के सीने में गोली लगी थी। अपनी कुर्बानी से पहले उन्होंने चार पाकिस्तानियों को मौत दी थी। बिजेंद्र कुमार कारगिल के युद्ध में सभी शहीदों में सबसे कम उम्र के थे।

शंटिंग कराते समय ट्रेन की चपेट में आने से स्टेशन मास्टर की मौत

● न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

संजय राघव का फाइल फोटो।

न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पर शंटिंग कराते वक्त स्टेशन मास्टर संजय राघव रेलवे लाइन पर पड़े पत्थर से पैर फिसलने से ट्रेन की चपेट में आ गए, इससे उनकी मौत हो गई। जीआरपी ने शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले संजय राघव एनआईटी-पांच जे ब्लॉक में रहते थे। वह 20 साल से दिल्ली-फरीदाबाद सेक्शन में कार्यरत थे। करीब पांच साल से न्यू टाउन रेलवे स्टेशन मास्टर थे। गुरुवार की दोपहर करीब दो बजे वह न्यू टाउन स्टेशन पर मालगाड़ी की शंटिंग करा रहे थे। उनके साथ पाइंट मेन उमेश कुमार और धर्म सिंह भी थे, जोकि कुछ दूरी पर थे। स्टेशन मास्टर संजय राघव मालगाड़ी के बीचोंबीच थे, जो की मालगाड़ी को आगे-पीछे करा रहे थे। पुलिस के मुताबिक उसी वक्त पत्थर से पैर फिसलने के कारण वह ट्रेन की ओर गिरे। इससे की उनका दाएं हाथ कट गया और गर्दन में भी गंभीर चोट आई। दोनों पाइंटमेन ने उन्हें गिरते हुए देखा और वह दौड़ कर मौके पर पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो गई। इसके बाद जीआरपी थाना इंचार्ज राजपाल, संजय कुमार, सुभाष व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन मास्टर अखिलेश समेत अन्य रेलवे अधिकारियों ने संजय राघव की मौत पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि संजय राघव रेलवे के हरेक कार्य को अपना समझते हुए करते थे।

कारगिल दिवस पर निकाली मशाल यात्रा

● शहीद परिवारों व पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम में कारगिल दिवस पर यात्रा निकालते भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य।

कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष मयंक निर्मल के नेतृत्व में मशाल यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा लघु सचिवालय पार्किंग से शुरू होकर स्वंत्रता सेनानी भवन पर संपन्न हुई।

यात्रा में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, समाज के गणमान्य लोग और महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि कारगिल दिवस भारत के स्वाभिमान और गर्व का दिवस है। कमल यादव ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है कि जिन्होंने देश की सुरक्षा और रक्षा की। शहीदों के बलिदान और साहस के एक अद्वितीय युद्ध का नया इतिहास बना है। उन्होंने कहा कि शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रमों से हमारी पीढ़ी को शहीदों के शौर्य और उनकी वीरता से प्रेरणा मिलती है।

प्रवासी मंडल कार्यशाला में विधायक ने दिए जीत के मंत्र

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

प्रवासी मंडल कार्यशाला बल्लभगढ़ का आयोजन सेक्टर दो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि बल्लभगढ़ प्रवास के प्रभारी राजेश नागर विधायक तिगांव पहुंचे। उन्होंने शक्ति केंद्र प्रमुखों को भाजपा की जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में ही केवल कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है।

नागर ने कहा कि यही एक पार्टी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। भाजपा में विचार ही सिद्धांत हैं। हमारे लिए पूर्व में नेतृत्व प्रदान करके गए व्यक्तियों के विचार मार्गदर्शन करते हैं। भाजपा में सभी लोग एक परिवार के रूप में काम करते हैं। उन्होंने सभी से कहा कि अब विधानसभा चुनाव में समय नहीं रह गया है। सब मिलकर उसी तरह तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की दिशा में कार्य करें जैसे देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। नागर ने मंडल अध्यक्षों से आगामी चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी की जानकारी ली।

क्राइम ब्रांच का अफसर बता कर की 20 लाख की ठगी

● फेडेक्स पार्सल में अवैध सामग्री व मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता का दिखाया था डर

● शिकायत मिलने पर पुलिस ने फ्रिज कराई राशि

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

क्राइम ब्रांच का फर्जी अधिकारी बनकर एक साइबर ठग ने 20.50 लाख रुपये की ठगी कर ली। इससे पहले कि वह उस राशि को बैंक खाते से निकाल पाता, पुलिस ने उसके कृत्य का भंडाफोड़ करते हुए राशि को फ्रीज करवा दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इसके लिए कई टीमों का गठन किया है।

साइबर क्राइम थाना को एक शिकायत में पीड़ित ने कहा कि उसके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि वह फेडेक्स की मुंबई ब्रांच से बोल रहा है। आपके नाम पर एक पार्सल है जिसमें अवैध सामान है। उसके बाद कॉल मुम्बई पुलिस में कॉल ट्रांसफर कर दी।

पहले तो उससे फोन पर बात की। फिर स्काईप के माध्यम से वीडियो कॉल करके कहा कि उसका आधार कार्ड आईडी की कई मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि के केसों में संलिप्तता है। इस तरह से उसे मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया। इन्वेस्टिगेशन के लिए सिक्योरिटी के नाम पर उसके बैंक खाते से लगभग 20 लाख 50 हजार रुपए धोखे से ट्रांसफर करवा लिए। इस शिकायत पर थाना साइबर क्राइम में मामला दर्ज कर लिया गया। साइबर क्राइम अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस टीम ने शिकायतकर्ता से ट्रांसफर कराई गई राशि को फ्रिज करवा दिया, ताकि साइबर ठग उस राशि को निकाल ना लें। साइबर क्राइम पुलिस राशि फ्रिज करने के बाद आरोपी के खिलाफ सभी सबूत एकत्रित करके उसकी तलाश कर रही है।

सड़क पर भरे पानी में कुर्सी डालकर बैठे दुकानदार, जताया विरोध

गुरुग्राम। जिला के गांव बिलासपुर में सड़क पर भरे गहरे पानी की निकासी नहीं होने से गुस्साए दुकानदारों ने पानी में कुर्सियां डालकर धरना दे दिया। इस दौरान पटौदी से तावडू जाने वाला यातायात बाधित हो गया। जाम की सूचना पाकर एसडीएम दर्शन यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों को समझाया, तब जाकर उन्होंने जाम खोला। सड़क पर भरे बरसात के पानी में कुर्सियां डालकर धरना दे रहे दुकानदारों ने कहा कि बरसात जब आती है तो बिलासपुर गांव की सड़क पर कई फुट पानी भर जाता है। इस दौरान यहां से निकलना दुभर हो जाता है। वाहनों के आने-जाने से यहां स्थिति और खराब हो जाती है। दुकानों में गंदा पानी भर जाता है। दुकानदारों का कहना था कि कई बार प्रशासन को इसके समाधान करने के बारे में कहा गया है। प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई वर्षों से वे इस समस्या को झेल रहे हैं। हल्की बारिश में भी रोड पानी से लबालब भर जाता है। इस पानी की कोई निकासी न होने की वजह से लोगों का निकलना दुभर हो जाता है।

संक्षिप्त समाचार

भंडारे में प्रसाद वितरित करती निवर्तमान पार्षद शीतल बागड़ी।

शीतल बागड़ी ने आयोजित किया विशाल भंडारा

गुरुग्राम। नगर निगम वार्ड 10, नया घोषित वार्ड 33 की निवर्तमान पार्षद शीतल बागड़ी ने साल भर में सभी ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने का संकल्प पूरा किया है। अंतिम चरण में महाराष्ट्र के पांच ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन करके लौटने पर शीतल बागड़ी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद मंगत राम बागड़ी, ललित बागड़ी और शीतल बागड़ी ने लोगों को प्रसाद वितरित किया। शीतल बागड़ी ने कहा कि हमने सुख और शांति के लिए इस महान धार्मिक अनुष्ठान को पूरा किया है। भगवान शंकर की यह आराधना ईश्वर के ही आशीर्वाद से पूरी हो सकी है। शीतल बागड़ी ने बताया कि भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, जिनमें से पांच महाराष्ट्र में हैं। अंतिम चरण में पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित औंधा नागनाथ ज्योतिर्लिंग और महाराष्ट्र स्थित परली वैजनाथ मंदिर में दर्शन कर परिवार और वार्ड की जनता की सुख शांति की कामना की। शीतल बागड़ी ने बताया कि सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर के दर्शन किए।

शहीद सिंह पार्क में चलाया पौधरोपण अभियान

फरीदाबाद। एक पेड़ मां के नाम के तहत गांव जाजरू इंडस्ट्रियल एरिया शहीद सिंह पार्क में लघु उद्योग भारती बल्लभगढ़ इकाई , जिला लघु उद्योग भारती और भारत विकास परिषद् के सहयोग से एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राकेश त्यागी सह प्रान्त कार्यवाह, हरियाणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मनोज रूंगटा हरियाणा प्रान्त महासचिव और योगेश कुमार बंसल डायरेक्टर -जीएमटी इंडस्ट्रीज लिमिटिड उपस्थित रहे। इस अवसर पर अरुण बजाज राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य, लघु उद्योग भारती एवं हरियाणा सह प्रभारी, लघु उद्योग भारती बल्लभगढ़ इकाई के प्रेसिडेंट अशोक चौधरी ,महासचिव श्रीकांत दमानी, गुलशन सिंघल लूब उपाध्यक्ष बल्लभगढ़, कोषाध्यक्ष मनोज बंसल,जिला लघु उद्योग भारती फरीदाबाद से महासचिव अमृतपाल सिंह कोचर, गाँव जाजरू से मुख्य रूप से हरीराम डागर सहित सभी का पहुंचने पर लघु उद्योग भारती बल्लभगढ़ इकाई ने स्वागत किया। राकेश त्यागी सह प्रान्त कार्यवाह, हरियाणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और योगेश कुमार बंसल डायरेक्टर -जीएमटी इंडस्ट्रीज लिमिटिड का शॉल ओढ़ाकर व प्लांटर देकर सम्मानित किया गया।

कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया नमन

फरीदाबाद। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहीद स्मारक सेक्टर-12 समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने फूल अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके शौर्य वीरता व अदम्य साहस को सराहा कर शत शत नमन किया। कारगिल विजय दिवस समारोह में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने भी शिरकत की। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने कहा कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये सब इन शहीद सैनिकों की वजह से ले रहे है।

दो दिन तक 5 घंटे बाधित रहेगी बिजली की सप्लाई

गुरुग्राम। शनिवार एवं रविवार 27-28 जुलाई को एचवीपीएन द्वारा 220 केवी पचंगाव पावर हाउस के पीछे पचंगाव से फर्रूखनगर की नई टावर लाईन का कार्य किया जाना है। जिसके कारण 33 केवी पचंगाव पावर हाउस से चलने वाले सभी 11 केवी फीडर की सप्लाई सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बन्द रहेगी। 33 केवी पचंगाव पावर हाउस से बिजली आपूर्ति वाले गांव कुकडोला, फाजलवास, ग्वालियर, खेडकी बाघनकी, चादंला डुगंरवास, पुखरपुर, मोकलवास, राजा की ढाणी व इस एरिया की अन्य ढाणियों में बिजली बाधित रहेगी।

सीकरी के प्रयास से हटाए गए अस्थायी डिवाइडर

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

एडवाइजरी कौंसिल की बैठक में मौजूद जीएमडीए के अधिकारी एवं सदस्यगण।

जीएमडीए की रेजिडेंट एडवाइजरी कौंसिल की बैठक में सदस्य बोधराज सीकरी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक में चर्चा की। अधिकतर समस्याओं पर जीएमडीए से तुरंत कार्य करने का आश्वासन उन्हें मिला।

उन्होंने कहा कि भूतेश्वर मंदिर के पीछे खांडसा रोड पर अस्थायी डिवाइडर लगे हैं। उन्हें हटाया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों ने उनसे मुलाकात करके मांग की है। बैठक के तुरंत बाद बोधराज सीकरी डीसीपी (ट्रैफिक) वीरेंद्र विज के साथ मौके पर पहुंचे। मुआयना करने के बाद डिवाइडर के एक हिस्से को तुरंत हटाने के आदेश दिये गए।

इसी प्रकार सुशांत लोक वासियों ने पार्किंग की समस्या, व्यापार केंद्र पर ट्रैफिक की समस्या, पारस हॉस्पिटल के पास साइड लेन स्प्लिट रोड बनाने और पीने के पानी में मिट्टी के आने की समस्या पर भी चर्चा की।

टीआरपी स्टाफ ने पंकज डावर के नेतृत्व में डीसी को सौंपा ज्ञापन

डीसी निशांत कुमार यादव को मांग पत्र सौंपते पंकज डावर व स्टाफ सदस्य।

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम विश्वविद्यालय के शिक्षण संसाधन व्यक्तियों (टीआरपी) ने अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर के नेतृत्व में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डा. रूपसी, डा. सोमवीर, डा. मनी तनेजा, डा. चेतन जैन, डा. ममता, सिमरन, गरिमा, डा. गुरप्रीत कौर, प्रियंका, श्वेता, सुजाता, इशा, प्रतिभा, पर्ल चौधरी, निशित कटारिया मौजूद रहे।

ज्ञापन में कहा गया है कि गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018 में यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार हमें शिक्षण संसाधन व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया था। वेतनमान में गैर पीएचडी धारकों के लिए 30,000 रुपये और पीएचडी धारकों के लिए 35,000 रुपये तक ही उन्हें सीमित कर दिया गया है। उनका कार्यभार यूजीसी के मापदंडों से अधिक है। फार्मेसी विभाग में उनके नाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल पर स्थायी कर्मचारियों के रूप में शामिल किए गए हैं, जोकि गलत हैं। वर्ष 2019 के समान काम के लिए समान वेतन के सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें सहायक प्रोफेसर के समान मुआवजा, चिकित्सा या मातृत्व अवकाश भी नहीं दिया जा रहा। यदि कोई भी अवकाश लेते हैं तो वेतन काट लिया जाता है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दिसम्बर 2021 में पदभार संभालने वाले गुरुग्राम विवि के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार से कई बार अनुरोध किया गया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अफसरों ने किया कौशल विवि का भ्रमण

पलवल। इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारियों ने शुक्रवार को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने कौशल विकास के लिए उच्च शिक्षा के मॉडल का अध्ययन किया।

आईटीएस अधिकारियों ने इनोवेटिव स्किल स्कूल और विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी अवलोकन किया। हरियाणा इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तत्वावधान में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तक्षशिला भवन में इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारियों का स्वागत किया गया। अधिकारियों के दल के साथ कुलसचिव प्रोफेसर ज्योति राणा और अकादमिक अधिष्ठाता प्रोफेसर आर एस राठौड़ ने भी विविध आयामों पर मंत्रणा की।

ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ी रिदम को सीएम ने बधाई संदेश भेजा

पायनीयर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिला कार्यकारी खेल अधिकारी ने बताया कि जिला फरीदाबाद से रिदम सांगवान का पेरिस में आयोजित हो रहे ओलिंपिक गेम्स-2024 में शूटिंग इवेंट मे चयन हुआ है। आशा ने बताया कि मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह द्वारा जिला खेल विभाग को रिदम सांगवान को प्रोत्साहित करने एवं उत्कृष्ट संदेश देने के लिए खिलाड़ी को बधाई संदेश भेजा गया तथा साथ मे वीटा कंपनी का 5 किलो शुद्ध देसी घी देने के आदेश दिये गये। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के आदेशानुसार तथा उनकी ओर से दिया गया बधाई संदेश देने के लिए कार्यकारी जिला खेल अधिकारी फरीदाबाद आशा, हॉकी प्रशिक्षक निरेश, फुटबॉल प्रशिक्षक कुलदीप सिंह तथा कार्यालय उपाधीक्षक चेतन गांधी रिदम सांगवान के निवास स्थान पर पहुंचे। रिदम सांगवान के ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए पेरिस (फ्रांस) गये होने के कारण मुख्यमंत्री, का बधाई संदेश व घी उनके पिताजी नरेंद्र सांगवान तथा माताजी नीलम सांगवान को दिया गया।

राशन डिपो के लिए 8 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

● शैक्षणिक योग्यता 12वीं, 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए आवेदक की आयु

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

हरियाणा में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इच्छुक व्यक्ति लाइसेंस के लिए 8 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।

डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में कुल 121 राशन डिपो अलॉट किए जाने है जिनमें से 62 राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 59 राशन डिपो के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है तथा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होने के साथ-साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, आवेदन कर सकता है। डिपो अलॉट करने में तेजाब हमले से पीड़ित महिला व विधवा महिला को वरियता प्रदान की जायेगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 150 वर्ग फुट होना अनिवार्य है।

कोमा में जा चुके मरीज को मौत के मुंह से निकाल लाए डॉक्टर

● दो महीने तक कोमा में, चार महीने आईसीयू में रहा मरीज

● मल्टीपल ब्रेन स्ट्रोक, दौरे पड़ने व रक्तस्राव से भी जूझ रहा था कारोबारी

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

फोर्टिस अस्पताल में मरीज के ठीक होने के बाद उसके साथ डॉक्टर्स व स्टाफ की टीम।

गुरुग्राम के डॉक्टर्स ने एक ऐसे मरीज को जीवनदान दिया है, जो दो महीने तक कोमा में रहा। जिसके जीने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। रक्तस्राव, दौरे पड़ने व मल्टीपल ब्रेन स्ट्रोक उसे आ चुके थे। दो महीने तक कोमा में व 4 महीने तक आईसीयू में वेंटिलेटर पर होने के बाद भी डॉक्टर्स ने उपचार में इतनी मेहनत की कि उसके प्राण वापस ले आए।

मरीज अचानक ही बेहोश हो गया था। उसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर चक्कर आने, बेहोश होने व शरीर में अन्य विकास आने से कोमा में चला गया। सेहत में सुधार न होने पर उन्हें फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जिस स्थिति में मरीज को अस्पताल लाया गया था, उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उसका जीवन बच पाएगा। अपने आखिरी प्रयास तक डॉक्टर्स मरीज का जीवन बचाने की जद्दोजहद करते रहे। डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। कई बार दौरा पड़ने तथा दिमाग में सूजन के लिए उनका उपचार किया गया। उन्हें दवाएं व न्यूरोरीहैबिलेटेशन फीजियोथेरेपी दी गई, ताकि कोमा में रहते हुए शरीर और दिमाग की सेहत में सुधार से मदद मिलती रहे। ऐसे मरीजों का जीवन बचने की दर मात्र 1-5 फीसदी होती है। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में न्यूरोलॉजी विभाग में प्रिंसिपल डायरेक्टर डा. प्रवीण गुप्ता, डा. संदीप दीवान, क्रिटिकल केयर के निदेशक एवं एचओडी डा. संदीप दीवान के नेतृत्व में टीम ने मरीज का बेहतर उपचार किया।

मरने के कगार पर पहुंचे मरीज को जिंदा किया: डा. प्रवीण: डा. प्रवीण गुप्ता के अनुसार दो महीनों बाद मरीज कोमा से बाहर आ गए और उनका वेंटिलेटर हटा दिया गया। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। टीम द्वारा निरंतर दवाओं, फीजियोथेरेपी के माध्यम से अन्य बीमारियों का ठीक तरह से उपचार किया गया। डा. गुप्ता ने बताया कि मरीज के दिमाग की आर्टरियों में ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से उन्हें कई बार स्ट्रोक हुआ। कई बार सीजर हुआ और कई बार ब्रेन हैमरेज हुआ था।

हरियाणा में और गहराया स्वास्थ्य संकट

डाक्टरों के बाद एनएचएम कर्मचारियों ने भी काम रोका, दूसरे दिन भी जारी रही हड़ताल

● तीन हजार डाक्टर व 13 हजार एनएचएम कर्मचारी हड़ताल बुरी तरह से चरमराई सेवाएं

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में जहां लगातार दूसरे दिन डाक्टरों की हड़ताल जारी रही वहीं शुक्रवार से प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करने वाले कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। जिस कारण प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। गुरुवार को देररात तक बैठकों में डाक्टरों की मांगों का कोई समाधान नहीं निकलने पर शुक्रवार को सरकार भी इस मामले में शांत होकर बैठ गई।

निजी लैब में निशुल्क होगी जांच

हरियाणा सरकार ने मरीजों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सामान्य टेस्ट निजी लैब से करवाने पर सरकार द्वारा भुगतान का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार मरीजों के इलाज हेतु जरूरी खून, पेशाब ,एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने सभी सिविल सर्जन को सरकारी अस्पतालों में जांच उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, मरीजों की जांच निजी प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउंड व एक्स-रे केंद्र से निशुल्क करवाने के आदेश दिए हैं। जांच में आने वाला खर्च स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

करीब 3000 डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को इलाज जैसी महत्वपूर्ण सुविधा नहीं मिल रही है, वहीं एनएचएम के 13000 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शेष कामकाज भी प्रभावित हो गया है। अभी तक सरकार की तरफ से हड़ताल को खुलवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। जिसके चलते हालात बद से बदत्तर होते जा रहे हैं। गुरुवार को देररात तक डाक्टरों की विभाग के एसीएस के साथ भी बैठक हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

इस बीच शुक्रवार को एनएचएम कर्मचारियों ने भी बिगुल फूंक दिया है। एनएचएम के प्रदेश महासचिव हरि राज ने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल चार दिन तक जारी रहेगी। अगर इस बीच मांगों का सही और स्टीक हल नहीं निकला तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा।

हरिराज ने बताया कि पिछले कुछ लंबे समय से एनएचएम कर्मचारी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जिसे लेकर मुख्यमंत्री के करनाल आवास का घेराव भी कर चुके हैं। जिसके बाद उनकी मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से बातचीत हुई। जिन्होंने मांगों को लेकर ड्राफ्ट तैयार करने बारे बोला था। मगर इसी बीच एसीएस सुधीर राजपाल से बातचीत हुई। जिन्होंने 25 जुलाई को मांगों पर बातचीत के लिए एमडी एनएचएम से मिलने की बात कही थी। मगर वहां भी मांगों का हल नहीं निकला। जिसके चलते सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं।

ओलंपिक जाने वाले 115 खिलाड़ियों में से 25 हरियाणा के, सीएम ने दी बधाई

चंडीगढ़। विश्व में खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक 2024 खेलों की शुरुआत शुक्रवार से पेरिस में हो चुका है, जिसमें कुल 115 खिलाड़ी भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन 115 खिलाड़ियों में से 25 खिलाड़ी केवल हरियाणा से हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश व देश के अन्य खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कामना की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करेंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2 प्रतिशत जनसंख्या वाले हरियाणा से 22 प्रतिशत खिलाड़ियों का चयन पूरे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और यहां के लोग इस बात को समझते हैं कि इस स्तर की प्रतियोगिता तक पहुंचने के लिए किस तरह की लगन, मेहनत और दृढ़ता की जरूरत होती है। हम ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों की तैयारी करते समय खिलाड़ियों के सामने आने वाली शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से वाकिफ हैं।

भाजपाई दिग्गजों ने बनाई चुनावी रणनीति

● धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बैठक, सीएम व प्रदेशाध्यक्ष भी पहुंचे

● सतीश पूनिया सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

शिखा शर्मा। चंडीगढ़

भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में परिक्रमा भी बढ़ गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री व हरियाणा में विधानसभा चुनावों के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश के संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली में हुई इस बैठक में हरियाणा मामलों के प्रभारी डॉ सतीश पूनिया, सह-प्रभारी सुरेंद्र नागर, विधानसभा चुनाव के सह-प्रभारी बिप्लब कुमार देव, करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी व संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री को चुनावों को लेकर की गई तैयारियों के बारे में बताया। साथ ही, दोनों नेताओं ने फीडबैक के लिए तय किए गए कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट दी। मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष ने जिलों में प्रवास का फैसला लिया है।

दोनों नेताओं ने अलग-अलग प्रदेश के सभी नब्बे हलकों को कवर करने का फैसला लिया है। मोहनलाल बड़ौली 28 जुलाई से हरियाणा के जिलों का दौरा शुरू करेंगे। वहीं 2 अगस्त से सीएम नायब सैनी का जिला प्रवास कार्यक्रम शुरू होगा। हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का भी हरियाणा आने का कार्यक्रम है। वे पहले पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी चुनावी रणनीति को लेकर वे मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी तीन दिन दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान उनकी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित और भी कई केंद्रीय व संघ नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने चुनावी तैयारियों के साथ-साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रदेश स्तर के अलावा केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर भी प्रदेश में विधानसभा की सभी नब्बे सीटों के लिए सर्वे करवाया जा रहा है।

हरियाणा की बड़ी परियोजनाओं को केंद्र ने नहीं दिया बजट: दुष्यंत

● पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, किसान सम्मान निधि का बजट घटाने से दो करोड़ किसान योजना से हुए वंचित

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश तक सीमित रहा, जबकि सरकार की मंजूरी के बावजूद हरियाणा की बड़ी परियोजनाओं को बजट में जगह नहीं मिली। दुष्यंत शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रशासनिक मंजूरी वाले हरियाणा के 3500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित प्रोजेक्ट हिसार-रेवाड़ी हाईवे को केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया लेकिन 10 दिनों में 11 पुल गिरने वाले राज्य बिहार में 36 हजार करोड़ रुपए का विशेष बजट केवल सड़कों के विकास के लिए दे दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के रेल परियोजनाओं के बजट में भी केंद्र सरकार ने हरियाणा की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि झज्जर-फर्रुखनगर रेल का विस्तार, कैथल-बहादुरगढ़ में रेल लाइन को एलिवेटेड बनाने और स्टेशन के पुनर्निर्माण के मंजूर प्रोजेक्ट को भी केंद्र ने अपने बजट में जगह नहीं दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने की बात करने वाली भाजपा ने किसानों के बजट को भी कम करने का काम किया है।

PUBLIC NOTICE

It is informed to the public that **M/s Annapurna Melters and Founders (P) Ltd. through its Director** is the lessee/ owner and in possession of Industrial Plot No.C-118, Site-1, B.S. Road, Ghaziabad admeasuring 5754 sq. yards. **M/s Annapurna Melters and Founders (P) Ltd. through its Director** has lost/ misplaccd the Original Allotment Letter, Possession Letter AND Original Lease Deed executed by UPSIDC in favour of M/s Annapurna Melters and Founders (P) Ltd. vide entry in Bahi No.1 Zild 5274 pages 47/78 Serial no.2386 dated 29.03.2003 of the aforesaid property. M/s Annapurna Melters and Founders (P) Ltd. through its Director has intimated P.S. Kavi Nagar vide intimation dated 09.01.2018. Anybody (Banking/ Financial Institutions/ Individuals) having any kind of interest/ claim/ title/ objection on the basis of said Original Allotment Letter, Possession letter AND Original Lease Deed executed by UPSIDC in favour of M/s Annapurna Melters and Founders (P) Ltd. vide entry in Bahi No.1 Zild 5274 pages 47/78 Serial no.2386 dated 29.03.2003 may submit the same to the undersigned within 07 days of the publication. Please note carefully that if any objection is not received within the notice period, the said property will be treated as unencumbered, marketable and no claim will be accepted on the basis of the Original Allotment Letter, Possession letter AND Original Lease Deed executed by UPSIDC in favour of M/s Annapurna Melters and Founders (P) Ltd. vide entry in Bahi No.1 Zild 5274 pages 47/78 Serial no.2386 dated 29.03.2003.

VIVEK SEHGAL (Advocate)
II-F-04, Nehru Nagar, Ghaziabad. 9811144654

Public Notice

This is to inform the general public that **Mr. Jeevan Chandra** is the owner of Second floor without roof rights, area measuring 65.3 sq. yds., i.e., 54.559 sq. mtrs., built property no.272-273, out of Khasra no. 24/53, 25/53, situated in the Abadi of Harmander colony, Guru Ram Dass Nagar. Laxmi Nagar, in the area of village Khureji Khas, Illaqa Shahdara Delhi-110092. through Sale Deed dated 02.06.2015 doc. No. 2637 executed by Mr. Anil Gupta, Mr. Raj Kumar Gupta in favour of Mr. Jeevan Chandra in respect of said floor.

Mr. Jeevan Chandra intends to transfer the ownership by way of Sale Deed of aforementioned floor to **Mr. Dhiraj Kumar.** Subsequently, **Mr. Dhiraj Kumar** is in the process of mortgaging the said **Aditya Birla Housing Finance Limited**. Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 07-days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 07-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our client.

If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 07-days period by contacting **Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-44/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s): +910120-3101683, e-mail: accounts@lvnorth.in**

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client Izhar Ahmed is in process to purchase the property bearing no. C-100 admeasuring 55 sq. yds. i.e. 45.98 sq. mtr. out of khasra no. 711/684/442 Situated at Village Uldhanpur in the abadi of gali no. 7, Kanti Nagar Extn. Delhi-110051 (taking loan from Piramal Capital & Housing Finance Limited) from Mohd Danish Ansari, who acquired the same vide sale deed dated 24.07.2023 executed by Mr. Khushnoor Ali and Mr. Abdul Sattar (doc. No. 7318) All person/s having any claim against or in respect of the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgage (equitable/ registered or otherwise), gift, trust, inheritance, family arrangement, maintenance, bequest, partnership, possession, lease, sublease, tenancy, license, lien, charge, pledge, easement or otherwise howsoever, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 7 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned.

Kamal Kant Gupta (Advocate)
Unit No. FF-2, First floor, Mahaluxmi Metro Tower Sec-4, Vaishali, Gzb., U.P., Mob. 9810063351

PUBLIC NOTICE

I, Neeraj Kumar Singh S/o Shri Nawal Kishor Singh Old R/o Flat No.304, Top Floor-21 and 22, Madhu Vihar, Delhi-110092, and New Address is Flat No. G-2, Associated Apartments, Plot No.83, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092, hereby declare that my minor son name in the LIC of India Vide Policy no: 124157507, Branch Code-12-D, was mentioned as Naman Singh during his admission in School. I have changed the name from Naman Singh to Prathyush Singh. Hence forth both name Naman Singh and Prathyush Singh are same ward.

Public Notice

This is to inform the general public that **Mrs. Laxmi Devi Bhardwaj** is the owner of Plot of land area measuring 40 sq. yds., i.e., 33.44 sq. mtrs., out of Khasra no.257/2, situated at Gali no.5, Prkash Nagar, Khoda Pargana Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U.P. through Sale Deed dated 02.06.2023 as doc. No. 5642 executed by Mrs. Rama Devi in favour of Mrs. Laxmi Devi Bhardwaj in respect of said plot.

Mrs. Laxmi Devi Bhardwaj intends to transfer the ownership by way of Sale Deed of aforementioned Plot to **Mr. Umesh Kumar Singh & Mrs. Rekha Singh.** Subsequently, **Mr. Umesh Kumar Singh & Mrs. Rekha Singh** are in the process of mortgaging the said **SMFG India Home Finance Co. Ltd.** *(Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)* Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 07 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 07-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our client.

If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 07-day period by contacting **Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-44/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s): +910120-3101683; e-mail: accounts@lvnorth.in**

PUBLIC NOTICE

BE Known to all that my Client Mr. Prabhat S/o Nanak Chand R/o G-56, Rajeev Nagar Extension, Begumpur Nithari, North West Delhi, 110086., have severed all his relations with his son namely Mr. Rajesh, his wife Mrs. Suman & Grand children-Yuvraj, Devanshi. All residing at G-56, Rajeev Nagar Extension, Begumpur Nithari, North West Delhi, 110086.

henceforth my client hereby debar/disown them from all his movable and immovable properties. in future my client has no relation with son Mr. Rajesh his wife Mrs. Suman & Grand children - Yuvraj, Devanshi. Anyone dealing with them, shall be doing at his /her own Cost/risk and consequences and my client shall not be responsible for their acts and deals in any manner whatsoever.

Date: 27/07/2024, Place: New Delhi
S.K.SONI (ADVOCATE), En.No.D/3226/2017
Ch. No.371, Lawyer's Chamber Block
District Court Complex, Saket, ND-17

PUBLIC NOTICE

General Public at large is hereby informed that my client named SH. ANUPAM KUMAR PANDEY S/O-LATE SH. H. N. PANDEY, R/O- HOUSE NO. -A-15, GROUND FLOOR, DAYAL BAGH COLONY, TEHSIL & DISTRICT-FARIDABAD, HARYANA -121009, and also at HOUSE NO. F-1, P-56 SHRI RAM RESIDENCY, RANAWAT GUEST HOUSE, JHOTWARA, JAIPUR, RAJSTHAN is the legal owner & in possession of property bearing no. HOUSE NO. -A-15, GROUND FLOOR, DAYAL BAGH COLONY, TEHSIL & DISTRICT- FARIDABAD, HARYANA - 121009 by virtue of Family Settlement & inheritance through his father named Late Sh. Harinath Pandey. It has come to the knowledge of my client that one Lady named Smt. Sanyogita claiming to be the wife of Late Sh. H.N. Pandey, through her agents as well as personally, trying to sell the above-said property or create third party rights & interests. It is clarified through this notice that my client also has the possession of the above said property and is not interested to sell the said property. Further, a civil suit is already pending between the parties before Hon'ble Court. It is clarified that if any person deals with Smt. Sanyogita or her heirs, successors, agents, servants, assignees, administrators, executors etc. for selling, alienating, transferring and disposing of the said property and/or creating third party interest or making any WILL with respect to said property, he/she/they may do so at their own risk, costs and consequences and their acts shall be void & illegal. My client shall not be responsible to anybody for their acts and deeds. Further, despite this public notice, if any third party enters into any agreement, lease, license, sale or purchase, then my client shall be at liberty to take appropriate punitive legal actions against them. **K.K. JHA ADVOCATE CHAMBER NO. Y-2A, CIVIL WING TIS HAZARI COURT, DELHI-110054**

PUBLIC NOTICE

My client Mrs. Rama and Mr. Madhav Vasantrao Naik R/o 14 Godavari apts, Alaknanda, New Delhi -110019 have severed all relations from their son, Shree Madhav Naik and Daughter-in -law Shweta Shree Naik and have disowned and debarred them from my entire movable and immovable properties due to their incorrigible ways and irreconciliable differences. Anyone dealing with them will be doing so at own risk, My client has no responsibility.

Adv Hanmanth Pawar

PUBLIC NOTICE

I, Damini Munshi W/o Mr. Neeraj Kumar Singh R/o Flat No.-A-2/207, Phase-5, Aya Nagar, New Delhi-110047, hereby declare that my minor son name in the LIC of India Vide Policy No. 115306164 Branch Code-119, was mentioned as Nakshatra during the admission in School. I have changed the name from Nakshatra to Prathyush Singh Hence forth both name Nakshtra and Prathyush Singh are same ward.

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that Mr. Sri Pal Singh has acquired Plot No. 34-E/1, area measuring 30 sq. yrds., Khasra No. 21/4, situated in the area of Village Matiala Delhi, colony known as Nanhey Park, Delhi vide GPA along with ATS & Will dt. 09.09.1991 executed by Mr. Shiv Narain, Now Mr. Sri Pal Singh is the undisputed owner of above said property.

OR

Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

Ajay Kumar Giri (Advocate) H.No. 26/161, Basement, Vikram Vihar, Lajpat Nagar 4, New Delhi 110024.

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that Mr. Deepak Kumar Manchanda and Mrs. Sonia Manchanda has acquired House No. 383 E/12, area 66.5 sq. yrds., Khasra No. 800 Min, situated in the residential colony known as Krishna Colony, Gurgaon, Tehsil & Distt. Gurgaon, Haryana vide Sale Deed d.t 29.06.2015 executed by Mr. Rajesh Grover, Now Sale Deed dt. 28.07.2005 executed by Mrs. Rajni Gandhi in favour of Mr. Mohan Singh Duly Regd. as Doc No. 8815 is Lost in Original.

OR

Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

Ajay Kumar Giri (Advocate) H.No. 26/161, Basement, Vikram Vihar, Lajpat Nagar 4, New Delhi 110024.

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **निदा अंजुम और अल्ताफ इस्माइल सुरती उर्फ अल्ताफ सुरती** को **27.12.2023** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLDUB00247486** की राशि **रू.53,95,992.91 /- (रुपए तिरेपन लाख पंचानवे हजार नौ सौ बानवे और इकानवे पैसे मात्र)** और **19.12.2023** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **25.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.53,95,992.91 /- (रुपए तिरेपन लाख पंचानवे हजार नौ सौ बानवे और इकानवे पैसे मात्र) 19.12.2023** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड** (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था) के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.2104 जिसका सुपर एरिया 1585 स्के.फीट,इक्कीसवीं मंजिल पर, ब्लॉक -डी, ईको विलेज 3 से पहचाने जानेवाले प्रोजेक्ट में, प्लॉट नं.जीएच 06 पर स्थित, सेक्टर 16बी, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा -201303, उत्तर प्रदेश।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)

दिनांक :25.07.2024
स्थान :गौतम बुद्ध नगर

HDFC BANK We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरी मंजिल, एक्सपीरियो बिल्डिंग, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **एचडीएफसी बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार(रों) **1. मैसर्स राज ऑटो वर्ल्ड इसके प्रोपराईटर द्वारा श्री अजय कुमार (उधारकर्ता) 2. श्री अजय मिश्रा पुत्र श्री राज कुमार मिश्रा (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता) को** मांग सूचना दिनांक 01-05-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 62,39,941.00 (रु. बासठ लाख उनतालीस हजार नौ सौ इकतालीस मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार(रों) राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार(रों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **23.07.2024** को ले लिया है। कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **एचडीएफसी बैंक लि.**, के प्रभार वास्ते **रु. 62,39,941.00 (रु. बासठ लाख उनतालीस हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) और भविष्य का ब्याज साथ में खर्चे एवं प्रभार इत्यादि सहित वसूली घटाकर, यदि कोई हो,** के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति खसरा नं. 570 का भाग, क्षेत्रफल 50.16 वर्ग मी., जोकि बादशाह नगर, नगला बूढ़ी, मौजा–मऊ मुस्तकिल तहसील और जिला–आगरा, उत्तर प्रदेश–282005, चौहद्दीः पूरब में – श्रीमती रजनी का प्लॉट, पश्चिम में – डीगर का मकान, उत्तर में – सड़क / निकास 20 फीट चौड़ा, दक्षिण में – भूरी सिंह का प्लॉट

दिनांकः 23.07.2024, स्थानः आगरा — प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि हमारे मुवक्किल गांव पावला खुसरूपुर और गांव दौलताबाद (सेक्टर 106), उप–तहसील कादीपुर, तहसील जिला गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित जमीनों (नीचे अनुसूची में उल्लिखित) के संबंध में वित्तपोषण / उधार सुविधाएं प्रदान करने का इच्छुक है।

कोई भी कम्पनी/व्यक्ति सहित कोई बैंक या वित्तीय संस्थान उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई हक, स्वामित्व, दावा, मांग या अधिकार रखता हो या दावा करता हो या यदि किसी कम्पनी/व्यक्ति सहित किसी बैंक या वित्तीय संस्थान को कोई जानकारी हो या उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी विक्रय, अदला–बदली, सुपुर्दगी, दान, ट्रस्ट, लाइसेंस, किरायेदारी, पट्टा, लियन, ईज्मेन्ट, दृष्टि बंधक, विरासत, गिरवी, भार में पक्षकार हो, लम्बित कानूनी कार्यवाही, कब्जा, समझौता, विकास का अधिकार, साझेदारी, पारिवारिक समझौता /बंदोबस्त, लिस पेंडेंस, डिक्री या किसी अदालत द्वारा जारी आदेश, सरकार या किसी कम्पनी द्वारा अधिग्रहण, प्रतिबन्ध या किसी अन्य बाधा में पक्षकार हो तो ऐसी कम्पनी/ व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन के तिथि से 15 (पंद्रह) दिन की अवधि के अन्दर निम्न वर्णित पते पर लिखित मे दस्तावेजी सबूतों के साथ सूचित कर सकते हैं, जिसमें असफल होने पर यह माना जायेगा कि किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल हक, हिस्सा, स्वामित्व, अधिकार, दावा या मांग उक्त भूमि के सम्बन्ध में अस्तित्व में नहीं है वर्णित मालिकों का उक्त भूमि पर पूर्ण, स्पष्ट और बाजारयोग्य अधिकार है तथा सभी हक, अधिकार, दावा या मांग, यदि हो, पूर्ण रूप से और ज्ञाती भाव से समर्पित, अभ्यर्पित, त्याग, मुक्त तथा अधित्यक्त माने जायेगें और तदपश्चात किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार, दावा या मांग मान्य और विचाराधीन नही होगें और ना ही हमारे मुवक्किल व उसके उत्तरापेक्षी पर बाध्य होगें।

अनुसूची

सेक्टर–106, गुरुग्राम (गांव पावला खुसरूपुर उप–तहसील कादीपुर) में 24.10 एकड़ भूमि, जो कि मुस्तलील संख्या 18, किल्ला संख्या 21 (8–0) और 22/2 (4–0), मुस्ततील संख्या 19 किल्ला संख्या 24 (8–0), 25 (8–0), 16/2 (4–0), 23 (8–0), 22/2 (4–0) और 22/1 (3–1), मुस्ततील संख्या 21 किल्ला संख्या 5 (5–12), मुस्ततील संख्या 22 किल्ला संख्या 4 (8–0), 13 (8–0), 3 (8–0), 18/2 (3–5), 8 (8–0), 14 (8–7), 1/1 (6–5), 1/2/1 (0–12), 2/1/1 (1–0), 2/3 (3–3), 9/1 (4–8), 12/2 (5–3), 18/3 (1–3), 5 (7–3), 6 (8–0), 15/1 (4–0), 27 (0–17), 7 (8–0), 1/2/2 (1–3), 2/1/2 (0–10), 2/2 (2–7), 9/2 (3–12), 10 (5–16) और 12/1 (2–0), मुस्ततील संख्या 23 किल्ला संख्या 1 (8–0), 2 (8–0), 3 (4–7), 9/2 (3–9) और 10 (7–13) में सम्मिलित है [डीटीसीपी हरियाणा द्वारा जारी लाइसेंस सं. 80 दिनांक 17.8.2012 का भाग]

सेक्टर–106, गुरुग्राम (गांव पावला खुसरूपुर उप–तहसील कादीपुर) में 5.45 एकड़ भूमि, जो कि मुस्ततील संख्या 17 किल्ला संख्या 20/2 (1–18), 21/1/1 (1–18) और 21/2/1 (3–18), मुस्ततील संख्या 18 किल्ला संख्या 16/1/2 (2–7), 16/2 (4–9), 24 (4–0), 25/1 (6–5) और 25/2 (0–17), मुस्ततील संख्या 23 किल्ला संख्या 5/2 (3–16) और मुस्ततील संख्या 24 किल्ला संख्या 10/1 (6–4) और 1 (8–0) में सम्मिलित है [डीटीसीपी हरियाणा द्वारा जारी लाइसेंस सं. 79 दिनांक 17.08.2012 का भाग]

सेक्टर–106, गुरुग्राम (गांव पावला खुसरूपुर उप–तहसील कादीपुर) में 1.075 एकड़ भूमि, जो कि मुस्ततील संख्या 24 किल्ला संख्या 9/2 (5–4) और 2/1/1 (3–8) में सम्मिलित है [डीटीसीपी हरियाणा द्वारा जारी लाइसेंस सं. 11 दिनांक 12.03.2013 का भाग]

सेक्टर–106, गुरुग्राम (गांव पावला खुसरूपुर उप–तहसील कादीपुर) में 16.85 एकड़ भूमि, जो कि मुस्ततील संख्या 17 किल्ला संख्या 22/1/1 (0–11), 21/2/1 (0–14), मुस्ततील संख्या 18 किल्ला संख्या 16/2 (1–0), 24 (2–13), 14 (7–2), 18/1 (7–6), 15/1 (3–6), 13/2 (1–5), 17 (8–0), 23 (6–0) और 27 (1–7), मुस्ततील संख्या 19 किल्ला संख्या 19/1 (5–12), 20 (8–0), 21/1 (7–16), 21/2 (0–4) और 22/1 (0–7) मुस्ततील संख्या 20 किल्ला संख्या 16 (8–0) और 25 (8–0), मुस्ततील संख्या 22 किल्ला संख्या 26 (0–17), मुस्ततील संख्या 23 किल्ला संख्या 4/1 (2–0), 4/2 (3–19), 5/1/1 (2–0), 5/1/2 (1–15), 6/1 (6–4), 6/2 (1–16), 7 (5–15), 8/2 (2–4), 14/3(2–0), 15(8–0), 16 (5–5), 27 (0–11) मुस्ततील संख्या 24 किल्ला संख्या 2/1/2/1 (2–2), 2/1/2/2 (0–16), 10/2 (1–16), 11/1 (7–0), 20/1 (2–4) और मुस्ततील संख्या 48 किल्ला संख्या 5/15 (1–9–1) गांव दौलताबाद, उप–तहसील कादीपुर में सम्मिलित भूमि।

मंजुल मंत्री / शिवानी पांडा (अधिवक्ता)
लूथरा एण्ड लूथरा लॉ ऑफिसेस इंडिया
103, अशोका एस्टेट, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली –110001
फोन नं. 011–41215100
ईमेल आईडीः **mmantri@luthra.com & spanda@luthra.com**

Karnataka Bank Ltd. 100
Your Family Bank. Across India.

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
प्लॉट नं. 8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क,
पूसा रोड
नई दिल्ली – 110060

फोनः 011–40591567 (एक्स. 240)
ईमेलः delhiarm@kbank.com
वेबसाइटः www.karnatakabank.com
सीआईएनः L85110KA1924PLC001128

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.10.2021 को लिया गया है, उसके उधारकर्ता/गारंटर/सह–ऑब्लिगेंट (1) मैसर्स राधा माधव पब्लिक स्कूल इसके प्रतिनिधित्व द्वारा (i) श्री राजेश कमल छलेरिया–प्रबंधक, (ii) श्रीमती ललिता छलेरिया–प्रिंसिपल, एफ–43–44, संगम पार्क, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001, (2) श्री राजेश कमल छलेरिया पुत्र श्री नंद किशोर छलेरिया, (3) श्रीमती ललिता छलेरिया, पत्नी श्री राजेश कमल छलेरिया, (4) श्रीमती ओम वती छलेरिया, पत्नी श्री नंद किशोर छलेरिया, (5) श्री नंद किशोर छलेरिया, पुत्र श्री हरेश छलेरिया, सभी निवासी (2), (3), (4) और (5): 11/03–104, ब्लॉक – 11, त्रिलोकपुरी , दिल्ली – 110091 से सुरक्षित लेनदार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, अशोक विहार शाखा, ए–1, अशोक विहार, फेज I, नई दिल्ली–110052, की बकाया राशि रु. 33,78,891.10 (रु. तैंतीस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ इक्यानवे और पैसे दस मात्र) पीएस–टर्म ऋण खाता सं. 5617001800003701 के अंतर्गत दिनांक 05.05.2023 से भविष्य के ब्याज, प्लस लागत इत्यादि सहित की वसूली हेतु "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 22.08.2024 को बेचा जाएगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक, व्यवसायिक सम्पत्ति, नं. एफ 43 और 44, खसरा नंबर 985 में से निर्मित, क्षेत्रफल 200 वर्ग मी., संगम पार्क, गांव मकनपुर, तहसील और जिला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, श्रीमती ओम वती छलेरिया और श्रीमती ललिता छलेरिया से संबंधित, चौहद्दीः पूरब में – प्लॉट नं. 44–एफ, पश्चिम में – प्लॉट नं. 45–एफ, उत्तर में – सड़क 25 फीट चौड़ी, दक्षिण में – गली 10 फीट चौड़ी

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती: रु. 1,36,00,000/– (रु. करोड़ छत्तीस लाख मात्र)

जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशि: रु. 13,60,000/– (रु. तेरह लाख साठ हजार मात्र)

(उधारकर्ता/बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।)

(यह नोटिस उधारकर्ता/गारंटर को सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम–2002 के नियम (9) के उपनियम (1) के तहत नोटिस के रूप में भी कार्य करेगा)

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.karnatakabank.com** में दिए गए लिंक देखें। दिनांक 22.08.2024 को मेगा ई–नीलामी के अंतर्गत

ई–नीलामी 22.08.2024 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई–नीलामी (संभवतः 21.08.2024 को) मैसर्स 4क्लोजर, 605 ए, 6वीं मंजिल, मैत्रिवनम, अमीरपेट, हैदराबाद– 500038, संपर्क नं. 040–23836405, मोबाइल 8142000809, ई–मेलः info@bankauctions.in से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

दिनांकः 26.07.2024
स्थान : नई दिल्ली

कृते कर्नाटका बैंक लि.
मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड

सीआईएनः L92199DL2000PLC104779
पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार,
यूनिट नं. 236 और 237, दूसरी मंजिल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड,
मयूर विहार फेज । एक्सटेंशन, दिल्ली – 110091
दूरभाष नं. (+91–11) 49482870, (+91–124) 4354400, फैक्सः (+91–11) 49482900 (+91–124) 4354500
ईमेलः info@kamaholdings.com; वेबसाइटः www.kamaholdings.com

KAMA Holdings

होल्डिंग्स लिमिटेड की 24वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

कंपनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को अपराह्न 3:00 बजे IST पर कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और लिस्टिंग विनियमों और परिपत्र सं.–14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं.–17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं.–20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र सं.–2/2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिपत्र सं.–10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र सं.–9/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी। (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023 और 7 अक्टूबर, 2023 (सामूहिक रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार, एजीएम को बुलाने के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए–सदस्य www.evoting.nsdl.com पर वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। वीसी सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति और एजीएम की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.kamaholdings.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और ई–वोटिंग एजेंसी एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

जिन सदस्यों ने कंपनी के रजिस्ट्रार (आरटीए) के साथ अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किया है, वे नोटिस और ई–वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए आरटीए Einward.ris@kfintech.com या कंपनी info@kamaholdings.com से संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के पास केवाईसी अद्यतनीकरण फॉर्म (कंपनी की वेबसाइट info@kamaholdings.com और आरटीए की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/#isc_download_hrd पर उपलब्ध) भेजकर अपने विवरण को अद्यतन करें, जिस पर शेयरधारक(ओं) द्वारा आवश्यक विवरणों के साथ हस्ताक्षर किए गए हों।

एजीएम की सूचना में दूर से मतदान करने की विधि ("रिमोट ई–वोटिंग") प्रदान की गई है – एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोटों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग।

कृते कामा होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता/–
एकता माहेश्वरी
पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ और कंपनी सचिव

दिनांकः 26.07.2024
स्थानः गुड़गाँव

भौतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank — **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शॉल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा भौतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह–कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	अनमोल सेठी/ स्नेहलता सेठी/ LBGUR00002443068/ LBGUR00005354063/ LBGUR00002443069	शॉप नं.–308, थर्ड फ्लोर, ब्लॉक सी, निर्वाणा कंट्री साउथ सिटी, सेक्टर 50, गुड़गाँव, हरियाणा– 122001/ जुलाई 24, 2024	फरवरी 28, 2022 रु. 1,22,94,488/–	गुड़गाँव

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार(रों)/सह–कर्ज़दार(रों) एवं ज़मानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् कब्जे की संपत्ति(याँ) नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : जुलाई 26, 2024
स्थान : गुड़गाँव

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

सीआईएनः L29304DL1982PLC428372
कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः 4771, भरत राम रोड, 23, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, **दूरभाषः** 011–43000400,
ई–मेलः rkc@elinindia.com, **वेबसाइटः** www.elinindia.com

डाक मतपत्र की सूचना हेतु शुद्धिपत्र

यह विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कम्पनी द्वारा जारी दिनांक 05 जुलाई, 2024 के डाक मतपत्र सूचना के संदर्भ में है। यह शुद्धिपत्र कम्पनी के सदस्यों को उक्त सूचना के मद संख्या 1 से सम्बद्ध व्याख्यात्मक वक्तव्य में संशोधन के संबंध में सूचित करने हेतु जारी किया जा रहा है, अर्थात् सुश्री शिल्पा बैद (डीआईएनः 08538622) की 16 अगस्त, 2024 से आरम्भ कर 15 अगस्त, 2029 तक के निरंतर 5 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति। संबंधित परिवर्तन उक्त सूचना के पृष्ठ 13 पर अनुलग्नक–I अर्थात् "Details Of Directors Pursuant To Regulation 36(3) of The SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 And Secretarial Standards–2", मे "Qualification, Experience & Expertise in Specific Functional Areas", बिंदु के अंतर्गत सुश्री शिल्पा बैद (डीआईएनः 08538622) के विवरण में किए गए हैं।

विद्यमान विषय वस्तु नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रतिस्थापित सामग्री से प्रतिस्थापित मानी जाएगीः

Point	Details Of Directors Pursuant To Regulation 36(3) Of The SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 And Secretarial Standards – 2	
	Existing Content	Replaced Content
	Ms. Shilpa Baid	Ms. Shilpa Baid
Qualification, Experience & Expertise in Specific Functional Areas	Shilpa Baid, is an Independent Director on the Board of our Company. She holds a bachelor's degree in Commerce from Tribhuvan University, Nepal. She was a President of Ladies Circle India from the year 2003 to 2013. She has been associated with company since 2016.	Shilpa Baid, is an Independent Director on the Board of our Company. She holds a bachelor's degree in Commerce from Tribhuvan University, Nepal. She was a President of Ladies Circle India from the year 2003 to 2013. She has been associated with company since 2019.

इस शुद्धिपत्र को उक्त सूचना के साथ–साथ पढ़ा जाना चाहिए। उक्त सूचना की अन्य सभी सामग्री, इस शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित/परिवर्तित के अतिरिक्त, अपरिवर्तित रहेगी।

कृते **एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**
हस्ताक्षर/–
लता रानी पावा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एम. नं. A30540

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 जुलाई 2024

बेंजामिन नेतनयाहू
समर्थन पाने के प्रयास

बेंजामिन नेतनयाहू ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए गाजा युद्ध के लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने कांग्रेस में भाषण देते हुए अमेरिका से एकजुटता का आह्वान किया है। हालांकि, उनकी अपने देश में लोकप्रियता घट रही है और विरोध बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करते हुए नेतनयाहू ने अमेरिकन विधि-निर्माताओं का आह्वान किया कि वे गाजा में जारी सैनिक कार्रवाइयों का समर्थन करें। बढ़ती हिंसा तथा हताहत सिविलियनों की संख्या बढ़ने की पृष्ठभूमि में दिया गया यह भाषण नेतनयाहू की प्रतिबद्धता रेखांकित करता है कि वे इसराइल के सर्वाधिक शक्तिशाली सहयोगी का अडिग समर्थन चाहते हैं। उन्होंने जोर दिया कि इसराइल को गाजा में सक्रिय चरमपंथी समूहों, खासकर हमास से अपने अस्तित्व पर खतरा है। प्रधानमंत्री नेतनयाहू ने सैनिक कार्रवाई को इसराइली समुदायों को प्रभावित करने वाले राकेट हमलों तथा वर्तमान समय में जारी आतंकी हमलों की आवश्यक प्रतिक्रिया बताया। लेकिन नेतनयाहू के भाषण में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिन्ताओं को संबोधित नहीं किया गया था। 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' तथा 'ह्यूमन राइट्स वाच' समेत अनेक मानवाधिकार संगठनों ने इन क्षेत्रों में अनेक मानवाधिकार उल्लंघन उजागर किए हैं।

गाजा में मानवीय संकट नाकेबंदी के कारण और गंभीर हुआ है जिससे लोगों और वस्तुओं का आवागमन अत्यधिक सीमित हो गया है। इससे भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी

हो गई है। गाजा में वर्तमान आक्रमण 250 दिन से अधिक समय से जारी है जिसमें बड़े पैमाने पर मौतें और विनाश हुआ है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइली हमलों में 34,000 से अधिक लोग मारे गए हैं तथा 77,000 से अधिक घायल हुए हैं। मृतकों में लगभग 72 प्रतिशत महिलायें और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है कि 'हर दस मिनट में' गाजा में कोई बच्चा मारा जाता है या घायल होता है। इसराइल की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तथा सामूहिक दंड है जिसमें निरपराध सिविलियन जनसंख्या को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे मानवीय संकट गहरा रहा है। इसराइल के मुख्य सहयोगी के रूप में अमेरिका इसराइल-फिलिस्तीन टकराव की दिशा तय करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस समर्थन से अमेरिका की आलोचना हो रही है क्योंकि वह शांति तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराए हथियारों का प्रयोग इसराइल फिलिस्तीन में सिविलियनों के खिलाफ कर रहा है जो भयानक समय का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी जनता तथा कांग्रेस के कुछ सदस्यों में ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण की पैरोकारी की जा रही है। अमेरिका से अपील की जा रही है कि वह मानवाधिकार उल्लंघनों पर कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुए टकराव का टिकाऊ व न्यायोचित समाधान निकालने के राजनयिक प्रयासों का समर्थन करे। दोनों पक्षों के वैध सरोकारों को संबोधित करने वाले समावेशी व समग्र दृष्टिकोण से ही टिकाऊ शांति संभव होगी। इस क्षेत्र में न्याय व मानवाधिकारों की पैरोकारी की अमेरिका की नैतिक एवं रणनीतिक जिम्मेदारी है। अमेरिका बेंजामिन नेतनयाहू से कह सकता है कि वे गाजा पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सिविलियन ठिकानों पर बमबारी बंद करें ताकि हताहत सिविलियनों की संख्या न्यूनतम की जा सके। इस प्रकार अमेरिका इस क्षेत्र में स्थाई शांति की दिशा में केन्द्रीय भूमिका निभा सकता है।

दीर्घकालीन विकास को लक्षित बजट

केन्द्रीय बजट 2024-25 दीर्घकालीन विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करता है। भारत तेज विकास के लिए अपनी असाधारण क्षमता का लाभ उठाने की स्थिति में है।

दीपक सूद
(लेखक, एसोचैम के महासचिव हैं)

केंद्रीय बजट 2024-25 दीर्घकालीन विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करता है। भारत तेज विकास के लिए अपनी असाधारण क्षमता का लाभ उठाने की स्थिति में है। भारत की आर्थिक शक्ति मजबूत करने की दिशा में लक्षित 2024-25 वित्त वर्ष के केन्द्रीय बजट में प्रगतिशील सुधारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस बजट में एमएसएमई, ई-कामर्स व स्टार्टअप की प्रगति के अनेक प्राविधान किए गए हैं। इससे 'विकसित भारत' की दिशा में देश के रोडमैप के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाया गया है। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने गरीब, महिला, युवा और किसान को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्राविधान इस बजट में किए हैं। बजट में उनके द्वारा की गई घोषणायें एकदम सही समय पर सामने आई हैं। इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को 'अमृत काल' में आगे बढ़ाने तथा नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। इन प्रयासों से भारत का कद उभरती विश्व व्यवस्था में और आगे बढ़ेगा। पिछले दस साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में दसवें नंबर की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग 60 बाद पहली बार लगातार मिले अपने तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिज्ञा की है। मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट इस दिशा में बढ़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करता है।

इस बजट में एमएसएमई को और मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। बजट में उचित ही औद्योगिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर मौजूद एमएसएमई को आगे बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं जिसमें उसे आसानी से मिलने वाले कर्जों की व्यवस्था की गई है। भातर में वर्तमान समय में 633.9 लाख एमएसएमई हैं। इनमें से 99 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों की परिभाषा में आते हैं जिनकी संख्या 630.5 लाख है। 10 मिलियन रुपयों तक निवेश वाले सूक्ष्म उद्यमों को छोटे या मझोले उद्यम न बन पाने के पीछे एक प्रमुख कारण उनकी औपचारिक कर्ज तक पहुंच न होना था। 'मुद्रा लोन' की धनराशि दूनी करने तथा नई 'सिडबी' शाखायें स्थापित करने के माध्यम से ये संगठन अब आसानी से कर्ज तक पहुंच सकेंगे।

अन्य कदमों, जैसे 'मैनडेटरी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्कांउटिंग सिस्टम' से तरलता को बढ़ावा मिला है, जबकि औद्योगिक पार्क एमएसएमई को बहु-प्रतीक्षित डिजिटल समर्थन प्रदान करेंगे जो आमतौर से उनकी पहुंच में नहीं था। इसके साथ ही एमएसएमई के लिएनई कर्ज गारंटी योजनाओं ने बिना बंधक या तीसरे पक्ष की गारंटी के कर्जों की उपलब्धता सहज की है। इससे छोटे बिजनेस मालिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा तथा उद्यामिता को बढ़ावा मिलेगा। इस सकारात्मक समर्थन से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति छोड़ने का विश्वास पैदा होगा और वह 2047 का लक्ष्य बना कर तेजी से आगे बढ़ेगा। इस बजट में सरकार ने कौशल संवर्धन तथा रोजगार सृजन को केन्द्र में रखा है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने देश के नौजवानों में कौशल संवर्धन तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की है। कौशल संवर्धन पर लगातार जोर देने से प्रशिक्षण संस्थानों तथा बड़े निगमों को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति तैयार करने के दृष्टिकोण से सहभागिता में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षित श्रमशक्ति आसानी से बड़े एमएसएमई परिवेश में समाहित होगी, जबकि वर्तमान समय में इसे अक्सर प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए पैसे की कमी अनुभव होती है। लेकिन योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा ताकि रोजगार सृजन के प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ सकें।

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के इस बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। हालांकि, भारत का पिछले वर्षों में तेजी से शहरीकरण हुआ है, पर इसके बावजूद देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़ी संख्या में जनसंख्या की आजीविका का आधार बनी हुई है। मोदी सरकार पिछले दस साल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास कर रही है। इस प्रकार वर्तमान बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सरकार की ओर से मिलने वाले समर्थन का उद्देश्य इस क्षेत्र को मजबूत करना है जो देश की लगातार आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बजट 2024 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें की गई हैं जिनका उद्देश्य अनाजों व तिलहनों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा इनका उत्पादन बढ़ाना है। बजट में उठाए गए कदमों से नए आर्थिक क्लस्टर बनाने में व्यापक रूप से सहायता मिलेगी जो अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास सुनिश्चित करेंगे। बजट का उद्देश्य एक करोड़ किसानों को 'प्राकृतिक खेती' में प्रशिक्षण देना है। इसके साथ ही किसानों को मार्केटिंग, प्रमाणन व ब्रांडिंग, आर्गेनिक फार्मिंग, आदि क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण देने की योजना है। इन सबसे किसानों की अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत गति मिलेगी। सरकार ने भोजन की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने का लक्ष्य बनाया है। इससे सरकार का ग्रामीण परिस्थितिकी में दीर्घकालीन व टिकाऊ विकास का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से स्टार्टअप और ई-कामर्स को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट कदम उठाए हैं।

बजट में 'एंजल टैक्स' समाप्त करने की घोषणा की गई है। इससे पूरे देश के स्टार्टअप सिस्टम में खुशी की लहर दौड़ गई है। 2012 में लागू किए गए 'एंजल टैक्स' को गैर पंजीकृत कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशकों को जारी किए गए शेयरों से एकत्रित पूंजी पर लगाया जाता था, यदि शेयरों का मूल्य कंपनी की 'फेयर मार्केट वैल्यू'-एफएमवी से अधिक हो। इसी प्रकार ई-कामर्स का प्रयोग करने वाले व्यापारियों और कारीगरों को इस बजट में राहत दी गई है। इन पर टीडीएस न केवल घटाया गया है, बल्कि टीडीएस विलंब से जमा करने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इससे वर्तमान समय में ई-कामर्स निर्यात जो 2 बिलियन डालर है, उसके 2030 तक 350 बिलियन डालर होने की उम्मीद है। कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन से सरकार का इरादा उन कारीगरों और व्यापारियों को सहायता देना है जो अपनी चीजें वेबसाइटों से बेचते हैं।

यह कदम 'मेक इन इंडिया' रणनीति के अनुरूप है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत की ऊर्जा आवश्यकतायें तेजी से बढ़ रही हैं। छोटे नाभिकीय रिएक्टरों में निजी निवेश प्रोत्साहन तथा नाभिकीय ऊर्जा के नए रूपों में आरएंडडी को बढ़ावा देने के माध्यम से बजट भारत की 'ऊर्जा सुरक्षा' रणनीति सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। विभिन्न क्लस्टरों में नियमित 'ऊर्जा आडिट' के माध्यम से बड़े वाणिज्यिक थर्मल प्लांटों की स्थापना तथा भंडारण नीति को गति देकर बजट भारत को बढ़ती ऊर्जा मांग से निपटने का अवसर देता है। हालांकि, हमारे 'हरित ऊर्जा' लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं और 'हरित ईंधनों' की दिशा में परिवर्तन के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

भूमि रिकार्डों का 'डिजिटलीकरण' बजट में प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रगति पर संभवत: सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। हमारी भूमि के विशाल हिस्से, खासकर ग्रामीण भारत में अक्सर समुचित दस्तावेजीकरण न होने के कारण विवादों को जन्म देते हैं। यह बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की बड़ी बाधा है। पूरे भारत में भूमि रिकार्डों के डिजिटलकरण से सरकार विधि व्यवस्था में अनेक मामलों में बिचौलियों को समाप्त करने में सफल होगी तथा भूमि विवादों की संख्या में कमी आएगी। इस प्रकार कुल मिला कर केन्द्रीय बजट 2024-25 दीर्घकालीन टिकाऊ वृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत करता है। रणनीतिक निवेशों तथा अग्रगामी नीतियों से भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सफल होगा तथा अपना सामाजिक-आर्थिक विकास करेगा। 'विकसित भारत' का रास्ता अनेक चुनौतियों से भरा है, लेकिन टिकाऊ दृष्टिकोण व प्रगतिशील नीतिगत समर्थन से हम यह सपना पूरा कर सकते हैं।

बजट के द्वारा राजकोषीय व रोजगार संतुलन

बजट राजकोषीय अनुशासन के मार्ग पर चल रहा है, भले ही पीएम मोदी गठबंधन सरकार की अगुआई कर रहे हों।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखिक नीति विश्लेषक हैं)

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ग्यारहवां पूर्ण-कालिक बजट राजकोषीय अनुशासन के मार्ग पर चल रहा है, भले ही वह गठबंधन सरकार की अगुआई कर रहे हों। 4 जून के आश्चर्यजनक नतीजों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके करियर में शायद पहली बार गठबंधन सरकार दिलाई, लेकिन इसके बावजूद उनके बजट प्रस्तावों को रोका नहीं जा सका, जिसमें पृष्ठभूमि में ठोस अर्थशास्त्र के साथ-साथ राजनीतिक भी शामिल था।

बजट से पहले, कई लोगों ने उम्मीद की थी कि वित्त अधिनियम इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के राज्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोकलुभावन होगा। हालांकि निर्मला सीतारमण की जेब से जो निकला, वह एक ऐसा दस्तावेज था, जिसने लोकलुभावन मांगों के आगे झुकने के बिना दीर्घकालिक विकास और सभ्य बुनियादी ढाँचे के खर्च के मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चुना। सरकार द्वारा उजागर किया गया मुख्य विषय रोजगार है। देश के युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के सृजन के लिए घोषित योजनाओं की व्यवहार्यता के बारे में बजट के बाद के विश्लेषण में सवाल उठाए गए हैं।

भारत की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में प्रति वर्ष लाखों युवाओं को सरकारी वजीफा देने का वादा करने वाली प्रशिक्षु योजना तभी गेम चेंजर साबित हो सकती है, जब इन युवा प्रशिक्षुओं को ध्यानपूर्वक प्रशिक्षित किया जाए, ताकि उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से नौकरी मिल सके। अपेक्षाकृत अकुशल कार्यबल की प्रचुर उपलब्धता के बारे में गंभीर चिंताएँ हैं, जो बिना कोई सार्थक कौशल सीखे बड़े

कार्यालयों में काम करते रहते हैं।

ईपीएफओ से जुड़ी नई नौकरी प्रोत्साहन योजना के बारे में भी इसी तरह के सवाल उठाए गए हैं, जिसके कई पहलू हैं, जो संभवत: एक सुविचारित नीति को अंधेरे कोने में धकेल रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि नीतिगत धक्का मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अधिक युवाओं को औपचारिक मानक कार्यबल के भीतर लाना और उनमें शुरू से ही वित्तीय साक्षरता अनुशासन पैदा करना है।

हालांकि, यह वित्तीय साक्षरता तब धराशायी हो जाती है जब कोई सट्टा इक्विटी बाजार में निवेश करने वाले किसी भी निवेशक के लिए कर संरचनाओं में किए गए बदलावों को देखता है। पूंजीगत लाभ कर की बढ़ी हुई दर और नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के विपरीत प्रतीत होता है, सरकार चाहती है कि युवा पहले महीने के वेतन सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये का पूरा लाभ उठाने का बीड़ा उठाएं। पहले की कर व्यवस्थाओं ने औपचारिक नौकरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी युवा के लिए वित्तीय जिम्मेदारी की भावना पैदा की, जिसमें कई लोगों ने भविष्य में कर छूट का दावा करने और बचत करने के साधन के रूप में कम से कम एक उत्पाद चुना। इसने उन्हें कामकाजी पेशेवरों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक लंबे वित्तीय अनुशासन पथ पर आगे बढ़ाया, जो अब धीरे-धीरे आसान होता दिख रहा है। सरकार के पास प्रति-तर्क यह हो सकता है कि वे चाहते हैं कि उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पहले बढ़े, जिसका नेतृत्व युवा करें, जो अपनी नई नौकरियों में मिलने वाले मासिक वेतन से खाद्य पदार्थों, मनोरंजन आदि पर खर्च करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। हालांकि, यह उन्हें बचत की आदत डालने से रोकता है, जो बारिश के दिनों या कोविड जैसे संकटों के दौरान उपयोगी होती है। हां, सरकार ने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने में अच्छा काम किया, उम्मीद से बेहतर जीडीपी वृद्धि और केंद्रीय बैंक से भारी लाभांश भुगतान से उत्साहित। खाद्य पदार्थों को छोड़कर कुल मुद्रास्फीति भी सहनीय स्तरों के भीतर है, जिससे सरकार को कल्याणकारी परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए एक सहारा मिल रहा है, जो उसे लगता है कि आवश्यक है। केंद्रीय बजट 24-25 असंतुष्ट मतदाताओं को वापस लुभाने का एक प्रयास है। 4 जून के नतीजों से भाजपा ने जो सबक लिया है, वह यह है कि युवा विशाल मंदिरों, कुछ स्मार्ट चमचमाती ट्रेनों और अपने मेड इन इंडिया फोन में सस्ते मोबाइल डेटा को लेकर उत्साहित हैं।

लेकिन वे तेजी से पैसा कमाने, एक आकर्षक व्यवसाय करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षी जीवन शैली को आगे बढ़ाए। फिर गठबंधन की राजनीति के दबाव और खींचतान है, जिसमें एनडीए के दो सहयोगी टीडीपी और जेडी(यू) अपने मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की सेवा करने के लिए अपनी इच्छा सूची रखते हैं। एक दीर्घकालिक पासा फेंका गया है, शायद एनडीए 3.0 ने इस बजट के साथ गोल्डीलॉक्स संतुलन हासिल कर लिया है।

आप की बात

कारगिल युद्ध की स्मृति

कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर हम शहीदों को नमन कर रहे हैं। इस युद्ध ने भारत को कई सबक दिए हैं। पहले जहां सैनिकों के पांच पर्याप्त संसाधन, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट और बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे, वहीं वे आज सबको उपलब्ध हैं। 25 साल में सेना का कायापलट हो गया है और अब उसके पास अनेक आधुनिक संसाधन मौजूद हैं। फिर भी देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों के लिए निरंतर नई तकनीकों और मजबूत गुप्तचर तंत्र को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है। सेना के भीतर घुसे विदेशी जासूसों या उनको गुप्त जानकारी देने वालों की पहचान कर कठोर दंड देने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीक का उपयोग पूरे देश की सीमा पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि घुसपैठियों का स्वचालित ढंग से सफाया जा जाए। इस्राइल ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तकनीक का व्यापक विकास कर अनेक ऐसी तकनीकें भारत को भी सौंपी हैं। इनसे उन दुर्गम इलाकों में भी सटीक निगरानी संभव होगी जहां सैनिकों को पहुंचने व गश्त करने में कठिनाई होती है। लेकिन इस्राइल पर हुए भयंकरतम आतंकी हमले से स्पष्ट है कि केवल तकनीक पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। कारगिल शहीदों को सही श्रद्धांजलि सीमाओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाना होगा।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

संघ की बढ़ती स्वीकार्यता

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष शपथ पत्र देकर कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर अब केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है एवं अन्य संगठनों की तरह इसकी गतिविधियों में याचिकाकर्ता को शामिल होने का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 से संघ की गतिविधियों को राजनीतिक मानकर केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें शामिल होने पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। अपनी प्रखर व स्पष्ट राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण आरएसएस कांग्रेस समेत अनेक ऐसे राजनीतिक दलों के निशाने पर रहा है जो मुस्लिम तुष्टीकरण को अपने वोटबैंक का माध्यम बना कर जनता को संघ के खिलाफ भड़काते रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भारत-चीन युद्ध के समय संघ की प्रशंसनीय भूमिका को देखते हुए उसे गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। संघ के स्वयंसेवक देश में अनेक आपदाओं के समय राहत कार्यों से अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रतिबंध का कोई औचित्य नहीं था।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

परीक्षा व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा को निरस्त नहीं किया, हालांकि उसने परीक्षा में हुई गड़बड़ी को स्वीकार किया है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून अलग-अलग राज्य बना रहे हैं। इसके बजाय केंद्र को ही सभी बड़ी परीक्षाओं के लिए पूरे देश में एक कानून लागू करना चाहिए। पेपर लीक व किसी कोचिंग सेंटर के कई छात्रों का अत्यधिक नंबर लाने जैसी विसंगतियों के पुख्ता सबूत हैं। इन विकृतियों को देखते हुए पेपर सेट करने व उनको परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने की एकदम नई व्यवस्था पर विचार होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो एक ही विषय के लिए कई तरह के प्रश्न पत्र बनाएं और यह प्रश्न पत्र परीक्षा से एक घंटे पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन पहुंचाया जाए। इससे परीक्षा में मानवीय दखल पूरी तरह खत्म होने से कोई हेराफेरी संभव नहीं होगी। यदि परीक्षा परिणाम एक सप्ताह में जारी हो जाएं तो शिक्षा माफिया कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इससे परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी होगी। इसके साथ ही इंटरव्यू में भी पक्षपात समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। परीक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के सुझावों पर सभी पक्षों की राय लेकर केन्द्र व राज्यों के स्तर पर प्रभावशाली कदम उठने चाहिए।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

बाढ़ की विभीषिका

बाढ़ की विभीषिका अनेक स्थानों पर दिख रही है। फिर चाहे वह मुंबई, पूना, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, यूपी और बिहार हो, हर बाढ़ से मुसीबत आ रही है। पानी घरों में घुस रहा है, सड़कें डूब रही हैं, घरों में दरारें पड़ रही हैं तो कहीं पुल और पहाड़ दरक रहे हैं। यदि बरसाती पानी की संग्रहण व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए तो कभी पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन वर्षा जल के प्राकृतिक संरक्षक, वर्षा को बुलाने वाले तथा भूमिगत जल भंडारों के भरने में सहायक हरे-भरे जंगल कट रहे हैं और हरियाली उजड़ रही है। दूसरी ओर सीमेंट- कंक्रीट के नए-नए जंगल उभर रहे हैं जो पानी के प्राकृतिक बहाव में बाधा डालने के साथ ही बरसाती पानी को भूमिगत जल भंडारों तक पहुंचने से रोकते हैं। इससे सरकारों और जनता को पौधरोपण की याद आती है पर उनकी रखवाली भगवान् भरोसे छोड़ दी जाती है। शहरों में लगे पेड़ों की जड़ें चारों ओर पत्थरों, डामर या कंक्रीट से घिर जाती हैं और पेड़ों की अकाल मौत का कारण बनती हैं। नगर नियोजन, वृक्षारोपण व हरियाली की सुरक्षा में समन्वय बनाना जरूरी हो गया है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

सांसदों, विधायकों से मिले मुख्यमंत्री

तैयार होगी क्षेत्रीय विकास की कार्ययोजना

● अपने-अपने क्षेत्र में हो रही दिक्कतों और जनता की अपेक्षाओं को जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष किया प्रस्तुत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों संग लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक पूरी कर ली है। तकरीबन 20 दिन तक चली मंडलवार बैठकों में सांसदगण, विधायकगण और एमएलसी सीएम के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं और जन अपेक्षाओं को लेकर उपस्थित हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी जनप्रतिनिधियों को धैर्यपूर्वक सुनते हुए तथा उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास की नई रणनीति तैयार की जाए। 7 जुलाई को देवीपाटन और अयोध्या मंडल से शुरू हुई मंडलवार समीक्षा बैठक शुक्रवार को लखनऊ मंडल के साथ समाप्त हो गई है।

मंडलवार बैठक में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधिगणों ने खुलकर अपनी बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी विस्तार से भी की बातों को सुनने के बाद आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया। सीएम योगी ने संवाद, सक्रियता और सोशल मीडिया पर सर्वाधिक फोकस करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को जनता तक जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क लगातार बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विपक्ष की ओर से सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे अफवाहों और सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने के प्रयास का मुखर होकर विरोध करें। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए विपक्ष के हर झूठ को बेनकाब करें और जनता के बीच सच लेकर जाएं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में युवाओं और महिला संगठनों से संपर्क और संवाद स्थापित करें। युवाओं को बताएं कि बिना किसी रिश्वत और जाति, मत, मजहब के भेद के निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही है। ऐसे युवाओं से संपर्क स्थापित करें जिन्हें बिना भेदभाव और रिश्वत के नौकरियां मिली हैं। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों से भी लगातार संपर्क बनाए रखें।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुटने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है इस लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में हुए मतदान का बारीकी से एनालिसिस करें और इसी के आधार पर अपनी कार्ययोजना तैयार करें। सीएम योगी ने सभी जनप्रतिनिधियों को यह भी कहा कि शासन के लोककल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उतारने में कोई भी अधिकारी हीलाहवाली करे तो उसकी लिखित शिकायत करें, कार्रवाई निश्चित की जाएगी।

विधानभवन के निर्धारित स्थानों पर होनी चाहिए क्यूआरटी की उचित व्यवस्थाः सतीश महाना

● मानसून सत्र सोमवार से, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने की उच्च स्तरीय बैठक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी विधानसभा के आगामी 29 जुलाई से प्रारम्भ हो रहे मानसून सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुक्रवार को आलाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान वाहनों की जांच, आपातकाल स्थिति में विधानभवन परिसर से सदस्यों अधिकारियों एवं नागरिकों को सुरक्षित निकालने तथा विधानभवन के निर्धारित स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) आदि की भी चुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानभवन आने वाले विधायकों के गनर और सुरक्षा कर्मियों के बैठने तथा जलपान लंच आदि की उचित व्यवस्था करने के साथ ही भविष्य में उनके बैठने की स्थाई व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान अग्निशमन उपकरणों एवं दमकल वाहनों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही बैठक में विधानसभा भवन की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन करने, उसको सुदृढ़ करने, विधान सभा में दर्शकों एवं अन्य महानुभावों की प्रवेश प्रक्रिया तथा सुरक्षा आदि संबंधी अन्य बिंदुओं के विषय में विशिष्ट व्यवस्था करने पर विचार किया गया।

बैठक में प्रमुख सचिव, विधान सभा, प्रदीप दुबे, अपर मुख्य सचिव (गृह) दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन, के. रविन्द्र नायक, एडीजी (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश, एडीजी (सुरक्षा), रघुवीर लाल, पुलिस कमिश्नर, लखनऊ अमरेन्द्र सेंगर, जिलाधिकारी, तथा सूर्यपाल गंगवार समेत अन्य आलाधिकारी उपस्थिति थे।

सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है समाजवादी पार्टीः अखिलेश

● आरक्षण अधिकार दिवस पर सपा अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में स्थापित किया 'संविधान मान स्तम्भ'

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को 'आरक्षण अधिकार दिवस' के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम में 'संविधान मान स्तम्भ' की स्थापना की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी जिला एवं महानगर कार्यालयों में भी आज संविधान मान स्तम्भ की स्थापना के कार्यक्रम होंगे।

संविधान मान स्तम्भ का अनावरण करने के पश्चात् अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान मान स्तम्भ में स्थापित भारत का संविधान पीडीए प्रकाश स्तम्भ के रूप में हमारे लिए सदैव सामाजिक न्याय का मार्ग प्रकाशित और प्रशस्त करता रहेगा। यादव ने इस अवसर पर कहा कि समाजवाद का नाम इकलौती समाजवादी पार्टी में जुड़ा है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने आज के दिन कारगिल के शहीदों का भी स्मरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण अधिकार दिवस को समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तम्भ के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का विनम्र निर्णय लिया है क्योंकि 26 जुलाई सन् 1902 को महात्मा ज्योतिराव फुले जी द्वारा संकल्पित आरक्षण को कोल्हापुर के श्रीमंत महाराज राजर्षि छत्रपति साहूजी महाराज ने अपने राज्य में लागू करके आरक्षण का शुभारम्भ किया था। उनका उद्देश्य सभी को संख्या के अनुपात में आरक्षण देना था। यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की भावना को आरक्षण के रूप में इसी दिन अमल में लाया गया था जो आगे चलकर बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सद्प्रयासों से हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का मूल आधार बना और देश के लोकतंत्र की स्थापना का मूल सिद्धांत बना। उनका उद्श्य हजारों सालों से प्रतिनिधित्व वंचित लोगों को राजनीतिक जमात बनाने हेतु उनमें से ही प्रशासक वर्ग निर्माण करना था। आज भाजपा सरकार निजीकरण करके, नौकरियों में आरक्षण का अमल न करके इसे समाप्त कर रही है। यह सरकार युवाओं को नौकरियां भी सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है जिससे कहीं आरक्षण न देना पड़ जाए और दलित, पिछड़े, वंचितों को उनका हक न मिल पाए। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी का मानना है कि जाति के आधार पर जनगणना हो ताकि समानुपातिक आधार पर सबको सम्मान और हक हासिल हो सके। डॉ. राममनोहर लोहिया ने सबके विकास के लिए पिछड़ों को विशेष अवसर दिए जाने की मांग उठाई थी। संविधान और आरक्षण खत्म करने का खतरा अभी टला नहीं है। जनता के संकल्पित प्रयास से संविधान विरोधियों को मात देने का सिलसिला रूकने वाला नहीं। हम सब लामबंद होकर नफरत का खेल खेलने वालों को सफल नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का वैचारिक संघर्ष जारी रहेगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने शहीद मनोज पांडेय के आवास पर जाकर जाना उनके पिता का कुशलक्षेम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कारगिल युद्ध के नायक परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के आवास पर जाकर उनके पिता से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उन्हें अंगवस्त्र देकर आर्शीवाद लिया। राय ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास शहादत का रहा है और हम शहादत का मोल समझते हैं। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस पार्टी उन सभी शहीदों को नमन करती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। उनकी शहादत से सुरक्षित हैं इस देश की सीमाएं, सुरक्षित हैं हम। आज कांग्रेस पार्टी कारगिल युद्ध के सभी शहीदों को नमन करती है और उस युद्ध के शूरवीर शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के घर जाकर उन सभी शहीदों की शहादत को याद करते हुए भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करती है।

तदर्थ शिक्ष संघर्ष समिति ने अखिलेश यादव को सौंपा ज्ञापन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति उप्र ने ज्ञापन सौंप कर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सृजित, अनुदानित व रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त व दशकों से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सेवाएं समाप्त कर अपमानजनक व शोषणकारी मानदेय पूर्ण अस्थायी व्यवस्था में नियुक्ति के विरूद्ध तदर्थ शिक्षकों को न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1993 से अब तक नियुक्त व कार्यरत 2254 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं 9 नवम्बर 2023 के जारी एक शासनादेश से समाप्त कर दी गयी और उन्हें पिछले 8 महीने से न तो काम करने दिया जा रहा है, न ही वेतन दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने हालिया जारी शासनादेश 8 जुलाई 2024 में यह माना है कि माध्यमिक शिक्षा में हजारों पद रिक्त हैं और शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है तथा विकल्प के रूप में सेवा समाप्त ऐसे तदर्थ शिक्षकों को सहायक अध्यक्ष 25,000 रुपए तथा प्रवक्ता 30,000 रुपए के अत्यल्प मानदेय पर कार्य करने को निर्देशित किया है। जो बेहद अपमानजनक व शोषणकारी व्यवस्था के रूप में उसी विद्यालय के चपरासी के वेतन से कम है। शिक्षक संघर्ष समिति ने तदर्थ शिक्षकों के आंदोलन को पार्टी स्तर से नैतिक समर्थन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

निकाय से लेकर राज्य स्तर तक होगी मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना की निगरानी

● गठित होंगी कमेटियां, टेक्निकल एप्रेजल कमेटी करेगी प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

शहरी स्थानीय निकायों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही उनकी इनकम में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना को लेकर योगी सरकार बहुत आशान्वित है। सरकार इसके माध्यम से वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के अपने संकल्प में नगरीय निकायों को भी सहभागी बनाना चाहती है। ऐसे में निकायों में जो भी प्रोजेक्ट शुरू होंगे या फिर जिनका प्रस्ताव आएगा, उसका मूल्यांकन और मॉनीटरिंग निकाय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की जाएगी। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता के साथ ही प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में नगरों के सर्वांगीण विकास और नगरीय स्थानीय निकायों के रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि को लेकर नगर विकास विभाग ने राज्य की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं और अन्य मिशनों को मिशन टू मूवमेंट के रूप में विस्तारित कर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना की शुरुआत की है। शीर्ष स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग नगर विकास मंत्री के द्वारा की जाएगी। वो न सिर्फ योजना का सुपरविजन करेंगे, बल्कि योजना के ओवरआल इंप्लीमेंटेशन पर सलाह भी देंगे। वहीं स्टेट लेवल गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग के द्वारा की जाएगी। इसमें डायरेक्टर लोकल बॉडी मेंबर सेक्रेट्री होंगे, जबकि हाउसिंग, हेल्थ, एनर्जी, बेसिक एजुकेशन, फाइनेंस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेट्री और सीएडडीएस के डायरेक्टर इस समिति के मेंबर होंगे। कुछ रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स में एनआईसी के डायरेक्टर भी मेंबर होंगे। वहीं, चेयरपर्सन के निर्देश पर स्पेशल इनवाइटी को भी शामिल किया जाएगा। स्टेट प्रोग्राम मॉनीटरिंग यूनिट भी इसके तहत आएगी। टेक्निकल एप्रेजल कमेटी डायरेक्टर लोकल बॉडी अध्यक्ष होंगे, जबकि चीफ इंजीनियर, एडी अकाउंट्स, डायरेक्टर सीएंडडीएस और पीएमयू रिप्रजेंटेटिव्स इसके मेंबर होंगे। स्टेट प्रोग्राम मॉनीटरिंग यूनिट भी इसका हिस्सा होगी। नगर निगम के लिए बनी कमेटी में मेयर अध्यक्ष होंगे, जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर कमेटी के मेंबर सेक्रेट्री व कनवीनर होंगे। डीएम, डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी तथा डिवीजनल कमिश्नर द्वारा नामित पीडब्ल्यूडी के एसई इसके मेंबर होंगे। 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत सिविक बॉडी लेवल पर गठित कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाएगा। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए कमेटी में डीएम चेयरपर्सन होंगे, जबकि संबंधित निकाय के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, एग्जिक्यूटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और डीएम द्वारा नामित व्यक्ति इसके मेंबर होंगे।

योजना के माध्यम से प्रदेश में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में एकरूपता बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में नगरीय स्थानीय निकायों का योगदान बढ़ाने की दिशा में कार्य होगा। इसके साथ ही, नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में लाइवेबिलिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी, मास्टर प्लान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकरण जैसे आउटकम की संभावना है।

अचानक गाड़ी रुकवाकर मोची से मिले राहुल गांधी, बगल में बैठकर जाना हाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सुलतानपुर जिले में लंबित कानूनी मामले में तारीख पर पहुंचे। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पाण्डेय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' सहित भारी संख्या में कांग्रेस जन यात्रा में साथ रहे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी का रास्ते में कई जगहों पर कांग्रेसजनों तथा सामान्य नागरिकों खासतौर पर युवाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। न्यायालय में प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में लोको पायलट्स से मुलाकात की। नार्दन रेलवे इंप्लाइज यूनियन इकाई सुल्तानपुर लोको पायलट का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिला और अपनी मांगों को एक पत्र सौंपते हुए अपनी समस्याओं को वर्तमान सरकार के समक्ष रख उनके निराकरण कराने हेतु निवेदन किया। तदोपरान्त राहुल गांधी ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर मोची का काम करने वाले परिवार से लगभग आधे घंटे की मुलाकात कर उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने मोची परिजनों से कहा कि हम मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से संसद तक आपकी आवाज उठा रहे हैं।

जातिगत जनगणना कराने व आरक्षण के मुद्दे पर 10 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करेगी कांग्रेस

● राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन में कांग्रेस ने बुलंद की आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की पाबंदी हटाने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की पाबंदी हटाने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस और फिशरमैन कांग्रेस प्रदेश भर से 10 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करेगा। यह अभियान मण्डल आयोग की रिपोर्ट के लागू किये जाने के वर्षगांठ 7 अगस्त तक चलेगा। यह निर्णय शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय पर छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा 26 जुलाई 1902 में कोल्हापुर रियासत में लागू किये गए 50 प्रतिशत आरक्षण के वर्षगांठ पर आयोजित राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सामाजिक न्याय की जो आवाज बुलन्द की है उसे उत्तर प्रदेश में मजबूती से उठाया जाएगा। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि भाजपा के अंदर जो अगड़ों और पिछड़ों के नाम पर उठा पटक का नाटक हो रहा है वो सिर्फ़ पिछड़ों के कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देखने से हुई है।

इंग्लैंड और अमेरिका भी चखेगा कालानमक चावल का स्वाद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● सात दशक बाद इंग्लैंड व पहली बार अमेरिका जाएगा कालानमक

अब इंग्लैंड और अमेरिका भी चखेगा कालानमक चावल का स्वाद। करीब सात दशक बाद इंग्लैंड और पहली बार अमेरिका जाएगा कालानमक चावल। इसके पहले नेपाल, सिंगापुर, जर्मनी, दुबई आदि देशों को भी कालानमक चावल का निर्यात किया जा चुका है।

इंग्लैंड तो कालानमक के स्वाद और सुगंध का मुरीद रह चुका है। बात करीब सात दशक पुरानी है। तब गुलाम भारत में देश भर में अंग्रेजों के बड़े बड़े फॉर्म हाउस हुआ करते थे। ये इतने बड़े होते थे कि इनके नाम से उस क्षेत्र की पहचान जुड़ जाती थी। मसलन बर्डघाट, कैंपियरगंज आदि। सिद्धार्थनगर भी इसका अपवाद नहीं था। उस समय सिद्धार्थ नगर में अंग्रेजों के फार्म हाउसेज में कालानमक धान की बड़े पैमाने पर खेती होती थी। अंग्रेज कालानमक के स्वाद और सुगंध से वाकिफ थे। इन खूबियों के कारण इंग्लैंड में कालानमक के दाम भी अच्छे मिल जाते थे। तब जहाज के जहाज चावल इंग्लैंड को जाते थे। करीब सात दशक पहले जमींदारी उन्मूलन के बाद यह सिलसिला क्रमशः कम होता गया। और आजादी मिलने के बाद खत्म हो गया। इस साल पहली बार इंग्लैंड को 5 कुंतल चावल निर्यात किया जाएगा। इसी क्रम में पहली बार अमेरिका को भी 5 कुंतल चावल का निर्यात होगा। उल्लेखनीय है कि जबसे योगी सरकार ने कालानमक धान को सिद्धार्थ नगर का एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) घोषित किया है तबसे देश और दुनियां में स्वाद, सुगंध में बेमिसाल और पौष्टिकता में परंपरागत चावलों से बेहतर कालानमक धान के चावल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। जीआई मिलने से इसका दायरा भी बढ़ा है।

योगी सरकार ने इसे सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी घोषित करने के साथ इसकी खूबियों की जबरदस्त ब्रांडिग भी की। इसीके इसके रकबे उपज और मांग में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। राज्यसभा में 17 दिसंबर 2021 को दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2019/2020 में इसका निर्यात 2 फीसद था। अगले साल यह बढ़कर 4 फीसद हो गया। 2021/2022 में यह 7 फीसद रहा। कालानमक धान को केंद्र में रखकर पिछले दो दशक से काम कर रही गोरखपुर की संस्था पीआरडीएफ (पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन) के चेयरमैन पदमश्री डा आरसी चौधरी के अनुसार पिछले दो वर्षो के दौरान उनकी संस्था ने सिंगापुर को 55 टन और नेपाल को 10 टन कालानमक चावल का निर्यात किया। इन दोनों देशों से अब भी लगातार मांग आ रही है। इसके अलावा कुछ मात्रा में दुबई और जर्मनी को भी इसका निर्यात हुआ है। पीआरडीएफ के अलावा भी कई संस्थाएं कालानमक चावल के निर्यात में लगीं हैं डॉक्टर चौधरी के अनुसार निर्यात का प्लेटफार्म बन चुका है। आने वाले समय में यह और बढ़ेगा।

दुनियां का एक मात्र प्राकृतिक चावल जिसमें वीटा कैरोटिन के रूप में विटामिन ए उपलब्ध है। अन्य चावलो की तुलना में इसमें प्रोटीन और जिंक की मात्रा अधिक होती है। जिंक दिमाग के लिए और प्रोटीन हर उम्र में शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है। इसका ग्लाईसेमिक इंडेक्स कम (49 से 52 प्रतिशत) होता है। इस तरह यह शुगर के रोगियों के लिए भी बाकी चावलों की अपेक्षा बेहतर है।

विधायक बेदीराम व विपुल दूबे समेत 18 अभियुक्तों पर गैंगेस्टर में आरोप तय

विधि संवाददाता। लखनऊ

18 वर्ष पुराने गैंगस्टर के एक मामले में शुक्रवार को विधायक बेदीराम व विपुल दूबे समेत 18 अभियुक्त विशेष अदालत के समक्ष हाजिर हुए। विशेष जज पुष्कर उपाध्याय ने सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) के तहत आरोप तय कर दिया। साथ ही अभियोजन को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी।

गैंगेस्टर का यह मामला रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा से संबधित प्रश्न पत्र के लीक होने का है। गैंगेस्टर के इस मामले में कुल 19 अभियुक्त थे। 26 फरवरी 2006 को एसटीएफ ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की रिपोर्ट थाना कृष्णानगर में दर्ज हुई थी। आरोपी बेदीराम गाजीपुर की जखनियां जबकि विपुल दूबे भदोही की ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं। इससे पूर्व विशेष अदालत के समक्ष कुछ अभियुक्तों की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की गई। जबकि एक अभियुक्त ने आरोप पत्र की नकलें दिलाने की मांग की। विशेष अदालत ने सभी अर्जी खारिज कर दी। कहा कि 13 वर्ष पूर्व ही इस मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जा चुका है। अब अभियुक्तगण जानबूझकर इस मामले को और विलंबित करना चाहते हैं। यह भी कहा कि आरोप पत्र की नकलें सभी को मुहैया करा दी गई है। शुक्रवार को विशेष अदालत में विधायक बेदीराम उर्फ बेदीलाल व विपुल दूबे के अलावा अभियुक्त संजय श्रीवास्तव, कृष्णकांत, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, रामकृपाल सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी, आनंद कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार, रमेश चंद्र पटेल, मो. असलम, अवधेश सिंह, सुनील कुमार यादव, अख्तर हुसैन, दीना उर्फ दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह व रश्मि चंद्रा हाजिर हुए थे। विशेष अदालत ने इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) के तहत आरोप तय किया। कहा कि वर्ष 2006 से पूर्व अभियुक्तगणों ने लखनऊ शहर में एक संगठित गिरोह बनाया। जिसका उद्देश्य स्वयं तथा अपने गिरोह के अन्य साथियों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने विभिन्न तारीख व समय पर आईपीसी के अध्याय 17 में वर्णित अपराध किए। लिहाजा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश गिरोह बंद तथा समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का मामला निर्मित होता है। विशेष अदालत ने एक अभियुक्त कृष्ण कुमार यादव की मौत होने के चलते उसके विरुद्ध मुकदमा समाप्त कर दिया।

मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में संविदा कर्मी, काला फीता बांध किया काम

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ की लखीमपुर इकाई द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी के आवाहन पर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार से आंदोलन में सहभागिता शुरू कर दी गई है। इसके क्रम में शुक्रवार को जिले के समस्त एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर कार्य किया और अपना विरोध दर्ज कराया। जिला अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश भर में एनएचएम के अंतर्गत तैनात कर्मचारी की प्रमुख मांगों को लेकर लगातार शासन व प्रशासन से वार्तालाप किया जा रहा था परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी जब निष्कर्ष नहीं निकला तब प्रदेश कार्यकारिणी के आवाहन पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिलेभर में तैनात एनएचएम संविदा कर्मियों ने शुक्रवार को काला फीता बांधकर कार्य किया और अपना विरोध दर्ज कराया है।

जिला पुरुष चिकित्सालय में डॉ शिखर बाजपेई और डॉ शिशिर पांडे के नेतृत्व में संविदा कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन महंत सिंह व फार्मासिस्ट सहदेव सचान सहित संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं टीबी क्लिनिक में तैनात संविदा कर्मचारियों ने भी कला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से फार्मासिस्ट परमानंद वर्माए संजय राय आधिकारिक कर्मचारियों ने भाग लिया इसी तरह सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केदो पर तैनात संविदा कर्मचारियों ने कला फीता बांधकर पहले दिन अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है।

कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण पांच अगस्त तक हो सकेंगे

फतेहपुर। यूपी बोर्ड के स्कूलों में प्रवेश लेने वालों के लिए अभी भी मौका है। बोर्ड की ओर से कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के पंजीकरण के लिए 5 अगस्त अंतिम तिथि तय की है। ऐसे में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को पांच अगस्त तक का मौका मिल सकेगा। छात्र-छात्राओं के पंजीकरण कराने में हेराफेरी करने वाले विद्यालयों पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के पंजीकरण के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है।

26 अगस्त तक जमा होगा चालान: माध्यमिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं का शुल्क चालान के माध्यम से कालेज के प्रधानाचार्य को 26 अगस्त तक जमा कराना होगा और 26 अगस्त तक सभी छात्र-छात्राओं का विवरण भी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराना आवश्यक होगा। 26 अगस्त से 5 सितंबर के बीच संस्था के प्रधानाचार्य वेबसाइट पर छात्र-छात्राओं के विवरण फोटो आदि की जांच कर सकेंगे। इस दौरान किसी भी विवरण में अपडेशन नहीं कराया जा सकेगा। जांच के बाद कमी पाए जाने पर 5 सितंबर से 20 सितंबर तक परीक्षार्थियों के विवरण में संशोधन कराया जा सकेगा लेकिन इस दौरान कोई नवीन छात्र का विवरण अपलोड नहीं कराया जा सकेगा। 20 सितंबर को कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं के विवरण को अंतिम रूप देने के बाद उसकी एक प्रति माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को 30 सितंबर तक प्रधानाचार्य के माध्यम से भेजी जाएगी।

कारगिल दिवस पर युवाओं ने दिया देशभक्ति का संदेश

फतेहपुर। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्रेक्षागृह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सभा का आयोजन कर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिक कैप्टन राजकुमार राठौर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जिला प्रवासी रुद्र मिश्रा रहे।

भाषण, गीत प्रतियोगिता, ताइक्वांडो प्रदर्शन समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें 10 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि ने युवाओं में उत्साह भरते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने अदम्य साहस दिखाते हुए 60 दिनों में भारतीय विजय पताखा फहराने का काम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीचता पूर्ण घटना का पूरे दमखम के साथ धूल चटाने वाले अटल बिहारी वाजपेई हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। प्रदेश कार्य समिति सदस्य रुद्र मिश्रा ने युवाओं में उत्साह भरा।

जिलाध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा ने सभी भाषण प्रतिभागियों, पूर्व सैनिकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की सराहना की। संचालन जिला महामंत्री प्रसून तिवारी ने किया। इस अवसर पर ऐश्वर्या सिंह चंदेल, गौरव अग्रहरि, विमलेश पांडेय, सावन गुप्ता, उदय प्रताप सिंह, कुलदीप मौर्य, सुयश अंबेडकर, मंडल अध्यक्ष किशन शुक्ला, गौरव अग्रहरि, हिमांशु त्रिपाठी, आलोक सिंह, अनुभव शुक्ला, सचिन पांडे समेत निलेश मिश्रा, घनश्याम राजपूत, दुर्गेश लोधी, नीरज निषाद आदि तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पूर्व राज्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को सौंपी आर्थिक सहायता

मृतक बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता देतीं पूर्व राज्यमंत्री।

गुरसहायगंज (कन्नौज)। विगत दिनों पूर्व समधन के मोहल्ला गर्दाबाद में तालाब में नहानें गये एक ही मोहल्ले के चार बच्चों की गहरे पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। जिसमें शासन द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता को पूर्व राज्यमत्री अर्चना पाण्डेय नें मृतक बच्चों के परिजनों को सौंपकर संवेदना व्यक्त कीं।

बीतीशाम क्षेत्र के कस्वा समधन के मोहल्ला गर्दाबाद में समर्थकों के साथ पहुंची पूर्व राज्यमंत्री अर्चना पाण्डेय नें छिबरामऊ उपजिलाधिकारी उमाकान्त, चेयरमैन आसमा बेगम व उनके प्रतिनिधि अखलाख हुसैन सिददीकी के साथ चार मृतक बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान करनें के उपरान्त मृतक बच्चों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हुये हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होनें कहा कि भाजपा सरकार समस्त प्रदेश वासियों के सुख दुख में सदैव साथ रही है।

भारी बारिश से सरकारी कार्यालय जलमग्न

मौदहा, हमीरपुर। शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश में सरकारी दावों की पोल खुल गई और कस्बे का जल संस्थान में पानी से भर गया, वहीं बिल जमा करने गए उपभोक्ता और कार्यालय में बैठे कर्मचारी असहाय नजर आए। वहीं बिल जमा करने कार्यालय आए उपभोक्ताओं में से एक उपभोक्ता ने वीडियो वायरल कर विभाग की पोल खोल दी। शुक्रवार दोपहर हुई लगभग घंटे की जोरदार बारिश ने कस्बे के सरकारी दावों की पोल खोल दी। दोपहर बाद एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हुआए जिसमें कार्यालय में कुर्सी पर बैठे कर्मचारी असहाय दिखाई दिएए जबकि पूरे कार्यालय में करीब चार से पांच इंच पानी से भरा हुआ दिखाई दिया। जिससे विभाग में रखीं फाइलें भी प्रभावित हुईं। हालांकि समाचार पत्र वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता हैए लेकिन वायरल वीडियो मौदहा के जल संस्थान का बताया जा रहा है। जिसमें लोगों द्वारा तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे है।

बरसात के चलते डीएम द्वारा गठित टीम मौके पर नहीं पहुची

हमीरपुर। लघु सिचाई द्वारा निर्मित किये गये चेकडैमों की जांच के लिये डीएम द्वारा बनायी गयी कई टीमे भारी बरसात होने के कारण मैके पर नही जा सकी। हालाकि इसके लिये टीम में शामिल अधिकारी ठेकेदारों को लेकर चंडौत बस स्टेशन में जाकर ग्रामीणों के बुलाकर उनसे मान मनौब्बल करते रहे। जमकर विवाद हुआ। उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। जानकारी के मुताबिक विभाग द्वारा वाटर रिचार्जिंग सिचाई के लिये बनाये गये चेकडैम समय से पहले ही नष्ट हो गये है बंधौली व चंडौत में अभी हाल ही में बनाये गये थे मगर वह चटक गये है जब कि विभाग के अधिशासी अभियंता एसबी सिंह का कहना है कि चेकडैम पांच साल पहले बनाये गये थे वह नष्ट हुये है एक्शियन ने उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया है। इधर आज जांच के लिये गयी जांच टीम के अधिकारी बरसात के कारण जब मौके पर नही जा पाये तो ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया जिससे जांच अधिकारियों में काफी देर तक झड़प होती रही। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई चेकडैम नही है जिससे एक बूद से खेत की सिचाई हुई हो उधर ठेकेदारों द्वारा ग्रामीणों पर जांच टीम दबाव पाने का प्रयास किया मगर ग्रामीणों ने ठेकेदारो को भी खरी खोटीसुनायी है। जिससे मौके पर भीड एकत्र हो गयी। उधर महेंद्र सिंह राजपूत ने चेकडैम के बारे में पांच साल के बनाये गये चेकडैमों की आरटीआई से सूचना मांगी है। ताकि विभागीय अभियंताओं की असलियत शासन के सामने लायी जा सके। हालाकि बिभागीय अभियंता नेताओं की चौखट में हाजिरी देना शुरु कर दिया है वही उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है।भाजपा नेताओ का कहना है कि यदि अधिशासी अभियंता ने किसानों के साथ धोखा किया तो आन्दोलन किया जायेगा। मामला शासन स्तर पर पहुच गया है।

आबकारी विभाग ने 118 लीटर कच्ची शराब की बरामद

फर्रूखाबाद। आबकारी आयुक्त, के आदेश एवं डीएम के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जनपद के आबकारी निरीक्षक क्षेत्र.1 कुमार गौरव सिंह एवं क्षेत्र .2 राजेश कुमार चौबे मय स्टाफद्वारा बाग लकूला एवं कायमगंज क्षेत्र में दबिश दी गई। लगभग 180 किग्रा लहन नष्ट किया व लगभग 118 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 3 अभियोग पंजीकृत किये गए। आबकारी दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। स्टाक रजिस्टर, आनलाइन पेमेंट एसी सी टी वी कैमरा का परीक्षण किया गया। अवैध मदिरा के निर्माण बिक्री परिवहन की रोकथाम हेतु प्रवर्तन कार्य निरंतर जारी रहेगा।

क्विक न्यूज

25 लाख से अधिक के कीमती 101 मोबाइल बरामद

फर्रूखाबाद। पुलिस ने आज 25 लाख रुपए से अधिक के कीमती 101 मोबाइल बरामद किये। यह जानकारी आज शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि देश, प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं थानों के पिछले कई महीनो से गायब हुए एवं चोरी गए फोन धारको की सूचना के उपरांत सर्विलांस पुलिस टीम प्रभारी विशेष कुमार के दलबल द्वारा आज शुक्रवार को 25 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाले 101 मोबाइलों को बरामद किया। उन्होंने बताया कि जिले की पुलिस सर्विलांस टीम द्वारा बरामद किए गएए सभी मोबाइलों को आज फतेहगढ़ पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित किए गए गए। एक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार प्रियदर्शी ने फोन धारक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया। जिसके फलस्वरूप सभी फोन धारकों में खुशी की लहर की दौड़ गई।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत

फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के कस्बे के समीप जंगल गया युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी राम प्रकाश सिंह का 24 वर्षीय पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह गांव के समीप जंगल गया था। तभी 11 हजार लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी परिजनों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत

फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जिसकी सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी स्वर्गीय जयपाल के 28 वर्षीय पुत्र छोटू कश्यप की घर पर संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच पड़ताल कर रही है।

बेतवा नदी का जल स्तर बढा

हमीरपुर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ व छतरपुर जिलों में हुई बारी बरसात के कारण धसान नदी में पानी बढ़ गया है। इसलिये वेतवा नदी में लगभग ढाई मीटर तक पानी बढने की संभावना है। दोनो नदियां खतरे के निशान से बहुत दूर है। हालाकि प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगो से बाढ़ से सतर्क रहने का एलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन का मानना है कि फिलहाल जिले में बाढ़ जैसे कोई हालात नही है।

तीन लोगों पर की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई

गुरसहायगंज (कन्नौज)। गुरुवार को स्थानीय कोतवाली कार्यालय में प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के कस्बा समधन के मोहल्ला गोरी नवादा निवासी वसीम पुत्र वकील तथा ग्राम अनीभोज निवासी रिजवान पुत्र यूनुस एवं ग्राम खाडेदेवर निवासी राजीव कुमार पुत्र सुरेश चंद्र कटेरिया आदि गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं इनका जनता में डर व आतंक व्याप्त है। उनके भय की वजह से जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं है। बताया कि वसीम व रिजवान अपने घर आते जाते रहते हैं। जबकि राजीव अपने घर पर मौजूद है। आरोपियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट कार्रवाई की गई है।

ज्वेलर्स की दुकान से युवक का मोबाइल हुआ चोरी

गुरसहायगंज (कन्नौज)। ज्वेलर्स की दुकान पर जेवरात खरीदने आए युवक का एक अज्ञात महिला ने मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर निवासी राम पाल बाथम पुत्र नंदराम द्वारा कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि शुक्रवार की दोपहर नगर के चकोर रोड स्थित मां आभूषण केंद्र पर जेवरात खरीदने आया था। ग्राम मझपुरवा निवासी अज्ञात महिला ने उसका मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।

पंचायत सचिवों, पंचायत मित्रों तथा प्रधानों के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम बना मजाक

मौदहा हमीरपुर। मनरेगा के कार्यों में होने वाले मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम में एक ही फोटो को अलग.अलग मस्टररोल में दर्शाया जा रहा है लेकिन जिम्मेदार आंख मिचौली का खेल खेलकर कार्य प्रभारी एवं पंचायत मित्रों की क्रिया कलापों पर मूकदर्शक बने बैठे हैं हालांकि सीडीओ समय-समय पर विकास कार्यों की निगरानी हेतु कार्य स्थल पर पहुंच वहां की जमीनी हकीकत देखते हुए भी अंजान बन रहे हैं।मौदहा विकासखंड का हमेशा विवादों से गहरा रिश्ता बना रहा है फिर चाहे यहां आवास घोटाला का मामला हो या मुर्दों से मनरेगा के विभिन्न काम करवाने का लेकिन मौजूदा समय में मनरेगा के हो रहे विकास कार्यों में सरकार द्वारा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से प्रतिदिन मनरेगा मजदूरों की हाजिरी का प्रावधान रखा गया है, उक्त पद्धति से मनरेगा में पारदर्शिता स्थापित होगी लेकिन विकासखंड कार्यालय में तैनात तमाम सचिवों प्रधानों एवं पंचायत मित्रों ने सरकार की मंशा को धता बता दिया है।

प्रशिक्षण व रोजगार गुणवत्ता की जांच समिति बनाकर करें: जिलाधिकारी

फतेहपुर। कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अनुश्रवण की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सी. इंदुमती की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। उन्होंने केंद्र प्रोषित योजनाएं पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, राज्य पोषित योजना स्टेट स्किल डेवलपमेंट, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, प्रोजेक्ट प्रवीन, जिला कारागार प्रशिक्षण से सबद्ध सस्थाओं की बिंदुवार प्रगति समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित पाए जाने वाली संस्था पोषिष्ट स्किल अग्रनाइजेशन, जीरो. टू0स्पा सैलून प्राइवेट लिमिटेड से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश संबंधितों को दिये। उन्होंने कहा कि संस्थाएं संचालित कोर्सो में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार युवक व युवतियों का नामांकन कराते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण निर्धारित समय से पूर्ण कराते हुए रोजगार दिलाएं। उन्होंने कहा कि संस्थाओं में संचालित कोर्सो में दिये जा रहे प्रशिक्षण व रोजगार की गुणवत्ता की जाँच समिति बनाकर करें और सूचना रिपोर्ट से भी अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कर रहे युवक व युवतियों के नाम, मोबाइल नंबर, पता सहित सूची भी उपलब्ध कराएं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत स्किल प्राप्त युवकों को औधोगिक अधिष्ठानों में अप्रेंटिसशिप दिलाएं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लेने वाले को समयबद्धता के साथ प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण के दौरान फोटोग्राफी कराकर उपलब्ध करायी जाये। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला अर्थ संख्याधिकारी, डीसीएनआरएलएम, प्रधानाचार्य आईटीआई, प्रधानाचार्य पॉलिटेक्निक, जिला पंचायत राज अधिकारी, उपायुक्त उद्योग सहित संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन व पुलिस ने आरटीओ कार्यालय के बाहर मारा छापा

पुलिस हिरासत में मौजूद चौदह आरोपी।

● लाईसेंस के नाम पर अबैध बसूली करनें वाले चौदह लोगों को पकडा

कन्नौज। शक्रवार को अपर जिलाधिकारी आशीष सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संसार सिंह के नेतृत्व में सदर क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश शर्मा द्वारा दलबल के साथ आरटीओ कार्यालय कर छापा मार कार्यवाही की गयी जिसमें करीब चौदह लोगों को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की गई है। स्थानीय कोतवाली में अपर जिलाधिकारी आशीष सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संसार सिंह नें जानकारी देते हुये बताया कि विगत कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि आरटीओ कन्नौज के बाहर कुछ लोगों ने अपनी दुकाने एवं झोपडिया खोली हुई हैं। आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेन्स एवं ड्राइविंग लाइसेन्स रिन्यूवल आदि काम करवाने हेतु लोग जाते है उन लोगों से यह कहकर कि तुम्हारा काम हमारे माध्यम से हो सकता है एवं काम कराने के बदले में अवैध वसूली करते हैं। एवं ये लोग काम करवाने हेतु आने वाले लोगों को यह कहकर धमकाते है कि यदि तुम लोग हमारे माध्यम से काम नहीं करवाओगें तो तुम्हारा काम नही होने देगे। एडीएम आशीष सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संसार सिंह, सदर क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार, प्रशिक्षु सीओ/थाना प्रभारी तालग्राम कपूर कुमार, प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश शर्मा, उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र ने दल बल के साथ छापेमारी कर श्रीराम, विकास, अभिषेक, ऋषभ, अवनेश कुमार, विपिन कुमार, देवेन्द्र, मुलाब, अजय कुमार, मो0 शमील, अमर कुमार शर्मा, सुमित, शिवाकान्त, हरिओम को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है।

सैकड़ों बीघा पशुचर, ग्राम समाज परती एंव सरकारी भूमि पर दबंगों ने किए कब्ज़े

रोपी गयी धान की फ़सल

संडीला (हरदोई)। क्षेत्र में सक्रिय पैसे और पहुंच वाले दबंग भूमाफ़िया के आगे प्रशासन कितना बेबस और बौना है इसका उदाहरण ग्राम ककराली और उसका मजरा सेमराखेड़ा तथा ग्राम सभा आलमपुर हैए जहां पशुचर, परती और खाद्य के गड्ढों आदि के लिए रिज़र्व भूमि पर दबंग भूमाफ़िया ने कब्ज़ा कर उन्हें खेतों पर परिवर्तित कर बाकायदा धान की फ़सल भी रोक दी। ग्रामसभा ककराली का मजरा सेमराखेड़ा में जानकारी के अनुसार लगभग 200 बीघा पशुचरए परती तथा वन क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि है। इस भूमि पर वर्तमान तथा पूर्व प्रधानों की सहमति और राजस्वकर्मियों के संलिप्त होने के कारण इनपर भूमाफ़िया ने अपने लोगों के कब्ज़े करा दिए। धीरे.धीरे इन लोगों ने इन जमीनों को खेतों में परिवर्तित कर दिया। इस क्षेत्र में बाकायदा जेसीबी चलाकर ज़मीनों की हदबंदी कराकर कब्ज़े किए गए और यह सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर जो कुछ पशुचर भूमि बची भी थी उसपर भी बाकायदा जुताई करके धान की पौध रोप दी गयी है। कई स्थानों पर मिट्टी माफ़िया ने अंधाधुंध खुदाई करके वहां बड़े.बड़े तालाब भी बना डाले हैं। हद तो यह है कि इन दबंग लोगों ने वन विभाग के लिए संरक्षित भूमि तक पर कब्ज़े कर लिए। वर्तमान स्थिति यह है कि ग्राम सेमराखेड़ा में द 10 बीघा भी पशुचर और परती भूमि नहीं बची है। अब आवारा पशु वनविभाग के द्वारा स्थापित वन उपवन में ही चराई कर अपना किसी प्रकार पेट भर रहे हैं।

इसके अलावा विधानसभा ककराली के आसपास जो भी पशुचर और परती भूमि थीए उसपर भी कब्ज़ा करके उन्हें खेतों में परिवर्तित कर दिया गया है। ग्रामसभा आलमपुर के बाहर जो भी खाद्य के गड्ढे, परती और पशुचर भूमि थी उस पर भी अवैध कब्ज़े हो गए हैं और इनमें से अधिकांश में धान की पौध रोक दी गयी है। सरकारी भूमि की इस प्रकार की गयी लूट के संबंध में तमाम शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी।

संचारी अभियान को मुंह चिढ़ा रही शहर में फैली गंदगी

फतेहपुर। बारिश के मौसम में वेक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण को लेकर चलाया जा रहा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान विफल होता नजर आ रहा है। शहर में जगह-जगह फैली गंदगी इस बात की गवाही दे रही हैं कि अभियान के तहत जो निरोधात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए वह नहीं हो रही हैं।

शासन के निर्देश पर एक से 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान समापन की ओर है। बावजूद इसके नगर पालिका के क्षेत्र में रानी कालोनी में गंदगी का अंबार लगा है। यहां पर सड़क किनारे नालियां गंदगी से अटी हैं। नालियां ओवरफ्लो होने के बाद गंदगी आधी सड़क पर फैली हुई है। यहां के लोगों का कहना कि यहां पर नगर पालिका की ओर से सफाई नहीं कराई गई है। यहां पर लोग सड़क किनारे ही गोबर व कूड़ा डालने का काम करते हैं। कई-कई दिन बाद कूड़े को उठाकर डंपिंग ग्राउंड में डाला जाता है। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा कई दिन तक कूड़ा इकट्ठा करने के बाद उठाया जाता है। जिस कारण नाली में पानी की निकासी बंद हो जाती है। गंदगी से नाली भरने के बाद सड़क पर गंदगी फैल जाती है।

सफाई के नाम पर झाड़ू तक ही सीमित: अभियान के सभी वार्डो के मोहल्लों में साफ सफाई के साथ एंटी लार्वा का छिड़काव, फागिंग समेत घास-झाड़ियों की कटाई आदि किया जाना चाहिए लेकिन तांबेश्वर मंदिर चौराहे से जिला कारागार जाने वाले मार्ग में मंदिर के ठीक पीछे झाड़ियों का अंबार है। झाड़ियां इतनी बड़ी हैं कि आधा मार्ग तक बंद हो चुका है लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। खासकर साउथ सिटी के अधिकांश मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा है जिसकी सफाई अभी तक नहीं हो सकी है। मच्छर बीमारी बांटने को तैयार: बारिश के मौसम में मच्छरों का आंतक बढ़ चुका है।

जरा याद करो कुर्बानी! कारगिल के शहीदों को शत् शत् नमन, डीएम ने दी श्रद्धांजलि

● डीएम ने खीरी के पांच पराक्रमी कारगिल सैनिकों को किया सम्मानित

लखीमपुर खीरी। जिलेभर में शुक्रवार को 25 वॉ कारगिल शौर्य दिवस को शौर्य दिवस मनाते हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कलेक्ट्रेट स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थित शहीद स्मारक में प्रभारी डीएम ने देश की सुरक्षा की खातिर शहीद हुए कारगिल शहीदों को पुष्प चढ़ाकर नमन किया गया। प्रभारी डीएम/सीडीओ अभिषेक कुमार ने एडीएम संजय कुमार सिंह संग जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम हुआ, प्रभारी डीएम अभिषेक कुमार ने कारगिल युद्ध में शामिल पराक्रमी 05 पूर्व सैनिकों (ऑनरी कैप्टन अकरम खान, ऑनरी लेफ्टीनेंट प्रेम कुमार, सुबेदार लखविंदर सिंह, नायक संदीप कुमार और नायक खगेश्वर प्रसाद) को शील्ड एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया।

प्रभारी डीएम अभिषेक कुमार ने कहा कि आज का दिन सिर्फ जीत को याद करने का नहीं है, बल्कि सेना के उन जवानों की वीरता, शौर्य और अदम्य साहस को याद करने का दिन है जिनके सजदे में देशवासियों का सिर हमेशा से झुकता आया है। आज पूरी देश करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतो को याद कर रहा है। डीएम ने कारगिल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कारगिल युद्ध में जवानों की योगदान को रेखांकित किया। एनसीसी कैडेट्स सेना के शौर्य को जानने के लिए उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ें। पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को कोई असुविधा न हो इसका पूरी अफसर की टीम की ओर से हर संभव प्रयास करेंगे। एडीएम ने कहा कि कारगिल जैसा कठिन युद्ध होने के बाद भी देश के सैनिकों ने बहादुरी को परिचय देते हुए देश की सरहदों को दुश्मनों से मुक्त करवाया।

पुरानी पेंशन व्यवस्था अब मुमकिन नहीं: वित्त सचिव सोमनाथन

नई दिल्ली। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है और इसे लाना देश के उन नागिरकों के लिए नुकसानदेह होगा, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) को लेकर कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से कुछ सार्थक बातचीत हुई है। सोमनाथन ने कहा कि सरकार देश में युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से उन्हें कंपनियों में प्रशिक्षण देने की सुविधा के अलावा 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को आधुनिक रूप भी देगी।

सोमनाथन ने पीटीआई-भाषा से विशेष बातचीत में कहा, एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने इस बारे में कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से बातचीत की है। इसमें कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की कुछ चिंताएं हैं। पहला, उनका कहना है कि यह नई योजना है। एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा है, हमें उतार-चढ़ाव नहीं चाहिए। उनका कहना है कि यह स्पष्ट हो कि कितनी पेंशन मिलेगी। दूसरा, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जो भी पेंशन मिले उसमें महंगाई से निपटने का भी कुछ प्रावधान यानी डीए (महंगाई भत्ता) जैसी कोई व्यवस्था चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पेंशन का वास्तविक मूल्य घटता जाएगा। तीसरा, अगर किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है, उसके लिए कुछ न्यूनतम पेंशन तय की जाए। ए ऐसे मामले हैं, जिस पर हमें निर्णय लेना है। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन लाना देश के उन नागिरकों के लिए नुकसानदेह होगा, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं।

वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जरूरत के हिसाब से बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था।

एक सवाल के जवाब में सोमनाथन ने कहा, बजट में महत्वपूर्ण रोजगार पर जोर देना है। एक तरफ जहां वित्तीय सहायता के जरिए रोजगार सृजन पर जोर है वहीं दूसरी तरफ रोजगार गहन क्षेत्र एमएसएमई और कौशल विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। कौशल विकास के तहत हम देश में युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से उन्हें कंपनियों में प्रशिक्षण देने की सुविधा के अलावा 1,000 आईटीआई को आधुनिक बनाएंगे। कौशल विकास के तहत केंद्र, राज्य और उद्योग के सहयोग से आईटीआई को आधुनिक रूप दिया जाएगा। उद्योग में जो आधुनिक मशीनरी, कामकाज का तरीका है उसे आईटीआई में शामिल किया जाएगा। अच्छे प्रशिक्षकों को भी जोड़ा जाएगा। इसका मकसद बेहतर प्रशिक्षण देना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह मंगलवार को पेश बजट में संगठित क्षेत्र में आने वाले नए कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के जरिए तीन योजनाओं की घोषणा की। रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गईं इन योजनाओं के लिए कुल 1.07 लाख करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। इससे अगले पांच साल में 2.90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक करोड़ युवाओं को कंपनियों में प्रशिक्षण और 20 लाख को आईआईटी में प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की गई है।

बजट में नई पीढ़ी के सुधारों और राज्यों के सहयोग से जुड़े सवाल के जवाब में वित्त सचिव ने कहा, सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। राजकोषीय उपायों के जरिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा में खाद्य मंहगाई को मौद्रिक नीति से अलग करने के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथन ने कहा, यह सोचने वाली बात है। अर्थशास्त्रियों की अलग-अलग राय हैं। इस पर चर्चा की जा सकती है। इसी सप्ताह पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि खाद्य पदार्थों को छोड़कर, महंगाई का लक्ष्य तय करने पर विचार किया जाना चाहिए। प्राय: खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें मांग के बजाय आपूर्ति की समस्या के कारण होती हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर विचार करता है। खाद्य महंगाई ऊंची होने से नीतिगत दर में पिछले साल अप्रैल से कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में सोमनाथन ने कहा, बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। मुझे नहीं लगता बहुत लोग इससे नाराज हैं। कुछ हो सकते हैं। हर बजट में कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, इसमें भी वही हैं। इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में विकसित भारत के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ पूंजीगत निवेश और राजकोषीय सूझ-बूझ के साथ नवोन्मेष, अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए कदम उठाए गए हैं।

धनखड़ ने कार्यस्थगन प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों को लिया आड़े हाथ

भाषा। नई दिल्ली

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराए जाने पर जोर दिए जाने के कारण उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सभापति द्वारा इस बारे में स्पष्ट व्यवस्था दिए जाने के बावजूद आसन पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद शून्यकाल में सभापति धनखड़ ने कहा कि उन्हें आज भाजपा सदस्य ईरण्ण कडाडी, सुधांशु त्रिवेदी, नरेश बंसल और बृजलाल के नियम 267 के तहत चार नोटिस मिले हैं। यह नोटिस कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति कार्पोरेशन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मिले हैं।

उन्होंने कहा कि यह सभी नोटिस नियम 267 के बारे में उनके द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों की स्पष्ट अनदेखी है। सभापति ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सदन में स्पष्ट व्यवस्था दी थी और उसके बाद पिछले दो दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव के कोई नोटिस नहीं आए।

धनखड़ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य कडाडी ने एक ऐसे मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया जिसे वह शून्यकाल में पहले ही उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुद्दा सदस्यों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, फौरी महत्व का हो सकता है किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे नियम 267 के तहत सदन में उठाए। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा शोरशराबा करने के बीच सभापति ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू को बोलने का अवसर दिया। रीजीजू ने कहा कि यद्यपि सभापति ने नियम 267 के नोटिसों के बारे में स्पष्ट व्यवस्था दी है किंतु यह एक अत्यंत महत्व का विषय जिससे कुछ सदस्य आंदोलित हैं और इसीलिए उन्होंने यह नोटिस दिया।

सभापति ने रीजीजू को टोकते हुए कहा कि वह नोटिस पर न बोलें क्योंकि ठीक इसी तरह उन्होंने पूर्व में सदन में नेता प्रतिपक्ष को भी इसी कारण नहीं बोलने दिया था। इसके उपरांत सत्ता पक्ष के सदस्य शांत होकर बैठ गए तथा विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से शून्यकाल में लोक महत्व के विषय उठाने शुरू कर दिए। सभापति ने बाद में शून्यकाल के दौरान कडाडी को कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। विपक्ष, खासकर कांग्रेस के सदस्यों ने इसका जोरदार विरोध किया। विरोध और हंगामे के बीच कडाडी ने कन्नड में अपनी बात रखी।

भाजपा नेता प्रभात झा का गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में निधन

गुरुग्राम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का शुक्रवार की सुबह 5 बजे यहां मेदांता मेडिसिटी में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे और कई दिन से बीमार चल रहे थे। उनकी तबियत में कुछ खास सुधार नहीं हो पाया। बिहार के दरभंगा जिला के गांव हरिहरपुर में प्रभात झा का जन्म 4 जून 1957 को हुआ था। बाद में वे वे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के गवालियर में आकर रहने लगे थे। वे भाजपा के मुखपत्र कमल संदेश के संपादक भी रहे। कई पुस्तकों की उन्होंने रचना की। रंजना झा से उनका विवाह हुआ था। उनके दो बेटे तुष्मुल झा व अयत्न झा हैं। प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। बाद में पार्टी ने राज्यसभा सांसद भी बनाया। प्रभात झा पेशे से एक पत्रकार थे। पत्रकारिता के बाद उन्होंने राजनीति में किस्मत आजमाई।

पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे। परिजनों की ओर से जानकारी दी गई कि पहले उनका भोपाल के बंसल अस्पताल में इलाज करवाया था। वहां दो दिन रखा गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। दो दिन बार एयरलिफ्ट करके उन्हें गुरुग्राम मेदांता मेडिसिटी में लाया गया। उनके बेटे अयत्न ने निधन की जानकारी सांझा की। साथ ही कहा कि अंतिम संस्कार ग्वालियर या पैतृक गांव कोरियाही, सीतामढ़ी (बिहार) में होगा। उनके निधन पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

मानसून सत्र के अंतिम दिन आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से बहिर्गमन

भाषा। पटना

बिहार विधानसभा में शुक्रवार को राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को लेकर पेश एक निजी विधेयक पर मतदान कराने की मांग अस्वीकार किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को निजी विधेयक के जरिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा-माले) के विधायक अजीत कुमार सिंह ने आरक्षण में संशोधन को लेकर पारित दो कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाले की मांग की। इन दोंनों संशोधित कानूनों में वंचित वर्गों के लिए कोटा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया था।

बिहार विधानसभा परिसर में बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक भाई वीरेंद्र ने निजी विधेयक पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होने की स्थिति में मतदान का प्रावधान होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि मत विभाजन की विपक्ष की मांग को अध्यक्ष ने सरकार के इशारे पर खारिज कर दिया।

राजद विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में साझेदार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), दलितों के आरक्षण का विरोध करती रही है। विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भाजपा से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी गोदी में बैठकर किलकारी भर रहे हैं।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाल पिछली महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना कराया था जिसके मुताबिक राज्य में पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासियों की कुल आबादी में हिस्सेदारी करीब दो तिहाई है। इसके बाद तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने इन वर्गों का आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया था।

इन आरक्षण कानूनों को नौवीं अनुसूची में रखे जाने से ए न्यायिक समीक्षा से मुक्त हो जाएंगे और राज्य सरकार की ओर से इसके लिए अनुरोध केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के समक्ष लंबित है। इस बीच, पटना उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण में की बढ़ोतरी को खारिज कर दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को दिन भर की कार्यवाही समाप्त होने पर दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

बिहार विधानसभा का सत्र स्थगित किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, विपक्ष उस व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है जो स्टेशन पर देर से पहुंचता है और ट्रेन छूटने के बाद ट्रेन के पीछे भागता है।

उन्होंने आरोप लगाया, वे हताश हैं कि जाति सर्वेक्षण और आरक्षण में बढ़ोतरी का श्रेय मुख्यमंत्री को मिल रहा है। वे कुछ सुर्खियां बटोरना चाहते थे। जब केंद्र से इन्हें नौवीं अनुसूची में डाले जाने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है, तो इस मुद्दे को फिर से उठाना बेतुका है। चौधरी ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद संशोधित आरक्षण कानून प्रभावी नहीं रह गए हैं। पुराने कानून जिसके तहत आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है, लागू रहेंगे। यह एक तकनीकी बात है जिसे विपक्ष को समझना चाहिए। बिहार विधानमंडल के पांच दिवसीय मानसून सत्र के दौरान कुल मिलाकर सात विधेयक पारित किए गए जिनमें से दो का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक और अन्य गड़बड़ियों को रोकना है।

घोटालों और धन की हेराफेरी कर कर्नाटक को दिवालियापन की ओर धकेल रही कांग्रेस: भाजपा

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए घोटालों और धन की हेराफेरी कर राज्य को दिवालियापन की ओर धकेल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की राज्य में दो कथित घोटालों में संलिप्तता का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इन मामलों में शामिल कुछ लोगों को बचाने के लिए भाजपा सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में मुद्दा नहीं उठाने दिया। राज्यसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान उस समय हंगामा हुआ जब सभापति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार से संबंधित एक मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन के सूचीबद्ध कामकाज को निलंबित करने के भाजपा सदस्यों के नोटिस को खारिज कर दिया। धनखड़ ने हालांकि भाजपा के एक सदस्य को शून्यकाल के दौरान सदन में मामला उठाने की अनुमति दी। लोकसभा में झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने संबंधी टिप्पणी और कर्नाटक सरकार के एक मंत्री से जुड़े कथित घोटालों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के बीच कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में जोशी ने कहा, कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है लेकिन अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, वहां उचित सड़कें नहीं हैं। इस बार भारी बारिश के कारण कई मकान ढह गए और पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर गया, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी। धारवाड़ के सांसद ने दावा किया कि राज्य परिवहन की बसें इसलिए खड़ी हैं कि उन्हें चलाने के लिए डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जोशी ने कहा, कांग्रेस के शासन में कर्नाटक में दो-तीन घोटाले हुए और मुख्यमंत्री इनमें से दो घोटालों में सीधे तौर पर संलिप्त हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रगतिशील और फलते-फूलते राज्य कर्नाटक को कांग्रेस सरकार दिवालिया होने की ओर धकेल रही है और राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल गारंटी (कांग्रेस के चुनावी वादे) को लागू करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सदस्यों ने भाजपा सांसदों को शुक्रवार को संसद में मुद्दे नहीं उठाने दिए क्योंकि कर्नाटक की मौजूदा स्थिति के लिए पार्टी आलाकमान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है। यही कारण है कि उन्होंने भाजपा सदस्यों को राज्यसभा में यह मुद्दा नहीं उठाने दिया। लोकसभा में उन्होंने हंगामा किया। इसका मतलब है कि कांग्रेस आलाकमान की भी इसमें (घोटालों में) हिस्सेदारी थी।

भाजपा ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े कथित घोटालों में सिद्धारमैया की संलिप्तता का दावा करते हुए कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विवादास्पद योजना में लेआउट बनाने के लिए अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वाले को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने की परिकल्पना की गई है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में कर्नाटक में भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति से जुड़े कोष का तथाकथित गारंटी के लिए इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार के माध्यम से राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों के लिए सबसे वंचित वर्ग के उत्थान से जुड़ी निधियों का उपयोग एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और दर्दनाक मुद्दा है। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा करने का आरोप लगाया।

यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी सूरज रेवन्ना ने कहा, सच्चाई 15-20 दिन में सामने आ जाएगी

मैसुरु (भाषा)। कुछ पुरुषों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे और जमानत पर बाहर आए जनता दल (सेक्युलर) के विधान पार्षद सूरज रेवन्ना ने शुक्रवार को कहा कि 15 से 20 दिन में उन सभी लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा जो उनके और उनके परिवार के खिलाफ साजिश का हिस्सा थे। रेवन्ना ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना ने मैसुरु में देवी चामुंडेश्वरी की पूजा करने के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसलिए हम सभी इतने आश्वस्त हैं। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। समय इसका जवाब देगा। सूरज ने कहा, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सच्चाई लंबे समय तक छिप नहीं सकती। इस साजिश में शामिल सभी लोग बेनकाब होंगे। बस 15 से 20 दिन इंतजार कीजिए। चामुंडी हिल्स की अपनी यात्रा के बारे में जद (एस) विधान पार्षद ने कहा कि यह एक पारिवारिक परंपरा है कि हर साल वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ देवी की पूजा करने के लिए चामुंडेश्वरी मंदिर जाते हैं। सूरज रेवन्ना को यौन उत्पीड़न मामले में दो दिन पहले ही जमानत पर रिहा किया गया था। सूरज को जद (एस) कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। सूरज के छोटे भाई प्रज्वल रेवन्ना पर भी कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है और वह जेल में हैं।

स्वर्ण उद्योग की मांग एक राष्ट्र, एक दर, पूर्वी भारत से होगी शुरुआत

भाषा। कोलकाता

स्वर्ण आभूषण उद्योग एक राष्ट्र, एक दर नीति की वकालत कर रहा है, जिसकी शुरुआत अगस्त से पूर्वी भारत के लिए समान दर लागू करने के साथ की जाएगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। स्वर्ण शिल्प बचाओ समिति के अध्यक्ष समर कुमार डे ने कहा कि सभी हितधारकों ने देश भर में एक समान सोने की दर के विचार में रुचि दिखाई है।

डे ने कहा, हम अगस्त से बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एकल दर की शुरुआत करेंगे। इस पहल में हमने सर्राफा विक्रेताओं को भी शामिल कर लिया है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा, इसका मकसद सभी हितधारकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना और मूल्यह्रास को रोकना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था। उद्योग जगत के लोगों ने कहा कि शुल्क में भारी कटौती से अवैध आयात को खत्म करने में मदद मिलेगी।

हीरा आयातक सनी ढोलकिया ने कहा, कुल 950 टन आयात में से 100 टन सोने की तस्करी किए जाने का अनुमान है। हालांकि, उद्योग सूत्रों ने बताया कि इस बात को लेकर चिंता है कि क्या सरकार के पास सोने से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में कोई अन्य योजना है। जीजेसी ने जीएसटी परिषद से आभूषणों पर कर की दर मौजूदा तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने की अपील की है।

पांच वर्ष से कम आयु के 36 प्रतिशत बच्चे बौने: महिला एवं बाल विकास मंत्री

भाषा। नई दिल्ली

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 0-5 वर्ष आयुवर्ग के लगभग 17 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले हैं, जबकि 36 प्रतिशत बच्चे बौने और छह प्रतिशत कमजोर (शक्तिक्षीण) हैं। शून्य से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में बौनापन, शक्तिक्षीणता और कम वजन कुपोषण के मुख्य संकेतक हैं। बौनापन से तात्पर्य उन बच्चों से है जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं। ऐसा आमतौर पर दीर्घकालिक कुपोषण के कारण होता है।

शक्तिक्षीण बच्चों का तात्पर्य उन बच्चों से है, जो अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत पतले हैं, जो गंभीर रूप से कम वजन के कारण तीव्र कुपोषण का संकेत देते हैं। ऐसे बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है, जिसमें बौनापन और शक्तिक्षीणता दोनों शामिल हैं और यह दीर्घकालिक या तीव्र कुपोषण या दोनों को दर्शाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जून 2024 के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, छह वर्ष से कम उम्र के लगभग 8.57 करोड़ बच्चों की लंबाई मापी गई, जिनमें से 35 प्रतिशत बौने पाए गए वहीं 17 प्रतिशत कम वजन वाले और पांच वर्ष से कम उम्र के छह प्रतिशत बच्चे शक्तिक्षीण पाए गए।

उन्होंने राज्यवार आंकड़े भी साझा किए, जिसके अनुसार बौनेपन की सर्वाधिक 46.36 प्रतिशत दर उत्तर प्रदेश में है, जिसके बाद लक्षद्वीप में यह दर 46.31 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बौनेपन की दरें क्रमश: 44.59 प्रतिशत और 41.61 प्रतिशत दर्ज की गई हैं। बिहार और गुजरात में बच्चों में शक्तिक्षीणता की दर क्रमश: 9.81 प्रतिशत और 9.16 प्रतिशत है। कम वजन वाले बच्चों के मामले में, मध्य प्रदेश 26.21 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है, इसके बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव 26.41 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

पेज 1 का शेष

ओलंपिक...

कोरी ग्रेंगर नाम के एक यात्री ने कहा, उनके पास यात्रियों के लिए और अधिक जानकारी होनी चाहिए, खासकर तब, जब यह एक दुर्भावनापूर्ण हमला है। फ्रांस की राष्ट्रीय रेल कंपनी एसएनसीएफ ने इन घटनाओं को सुनियोजित हमला करार दिया। इसने कहा कि हमलों के कारण इंग्लिश चैनल के रास्ते लंदन, बेल्जियम और पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी फ्रांस तक संचालित की जाने वाली कई ट्रेन का परिचालन ठप पड़ गया। सरकारी अधिकारियों ने पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले हुई इन घटनाओं की निंदा की। हालांकि, इनका ओलंपिक खेलों से संबंध होने के तत्काल कोई संकेत नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय पुलिस ने कहा कि अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं कि रेल लाइनों पर परिचालन क्यों प्रभावित हुआ। इस बीच, फ्रांसीसी मीडिया ने व्यस्त पश्चिमी मार्ग के एक स्टेशन पर भीषण आगजनी की खबर दी है। खेल मंत्री एमेली औडिया-कास्टेरा ने कहा कि अधिकारी यात्रियों और एथलीट पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रहे हैं तथा ओलंपिक खेलों के प्रतिस्पर्धा स्थलों तक सभी प्रतिनिधिमंडलों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पाक ने...

के लिए युद्ध स्मारक नहीं बनाया, सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को पर्याप्त बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराई और अपने पास रखा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ लद्दाख के उपराज्यपाल, ब्रिगेडियर (डॉ.) बी डी शर्मा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान और तीनों सशस्त्र बलों के सेना प्रमुख उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने गौरव गाथा सुनी- एनसीओ द्वारा कारगिल युद्ध पर ब्रीफिंग और अमर संस्मरण- हट ऑफ रिमेंबरेंस का दौरा किया। उन्होंने वीरभूमि का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअली लद्दाख में शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट का पहला विस्फोट भी देखा।

कांवड़ मार्ग...

कहा कि उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और उनका कहना है कि संबंधित निर्देश कानून के तहत अनिवार्य हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई की जाए, अन्यथा यह मुद्दा निरर्थक हो जाएगा। सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ होती है, खासकर श्रावण के महीने में। उन्होंने कहा, हमें एकपक्षीय आदेश का सामना करना पड़ा और बिना सुनवाई के आदेश पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश केंद्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि भोजनालयों और दुकानों को नियंत्रित करने वाला कोई कानून है तो राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में इसे लागू करना चाहिए। न्यायमूर्ति रॉय ने रोहतगी से कहा, कानून को पूरे राज्य में लागू किया जाए, न कि केवल कुछ क्षेत्रों में। कृपया एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें दिखाया जाए कि कानून को पूरे राज्य में लागू किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यदि नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने संबंधी यह कानून पिछले 60 वर्षों से लागू नहीं किया गया है, तो इस मुद्दे को समय आने पर उठाया जा सकता है और निर्देश लागू किए बिना यात्रा जारी रहने दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब उन्हें कल (बृहस्पतिवार) रात साढ़े दस बजे दिया गया और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने कहा कि राज्य ने कांवड़ यात्रा के संबंध में कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया है और सरकार केवल उस कानून को लागू कर रही है, जिसके तहत सभी त्योहारों के दौरान भोजनालयों के नाम का खुलासा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा एक वार्षिक तीर्थयात्रा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और किसी भी शरारत से बचने के लिए राज्य को कानून लागू करने की जरूरत है। सेठी ने पीठ से आग्रह किया कि राज्य को दो कानूनों को लागू करने के लिए कार्वाई की अनुमति दी जाए, जिसके तहत दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का अंतरिम आदेश उन कानूनों को लागू करने में बाधा बन रहा है। उन्होंने जिन दो कानूनों का उल्लेख किया वे हैं: खाद्य सुरक्षा और मानक (पंजीकरण और लाइसेंसिंग) विनियम, 2011 (एक केंद्रीय कानून) और उत्तराखंड पंचायती राज उपनियम (एक राज्य कानून)। सेठी ने कहा, अगर कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया तो हमें कानून-व्यवस्था की समस्या की आशंका है। पीठ ने हालांकि ऐसा कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट...

लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने मार्च में शीर्ष अदालत का रुख किया था और आरोप लगाया था कि विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया था और ये अब भी मंजूरी के लिए लंबित हैं। पश्चिम बंगाल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राज्यपाल आठ विधेयकों पर मंजूरी नहीं दे रहे हैं। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने कहा , यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

क्रिकेट...

डालते हुए 10 रन देकर तीन विकेट चटकाए। उन्होंने बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को झकझोरा तो वहीं राधा ने मध्यक्रम के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाया। बांग्लादेश के लिए कप्तान निगार सुल्ताना ने 51 गेंद में 32 जबकि शोर्ना अख्तर ने नाबाद 19 रन का योगदान दिया। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन रेणुका ने पहले ओवर में ही छक्का खाने के बाद दिलारा अख्तर (06) को चलता किया। दिलारा के एक और बड़ा शॉट खेला लेकिन यह डीप मिडविकेट पर खड़ी उमा छेत्री को पार करने के लिए काफी नहीं था। उन्होंने अपने अगले दो ओवरों में इश्मा तंजीम (08) और मुर्शिदा खातून (04) को चलता किया जिससे पावरप्ले में बांग्लादेश की टीम तीन विकेट पर 25 रन ही बना सकी। कप्तान सुल्ताना ने एक छोर से पारी को संभालने की कोशिश की। भारतीय गेंदबाजों ने सातवें से 10वें ओवर के बीच सात रन खर्च किए और इस दौरान राधा ने रूमाना अहमद (01) को आउट कर शिकंजा और कस दिया। भारतीय स्पिनरों की सटीक लाइन लेंथ का बांग्लादेश के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। गत चैम्पियन भारत का क्षेत्ररक्षण में काफी सुधार दिखा। शेफाली ने पूजा वस्त्राकर की गेंद पर राबिया खान (01) का डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। दीप्ति की गेंद पर रितु मोनी (05) को विकेटकीपर रिचा घोष ने स्टंप किया।सुल्ताना को इसके बाद शोर्ना के रूप में अच्छा साथ मिला और दोनों ने 35 गेंद में 36 रन की साझेदारी कर टीम को कुछ हद तक संघर्ष करने लायक स्कोर तक पहुंचाया। राधा ने दीप्ति के हाथों कैच कराकर सुल्ताना को पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश की कप्तान टूर्नामेंट में पहली बार आउट हुई। उन्होंने 51 गेंद की पारी में दो चौके लगाए। शोर्ना ने भी 18 गेंद की नाबाद पारी में दो चौके लगाए।

असम...

लेकिन केवल 30 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और असम राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग के सलाहकार और पर्यटक गाइड ट्रेनर रंजन के बरुआ ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में चराइदेव मोइदम्स को शामिल किए जाने की सराहना करते हुए इसे असम और उससे आगे के लोगों के लिए बेहद गर्व का क्षण बताया। उन्होंने टिप्पणी की, ये उल्लेखनीय स्थल अहोम राजवंश की विरासत की भव्यता का प्रतीक हैं और मिस्र के पिरामिडों के समान एक वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़े हैं। बरुआ ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या इसी तरह के संस्थानों द्वारा आगे की खोज से अहोम राजवंश की समृद्ध विरासत में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि का पता चल सकता है, जिससे इस ऐतिहासिक खजाने के बारे में हमारी समझ समृद्ध होगी।ताई-अहोम 13वीं शताब्दी में वर्तमान असम में चले गए और उन्होंने चराइदेव को अपनी पहली राजधानी और शाही क़ब्रिस्तान के लिए स्थान के रूप में चुना। उन्होंने पूर्वी भारत में पटकाई पहाड़ियों पर पहली राजधानी स्थापित की और इसका नाम चराइदेव रखा, जिसका उनकी भाषा में अर्थ है पहाड़ के ऊपर एक चमकदार शहर। भले ही कबीले शहरों में चले गए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए दफन स्थल को राजघरानों की दिवंगत आत्माओं के लिए सबसे पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता था।यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार, इस स्थल पर इन गुंबददार टीलों की कब्रगाहों की सबसे बड़ी सघनता है।

मध्य प्रदेश सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर कोटा लागू करेगी:मुख्यमंत्री

भाषा। भोपाल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी। उन्होंने यह घोषणा करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ पर की।अग्निवीर, अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में चार साल के लिए सैनिकों की तैनाती की जाती है। यादव ने संवाददाताओं से कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है'' उन्होंने कहा, ''हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की भावनाओं के साथ चलेंगे'' इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण है और विपक्ष पर सशस्त्र बलों में औसत आयु को युवा बनाए रखने के उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया पर राजनीति करने का आरोप लगाया ।करगिल युद्ध में विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए द्रास में कारगिल विजय दिवस पर अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि पेंशन राशि बचाने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है।उन्होंने कहा, योजना शुरू की गई है।उन्होंने कहा, अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युवा बनाना है...अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को लगातार युद्ध के लिए फिट रखना है।

छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस और वनरक्षक भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस आरक्षक, वन रक्षक और अन्य पदों की भर्ती में राज्य के अग्निवीरों को आरक्षण देगी। विधानसभा परिसर में संवाददताओं से बात करते हुए साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तब छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। साय ने कहा, अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश हमारी सरकार शीघ्र ही जारी करने जा रही है।

आईटीबीपी के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे अग्निवीर: महानिदेशक

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रक्षा के लिए तैनात आईटीबीपी के लिए अग्निवीर बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह बात केंद्रीय बल के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कही। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी) राहुल रसगोत्रा ने गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि इन ''अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुशासितै सैनिकों की भर्ती के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जो सेना से सीमा सुरक्षा पुलिस बल में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जैसा कि ज्ञात है, आईटीबीपी और सेना के जवान भारत-चीन सीमा की रक्षा करते हैं और इसलिए ''ए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीर, सीमा सुरक्षा पुलिस बल के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आईटीबीपी महानिदेशक ने कहा कि सीमा सुरक्षा पुलिस बल ''का मानना है कि अग्निवीरों के शामिल होने से आईटीबीपी को एक नई ऊर्जा मिलेगी और उसे उनसे लाभ होगा। रसगोत्रा ने कहा कि अग्निवीरों को शामिल करने के लिए आईटीबीपी के भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और वे आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब सेना, नौसेना और वायुसेना में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। सरकार ने सेना के तीनों अंगों में औसत आयु वर्ग को युवा रखने के उद्देश्य से 2022 में अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस योजना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को अगले 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि चार साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा। लगभग 90,000 कर्मियों वाली आईटीबीपी को मुख्य रूप से चीन के साथ लगती 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रखवाली करने के अलावा कई तरह की आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी भी निभानी होती है।

उच्चतम न्यायालय ने असम के निरुद्ध केंद्र में सुविधाओ की कमी को लेकर चिंता जताई

नई दिल्ली। (भाषा) असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों के लिए बनाए गए एक निरुद्ध केंद्र की दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वहां पर्याप्त जल आपूर्ति, उचित स्वच्छता और पर्याप्त शौचालय सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाओं की कमी है। न्यायालय ने कहा कि उसने असम के मटिया स्थित निरुद्ध (डिटेंशन) केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, हमने पाया है कि सुविधाओं का अभाव हैं, यहां पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं है, उचित साफ-सफाई नहीं है, पर्याप्त शौचालय सुविधाएं नहीं हैं। पीठ विदेशी घोषित किए गए लोगों के निर्वासन और असम में निरुद्ध केंद्रों में प्रदान की गई सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में भोजन और चिकित्सा सहायता की उपलब्धता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। न्यायालय ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि वह केन्द्र में आपूर्ति किए जाने वाले भोजन की मात्रा और गुणवत्ता, रसोईघर में साफ-सफाई, तथा चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बार और वहां का दौरा करें।

आयकर विभाग ने अचल संपत्ति पर एलटीसीजी गणना को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। (भाषा) आयकर विभाग ने कहा है कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की गणना के उद्देश्य से वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की लागत एक अप्रैल 2001 तक उचित बाजार मूल्य (एफएमवी, स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) या भूमि या भवन की वास्तविक लागत होगी।

सरकार ने मंगलवार को आम बजट में अचल संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने के साथ ही अप्रैल, 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों के मुद्रास्फीति समायोजन (इंडेक्सेशन) से जुड़े लाभ को हटाने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के मामले में, उचित बाजार मूल्यांकन (स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) को मुद्रास्फीति समायोजन मूल्य निर्धारित करने के लिए आधार बनाया जा सकता है। मुद्रास्फीति समायोजन के बाद मूल्य को एलटीसीजी की गणना के लिए बिक्री मूल्य से घटा दिया जाएगा और फिर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए एक अप्रैल 2001 तक अधिग्रहण की लागत के बारे में मुद्दा उठाया गया है। विभाग ने कहा है कि एक अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों (भूमि या भवन या दोनों) के लिए एक अप्रैल 2001 के मूल्य के हिसाब से खरीद लागत, या एक अप्रैल 2001 को ऐसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य (जहां भी उपलब्ध हो, स्टांप शुल्क मूल्य से अधिक नहीं) उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगी। विभाग ने बृहस्पतिवार रात को जारी सूचना में कहा, करदाता दोनों में से एक विकल्प चुन सकते हैं। आयकर विभाग ने एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश है कि 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के मामले में पूंजीगत लाभ कर की गणना किस तरह की जाएगी। उसने एक संपत्ति का उदाहरण दिया, जिसकी 1990 में अधिग्रहण की लागत पांच लाख रुपए थी और एक अप्रैल 2001 को इसका स्टांप शुल्क मूल्य 10 लाख रुपए और एफएमवी 12 लाख रुपए था। यदि इसे 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद एक करोड़ रुपए में बेचा जाता है, तो एक अप्रैल 2001 तक अधिग्रहण की लागत 10 लाख रुपए (स्टाम्प ड्यूटी या एफएमवी में से जो भी कम हो) होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में इस अधिग्रहण की मुद्रास्फीति समायोजन लागत 36.3 लाख रुपए (10 लाख रुपए गुणा 363।100) है। 363 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक है। इस सूचकांक को आयकर विभाग अधिसूचित करता है। इस मामले में एलटीसीजी 63.7 लाख रुपए (एक करोड़ रुपए में से 36.3 लाख रुपए घटाकर) बैठता है। इस तरह 20 प्रतिशत की दर पर, ऐसी संपत्तियों के लिए एलटीसीजी कर 12.74 लाख रुपए बनेगा। वहीं नई व्यवस्था में एलटीसीजी 90 लाख रुपए (एक करोड़ में से लागत 10 लाख रुपए घटाने) आंका जाएगा और इस पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 12.5 प्रतिशत हिसाब से 11.25 लाख करोड़ रुपए बैठेगा।

भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण संगठन एडीपीसी की अध्यक्षता संभाली

नई दिल्ली। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर (एडीपीसी) की अध्यक्षता संभाल ली है। यह संगठन एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्रियान्वयन और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य और विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने थाइलैंड के बैंकॉक में बृहस्पतिवार को वर्ष 2024-25 के लिए चीन से एडीपीसी की अध्यक्षता संभाली ।बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के क्षेत्र में भारत वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है। भारत ने इस दिशा में कई वैश्विक पहल की हैं, जिनमें आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना जैसी पहल प्रमुख हैं। बयान के मुताबिक, भारत और आठ पड़ोसी देश बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका और थाईलैंड, एडीपीसी के संस्थापक सदस्य हैं।

राजस्थान : सलूंबर में शिक्षक की तलवार से वार कर हत्या, आरोपी की तलाश जारी

जयपुर। राजस्थान के सलूंबर जिले में बृहस्पतिवार रात 40 साल के एक शिक्षक की तलवार से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बचाव करने आए शिक्षक के पिता को भी तलवार से घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार सलूंबर के अदवास गांव की मेघवाल बस्ती में सिगरेट खरीदने के बहाने दुकान पर आए आरोपी फतेह सिंह ने दुकान के पास खड़े शिक्षक शंकरलाल मेघवाल पर अचानक तलवार से हमला कर दिया। उसने अध्यापक की गर्दन पर वार किया जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जब शंकरलाल के पिता डाल चंद (60) उसे बचाने आए, तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया। उनका अस्पताल में उपचार जारी है। सलूम्बर के पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी मानसिक रूप से परेशान था और उसे संदेह था कि कोविड महामारी के दौरान शिक्षक द्वारा उसे फूल भेंट करने के बाद से उसका व्यवसाय नहीं चल रहा। आरोपी अहमदाबाद में फोटोकॉपी की दुकान चलाता है। उन्होंने बताया कि मृतक शिक्षक के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मुआवजे की मांग के चलते शव का पोस्टमार्टम अभी तक हुआ है। उन्होंने बताया कि मामले में चार पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में आरोपी को तलवार देने वाले भी शामिल हैं। शिक्षक की पत्नी ललिता ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मेरे पति की गर्दन पर वार करके हत्या कर दी गई। जब तक मैं पहुंची, तब तक वे जमीन पर पड़े थे। मेरे ससुर पर भी हमला किया गया। अब मैं क्या करूं? शंकरलाल के छोटे भाई प्रकाश ने कहा, मेरे पिता दुकान पर थे। तभी एक व्यक्ति सिगरेट खरीदने के बहाने आया। सिगरेट जलाने के तुरंत बाद उसने मेरे भाई पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने बीच बचाव करने आए मेरे पिता पर भी हमला किया। उनका हाथ कट गया और शरीर पर कई चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि आरोपी रात में गांव के पास के जंगल में फरार हो गया। पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक एक पुलिस दल को आरोपी की तलाश के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। इस बीच, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से इस पर जवाब देने की मांग की।

राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त

जयपुर (भाषा)। राजस्थान में विधानसभा की पांच सीटों पर उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ को नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे इस पद पर सांसद सीपी जोशी की जगह लेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने अरुण सिंह की जगह सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दो दिन पहले सांसद सीपी जोशी ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद राठौड़ ने एक्स पर लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर भाजपा राजस्थान को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे और डबल इंजन की सरकार में विकास की नई गाथा लिखेंगे। उन्होंने लिखा कि भाजपा राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी जी से शिष्टाचार मुलाकात की। राठौड़ पांच महीने पहले राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। अब पार्टी ने ओबीसी के अपने वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए उन्हें प्रदेश भाजपा की नई जिम्मेदारी सौंपी है। मदन राठौड़ पाली की सुमेरपुर विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। वह 2013 से 2018 तक सरकार के उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं। उनके पास लंबा संगठनात्मक अनुभव है। उन्होंने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कुछ महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। अब प्रदेश भाजपा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मदन राठौड़ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को भाजपा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, नि:संदेह, आपके ऊर्जावान नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन में भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ प्रदेश में सफलता के नवीन मानक स्थापित करेगी।

भाजपा ने राधामोहन दास अग्रवाल को राजस्थान, हरीश द्विवेदी को असम का प्रभारी बनाया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव राधामोहन दास अग्रवाल को राजस्थान के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया। पूर्व लोकसभा सदस्य हरीश द्विवेदी को असम के लिए पार्टी का प्रभारी बनाया गया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन और पूर्व सांसद राजदीप रॉय को क्रमश: तमिलनाडु और त्रिपुरा का प्रभारी नियुक्त किया है। मेनन को फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष विजया रहाटकर राजस्थान में और सुधाकर रेड्डी तमिलनाडु में संगठनात्मक मामलों के सह-प्रभारी होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने बिहार और राजस्थान में भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

भाजपा को महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए : नारायण राणे

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सभी 288 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा राज्य में महायुति सरकार का हिस्सा है। गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल है।राणे ने एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे लगता है कि भाजपा को (विधानसभा की) सभी 288 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री राणे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बृहस्पतिवार को राज्य में चुनाव की तैयारियों पर भाजपा नेताओं के साथ बैठक की थी। शिवसेना सांसद और पार्टी प्रवक्ता नरेश म्हास्के ने राणे की टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी।

हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर मस्जिद, मजारों के आगे लगाए गए पर्दे हटाने का कार्य शुरू

हरिद्वार (भाषा)। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को पर्दों से ढके जाने से शुरू हुए विवाद के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने कुछ घंटों के बाद ही उन्हें उतारना शुरू कर दिया। हालांकि, यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानों के आगे लगाए गए पर्दों को नहीं हटाया गया है। शराब की दुकानों के बाहर भी इस बार पहली बार पर्दे लगाए गए हैं।

हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा की इस वर्ष शुरुआत विवादों के साथ हुई जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबा संचालकों को अपने नाम और पते वाले साइनबोर्ड लगाने का आदेश दिया। इस पर विवाद के बीच मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा जहां इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। अभी यह विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को पर्दों से ढक दिया। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मस्जिद और मजारों को ढका गया। उन्होंने कहा, कोई समस्या न हो, इसे देखते हुए ही कुछ बातो पर रोक लगाई जाती है। कांवड़ मार्ग पर किसी प्रकार की उत्तेजना न हो, इसलिए मस्जिद और मजारों को ढका गया है। ज्वालापुर में आर्यनगर के पास इस्लामनगर की मस्जिद और उंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढक दिया गया। लेकिन इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद प्रशासन ने कुछ ही घंटों में उन्हें उतारने का कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन के निर्देश पर मस्जिदों और मजारों के आगे लगे पर्दे हटाने पंहुचे कांवड़ मेले के एसपीओ (पुलिस की सहायता के लिए तैनात स्वयंसेवक) दानिश अली ने बताया कि पुलिस चौकी से उन्हें पर्दे हटाने का आदेश मिला है और इसलिए वह उन्हें हटाने आए हैं। इससे पहले, कांवड़ यात्रा के दौरान मस्जिदों और मजारों को कभी नहीं ढका नहीं जाता था। ज्वालापुर स्थित मजार के प्रबंधक शकील अहमद ने कहा कि इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं की गई।

पश्चिम बंगाल : भाजपा विधायक ने नया केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की मांग की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की मांग से सहमति जताते हुए भाजपा के एक विधायक ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्होंने पहले भी यह मुद्दा उठाया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के विधायक गौरी शंकर घोष ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने दो अगस्त 2022 को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र भेजकर नया केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की मांग की थी। घोष ने कहा, मैंने केंद्र को मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों के माध्यम से अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी लोगों के बारे में सूचित किया था, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। घोष ने उम्मीद जताई कि लोकसभा में भाजपा के एक सांसद द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद गृह मंत्रालय अब इस मामले को गंभीरता से लेगा। उन्होंने कहा, अब मेरी पार्टी के एक सांसद ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अब इस पर गंभीरता से विचार करेगा। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने भाजपा पर चुनावी असफलताओं के बाद लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने और पश्चिम बंगाल के विभाजन के प्रयास करने का आरोप लगाया। दुबे ने बृहस्पतिवार को मांग की कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, ताकि क्षेत्र में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से उत्पन्न चुनौती से निपटा जा सके।

कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का फैसला किया

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, हमने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का निर्णय लिया है...यह वहां के लोगों की मांग पर किया गया है। राजस्व विभाग इस प्रक्रिया को शुरू करेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए पाटिल ने कहा, केवल जिले का नाम बदलेगा, शेष सभी नाम (तालुकाओं के) वही रहेंगे। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, सिर्फ जिले का नाम बदलेगा, बाकी सब वही रहेगा। राजधानी बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित रामनगर कस्बा बेंगलुरु साउथ जिले का मुख्यालय बना रहेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, रामनगर के लोग ब्रांड बेंगलुरु के अंतर्गत आना चाहते हैं। जिले के लोगों और कुछ प्रमुख हस्तियों की राय है कि वे ब्रांड बेंगलुरु चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या यह निर्णय चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, पाटिल ने कहा, यह चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया, यह वहां के लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर आधारित है। रामनगर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार का गृह जिला है। वह जिले के कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में पहली बार यह प्रस्ताव रखा था।अगस्त 2007 में जब रामनगर जिला बनाया गया था तब केंद्रीय मंत्री और जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के नेता एच डी कुमारस्वामी जद-एस-भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री थे।प्रस्ताव पर कटाक्ष करते हुए कुमारस्वामी ने हाल ही में कहा था कि यदि वह दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस योजना के लागू होने पर वह इसे पलट देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने आरोप लगाया था कि इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य वहां रियल एस्टेट के अवसरों का दोहन करने का है।रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का प्रस्ताव हाल में तब जोर पकड़ गया जब उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस मुद्दे को उठाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा।

भाजपा के साथ गठबंधन फेविकोल से चिपका हुआ है

नई दिल्ली (भाषा)। जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय बजट को विपक्ष द्वारा सरकार बचाओ बजट बताए जाने पर शुक्रवार को पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनकी पार्टी का चुनाव-पूर्व गठबंधन है जो फेविकोल से चिपका हुआ है। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से ऐसी गुगली फेंकी है कि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया है। उन्होंने कहा, यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मोदी जी के संकल्प को दर्शाने वाला बजट है। सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सदन में बजट पर नहीं,

बल्कि नरेन्द्र मोदी जी की आलोचना पर भाषण चल रहा है। उनका कहना था, पूरे विपक्ष की शैली यह दर्शाती है कि इन लोगों को मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है और वो प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी की यह उपलब्धि है कि 60 साल बाद किसी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है।उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, हमारा यह एक परामर्श है कि आप लोग (विपक्ष) सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। ललन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हम इनके साथ थे, ए गठबंधन के अंदर लॉबी चलाते हैं। इस कारण हम लोगों ने इन्हें प्रणाम किया और इधर (भाजपा के साथ) चले आए। उन्होंने कांग्रेस पर लोकसभा में उसकी 99 सीट को लेकर कटाक्ष किया और सांप-सीढ़ी के खेल का जिक्र करते हुए कहा कि इस खेल में 99 पर पहुंचते ही सांप काट लेता है और फिर सीधे शून्य पर पहुंच जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बजट को सरकार बचाओ बजट करार दिए जाने को लेकर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, चाहे हमारे साथ हो या तेलुगु देसम पार्टी के साथ हो, यह चुनाव-पूर्व गठबंधन है। हमारा यह गठबंधन फेविकोल से चिपका हुआ है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के सदन में दिए गए भाषण और सरकार की आलोचना को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, वो उन्हें नहीं दिखाई देता। केंद्रीय मंत्री का कहना था, यह देश का बजट है और प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश का विकास करना चाहते हैं इसलिए विपक्षी सदस्य केवल एक-एक राज्य की बात नहीं करें बल्कि पूरे देश की बात करें।

जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री व अन्य समकक्षों से भेंट की

भाषा। वियनतियाने (लाओस)

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव और ब्रुनेई, न्यूजीलैंड और लाओस के अन्य नेताओं से मुलाकात की और शिक्षा तथा कृषि प्रौद्योगिकी समेत द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जयशंकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) की बैठकों में शामिल होने के लिए लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी में हैं। उन्होंने बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की।

रूसी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने आसियान कार्यक्रम के इतर मुलाकात की। जयशंकर ने ब्रुनेई और न्यूजीलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें कीं और शिक्षा तथा कृषि प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

उन्होंने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष और देश के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स से मिलकर मुझे हमेशा खुशी होती है। शिक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशांत द्वीप समूह और क्रिकेट पर चर्चा हुई।

जयशंकर ने ब्रुनेई के अपने समकक्ष दातो हाजी एरीवान के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने के मौके पर लोगो जारी किया। जयशंकर ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने लाओस के गृह मंत्री विलायवो एनजी बौड्डखम, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मलाइथोंग कोमासिथ, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सन्या प्रसुथ और विशेष दूत अलौंकियो किट्टीखौन से भी मुलाकात की।

जयशंकर ने कहा, हमारी मेजबानी के लिए राजदूत प्रशांत अग्रवाल को धन्यवाद। जयशंकर आसियान-भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) के प्रारूप में आसियान ढांचे के तहत विदेश मंत्रियों की बैठकों में शामिल होने के लिए लाओस की राजधानी में हैं, ताकि इस समूह के साथ भारत के संबंधों को और गहरा किया जा सके। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक पूरा हो रहा है।

डोभाल ने आतंकवाद समेत अन्य मुद्दों से निपटने के लिए बिम्सटेक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया

नेपीता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) देशों से आतंकवाद, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा संगठित अपराध से निपटने में मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डोभाल ने म्यांमा की राजधानी में बिम्सटेक देशों के सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। म्यांमा स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एनएसए ने बिम्सटेक बैठक में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। उन्होंने आतंकवाद , मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी तथा संगठित अपराध से निपटने में सहयोग मजबूत करने, बिम्सटेक कनेक्टिविटी, दूसरे बंदरगाह सम्मेलन के आयोजन और

हिमालई नदी प्रणालियों की जल सुरक्षा पर बात की।

यह बैठक सदस्य देशों के समक्ष आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण पहलों की रणनीति बनाने और समन्वय स्थापित करने के लिए आयोजित की गई है। इससे पहले डोभाल ने बृहस्पतिवार को म्यांमा के अपने समकक्ष एडमिरल मोए आंग से मुलाकात की। इसके अलावा वह अन्य बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग से भी मिले।

डोभाल बृहस्पतिवार को हनोई से यहां पहुंचे थे। हनोई में उन्होंने वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुएन फू ट्रोंग के राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया था। गुएन फू ट्रोंग का 19 जुलाई को निधन हो गया था। बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को आर्थिक विकास, व्यापार और परिवहन, ऊर्जा और आतंकवाद-निरोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जोड़ता है। उद्देश्य सदस्य देशों- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

डोभाल ने एडमिरल मोए आंग को वहां की हिंसा और अस्थिरता के कारण म्यांमा की भारत के साथ लगती सीमा पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की चिंता से अवगत कराया। सेना द्वारा एक फरवरी 2021 को तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा किए जाने के बाद से म्यांमा में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर हिंसक विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। म्यांमा के कई हिस्सों में सेना और प्रतिरोधी बलों के बीच भीषण युद्ध जारी है। प्रतिरोधी बलों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। म्यांमा उग्रवाद प्रभावित नगालैंड और मणिपुर सहित भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।

इमरान खान की पीटीआई पार्टी ने की देशव्यापी आंदोलन की घोषणा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जेल में बंद अपने सभी नेताओं की रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। प्रशासन ने इस घोषणा के बाद पीटीआई समर्थकों के साथ संभावित टकराव से निपटने को लेकर तैयारी की है। दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी ने भी बिजली और अन्य वस्तुओं की ऊंची कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रदर्शन की घोषणा की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान (71) और अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। खान को पिछले साल पांच अगस्त को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा दायर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं। क्रिकेट से राजनीति में आए खान को जमानत मिल गई है या फिर उनकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया।

वह राजधानी में नेशनल प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन करेगी, जबकि जमात-ए-इस्लामी ने संसद भवन के सामने स्थित प्रसिद्ध एफ-चौक पर धरना देने की योजना बनाई है। इस बीच, इस्लामाबाद में पुलिस ने धारा 144 लागू करते हुए संघीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रेड जोन को सील करते हुए प्रवेश निषिद्ध कर दिया है। इस जोन में प्रमुख सरकारी कार्यालय और दूतावास हैं। पुलिस ने फैजाबाद इंटरचेंज पर इस्लामाबाद राजमार्ग को भी आंशिक रूप से बंद कर दिया है, यह रावलपिंडी से इस्लामाबाद के मुख्य प्रवेश बिंदु पर स्थित है। इसके अलावा पंजाब गृह मंत्रालय ने सभी विरोध प्रदर्शनों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रांत में धारा 144 लागू कर दी। पीटीआई ने दावा किया है कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों से पहले उसके पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसने कहा कि पंजाब पुलिस ने रावलपिंडी में पीटीआई नेता राजा बशारत के घर पर छापा मारा। उसने कहा कि कानूनविद जावेद इकबाल समेत दर्जनों लोगों को रहीम यार खान शहर में गिरफ्तार किया गयाहै। पुलिस ने लाहौर में पीटीआई नेता मेहर नईमुल्ला के कैंप कार्यालय पर छापा मारा और उनके पांच मित्रों को गिरफ्तार किया।

नेतन्याहू संबंधों में आई दरार को पाटने के लिए ट्रंप से मुलाकात करेंगे

वाशिंगटन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संबंधों में आई दरार को पाटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से शुक्रवार को मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ओर से इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रमुख इच्छाओं को पूरा करने में अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अधिक कदम उठाए थे। जब 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में नेतन्याहू ने चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डेमोक्रेट जो. बाइडन को बधाई दी तो ट्रंप और नेतन्याहू के संबंधों में दरार आ गई थी। शुक्रवार को, दोनों नेता लगभग चार साल में पहली बार आमने-सामने की मुलाकात करेंगे और इस संभावना पर विमर्श करेंगे कि क्या रिश्ते को सुधारा जा सकता है। दोनों की अपने मतभेदों को दूर करने में रूचि है।

ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। वह इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव में एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। ट्रंप ने 2021 की शुरुआत में नेतन्याहू से नाता तोड़ लिया था। ऐसा तब हुआ जब इजराइली प्रधानमंत्री ट्रंप के झूठे दावे की अनदेखी करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बाइडन को बधाई देने वाले पहले विश्व नेताओं में से एक बन गए। उस समय एक इज़राइली अखबार को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था, नेतन्याहू चुप रह सकते थे। उन्होंने एक भयानक गलती की। नेतन्याहू के साथ अपने अलगाव के बाद ट्रंप ने सार्वजनिक बयानों में खुद को राष्ट्रपति के रूप में इज़राइल के लिए कड़ी मेहनत करने वाले के रूप में चित्रित किया और नेतन्याहू पर वफादारी न निभाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने अन्य मुद्दों पर भी नेतन्याहू की आलोचना की है। ऐसे ही एक उदाहरण में उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमलों से निपटने के लिए नेतन्याहू की तैयारी नहीं थी।

नेतन्याहू ने बुधवार को अमेरिकी संसद में अपने भाषण में बाइडन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद गाजा में इजराइल की कार्वाई के लिए सैन्य और राजनयिक समर्थन जारी रखा है। उन्होंने ट्रंप की भी काफी प्रशंसा की और उनके द्वारा किए गए क्षेत्रीय समझौतों को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप को इजराइल के लिए किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद दिया।

ब्रिटेन ने नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट अनुरोध को चुनौती देने की योजना छोड़ी

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) के अनुरोध में ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस निर्णय से स्टॉर्मर की सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की योजना में अंतर आ गया है। सुनक ने वारंट को चुनौती देने की योजना बनाई थी। आईसीसी ने सरकार को चुनौती दायर करने के लिए शुक्रवार तक की समय सीमा तय की थी।

उत्तरी जापान में बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन सैकड़ों लोग शरण लेने को मजबूर

टोक्यो। उत्तरी जापान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण परिवहन सेवाएं बृहस्पतिवार को बाधित हो गईं तथा सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने यामागाटा और अकिता प्रांत के कई शहरों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इन शहरों में अब तक गर्म हवाएं चलने के कारण उमस भरा मौसम था। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रभावित इलाकों के लोगों से मौसम संबंधी जानकारियों पर लगातार नजर बनाए रखने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, अकिता प्रांत के युजावा शहर में एक व्यक्ति सड़क निर्माण स्थल पर भूस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता हो गया। एजेंसी के मुताबिक, युजावा में बचाव कर्मियों ने नाव की मदद से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से 11 प्रभावितों को सुरक्षित निकाला। पड़ोसी यामागाटा प्रांत में सबसे अधिक प्रभावित युजा और सकाटा कस्बों में बृहस्पतिवार को एक घंटे के भीतर 10 सेंटीमीटर (चार इंच) से अधिक बारिश हुई। क्षेत्र के हजारों लोगों को ऊंचे एवं सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई थी। हालांकि, शरण लेने वाले लोगों की संख्या के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है। पूर्वी जापान रेलवे कंपनी के अनुसार, यामागाटा शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं बृहस्पतिवार को आंशिक रूप से निलंबित कर दी गईं। एजेंसी ने शुक्रवार शाम तक क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर (आठ इंच) अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

चीन में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना से लोगों में नाराजगी

भाषा। बीजिंग

चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तेजी से बढ़ती उम्रदराज आबादी से निपटने के लिए कामकाजी आबादी की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना ने जनता में नाराजगी पैदा कर दी है। वर्तमान ढांचे के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में पुरुष कामगारों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, जबकि महिला कामगारों के लिए यह उनके व्यवसाय के आधार पर 50 या 55 वर्ष है। हाल में संपन्न चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के तीसरे पूर्ण अधिवेशन में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा की गई है जो कि गहराते जनसांख्यिकीय संकट, धीमी वृद्धि और बढ़ते स्थानीय सरकारी ऋण से प्रभावित है। अधिवेशन में सेवानिवृत्ति की आयु को स्वैच्छिक और लचीले तरीके से बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा की गई।

ग्यारह जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की जनसंख्या, जो वर्तमान में 2024 में 1.41 अरब है, 2054 में घटकर 1.21 अरब हो जाएगी और 2100 तक और घटकर 63.3 करोड़ हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया, यह अनुमान लगाया गया है कि चीन, जो वर्तमान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, 2024 और 2054 के बीच जनसंख्या में सबसे बड़ी कमी (20.4 करोड़) का सामना करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन के लिए लंबी अवधि के जनसंख्या अनुमान अधिक अनिश्चित हैं।

चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2023 के अंत तक जनसंख्या और उसकी संरचना के अनुसार, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत (29.69 करोड़) थी, जिसमें से 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या 15.4 प्रतिशत (21.67 करोड़) है। कामकाजी आयु वर्ग, यानी 16 से 60 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या 61.3 प्रतिशत (86.48 करोड़) है। पिछले सप्ताह आयोजित पूर्ण अधिवेशन द्वारा अनुमोदित आधिकारिक दस्तावेज में 2029 तक पूरे किए जाने वाले व्यापक सुधारों के तहत 300 से अधिक नीतिगत उपायों को सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि, सीपीसी ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की योजना को लागू करने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। दस्तावेज के अनुसार, सरकार व्यवस्थित और क्रमिक तरीके से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएगी और उम्रदराज लोगों के लिए विविध नौकरियों का सृजन करने को लेकर सिल्वर इकोनॉमी विकसित करने का प्रयास करेगी।

सिल्वर इकोनॉमी का आशय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत की ऐसी प्रणाली से है जिसका उद्देश्य उम्रदराज लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना और उनके उपभोग, जीवन और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना को लेकर चीनी सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया हुई है, जहां लोगों ने उनकी पेंशन मिलने में देरी की आशंका के चलते असंतोष व्यक्त किया है, युवा कर्मचारियों का कहना है कि यदि उम्रदराज कर्मचारी बने रहेंगे तो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ने से उनके पास कम नौकरियां बचेंगी। लोगों ने सरकार संचालित चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा 2019 में जताए गए एक पूर्वानुमान को भी साझा किया, जिसमें कहा गया था कि बढ़ती चिंताओं के बीच घटते श्रमबल के कारण चीन का सरकारी पेंशन कोष 2035 तक समाप्त हो जाएगा।

नेपाल विमान दुर्घटना में जीवित बचे कैप्टन शाक्य को सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया

भाषा। काठमांडू

नेपाल में एक घातक विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति कैप्टन मनीष राज शाक्य को स्वास्थ्य में सुधार के बाद गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) से सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। शुक्रवार को एक खबर में यह जानकारी सामने आई। इस विमान हादसे में 18 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। सौर्य एयरलाइंस के बॉम्बार्डियर सीआरजे-200 विमान में बुधवार को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आग लग गई। इसमें चालक दल के दो सदस्य, एयरलाइन के तकनीकी कर्मचारी और एक बच्चा और उसकी मां सहित 19 लोग सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन ने उपचार के दौरान दम तोड़ा।

कैप्टन शाक्य (37) को दुर्घटनास्थल से बचा लिया गया। विमान के बाकी हिस्से में आग लगने से कुछ सेकंड पहले ही विमान का कॉकपिट एक मालवाहक कंटेनर से टकराकर अलग हो गया था, जिसके बाद उन्हें बचा लिया गया। द काठमांडू पोस्ट समाचार पत्र की खबर के मुताबिक, कैप्टन शाक्य का काठमांडू मेडिकल कॉलेज (केएमसी) अस्पताल के आईसीयू में इलाज किया जा रहा था। अस्पताल ने कहा कि शाक्य की हालत अब स्थिर है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

केएमसी की निदेशक प्रोफेसर डॉ. मीना थापा के हवाले से खबर में बताया गया कि उनकी (शाक्य) स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के बाद उन्हें अब सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया गया है। थापा ने बताया कि न्यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ शाक्य की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया, उनके (शाक्य के) चेहरे, आंखों, नाक और सिर पर चोटें आईं हैं। इसके अलावा, उनके मेरु दंड (रीढ़ की हड्डी) की एक हड्डी और बाईं ओर की तीन पसलियां टूट गई हैं। खबर में थापा के हवाले से बताया गया, शाक्य की सर्जरी की जाए या नहीं अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केएमसी सूत्रों के अनुसार, आग में नहीं झुलसने के बावजूद कैप्टन शाक्य को कई अंदरूनी चोटें आईं हैं।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्व में इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)
सीआईएन: L10719DL1995PLC277176
रजि. कार्या. 288 बेसमेंट एजीसीआर एन्क्लेव, दिल्ली 110092 भारत
कॉर्पोरेट कार्या. बी-16, द्वितीय तल, सैक्टर-2, नोएडा-201301, भारत
ई-मेल: info@integredindustries.in वेबसाइट: www.integredindustries.in
मोबाइल: +91 9811060171 फोन: 011-45511351 फैक्स: 011-45511351

ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) और ई-वोटिंग सूचना के माध्यम से आयोजित होने वाली 38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") जिसे पहले इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कंपनी') के नाम से जाना जाता था, के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को दोपहर 02:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवाईएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के इच्छुक सदस्य एजीएम सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए वीसी/ओएवीएम सुविधा की गणना की जाएगी। आयोजित एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में की गई मानी जाएगी।

इसके अलावा, प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, 38वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट 26 जुलाई, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट/ कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट और 38वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.integratedindustries.in पर अपलोड कर दी गई है और यह स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक - 2 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, जैसा कि संशोधित है, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा 38वीं एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे ("रिमोट ई-वोटिंग") उल्लिखित तारीखों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके दूर से अपना वोट डाल सकते हैं।

क) दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:
दूरस्थ ई-वोटिंग प्रारंभ : शनिवार, 17 अगस्त, 2024 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति : सोमवार, 19 अगस्त, 2024 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी)
उपर्युक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को तत्काल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
ख) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("इंस्टा पोल") के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मूल्य नहीं डाला है, वे इंस्टा पोल के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकेंगे।
ग) कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।
घ) ई-वोटिंग से संबंधित उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित सूचना और निर्देश ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को भेजे गए हैं। वीटी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए।
ङ) रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ इंस्टा पोल के माध्यम से एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 ("कट-ऑफ तारीख') है। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तारीख को शेयर रखता है, वह एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और सदस्य कंपनी को info@integratedindustries.in पर अनुरोध भी भेज सकते हैं -
च) डीमैट मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टापोल के माध्यम से एजीएम में मतदान का तरीका 38वीं एजीएम की सूचना में दिया गया है-
जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टेलीफोन नंबर 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं।
सुश्री लवलीन गुप्ता (एफसीएस नं. 5287), कार्यरत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.integratedindutries.in पर अपलोड किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

कृते इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्व में इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)
हस्ता/-
(प्रियंका)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 26.07.2024
स्थान: दिल्ली

कमला ने नेतन्याहू से गाजा में युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमास के साथ जल्द युद्धविराम समझौता करने और गाजा में विनाशकारी युद्ध स्थाई रूप से समाप्त करने का आग्रह किया है। फलस्तीनी क्षेत्र में हताहतों की संख्या बढ़ने और मानवीय संकट गहराने के बीच हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस परिसर में हैरिस और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उपराष्ट्रपति ने संवाददाताओं से कहा, इजराइल को अपना बचाव करने का अधिकार है और वह ऐसा किस तरीके से करता है, यह मायने रखता है। पिछले नौ महीनों में गाजा में जो कुछ हुआ है वह विनाशकारी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर देखी जा रहीं हैरिस ने कहा, कई मामलों में दूसरी, तीसरी या चौथी बार विस्थापित होने के बाद सुरक्षा के लिए भाग रहे हताश, भूखे लोगों और मृत बच्चों की तस्वीरें हैं। हम इन त्रासदियों के सामने आंखें नहीं मूंद सकते। मैं चुप नहीं रहूंगी।

हैरिस ने द्वि-राष्ट्र समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इससे पहले बृहस्पतिवार को नेतन्याहू ने राष्ट्रपति जो. बाइडन से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू ने मुलाकात से एक दिन पहले कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को संबोधित करते हुए हमास के खिलाफ पूर्ण जीत का संकल्प जताया। इस दौरान, हजारों फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। युद्ध के नौवें महीने में पहुंचने के साथ नेतन्याहू पर इजराइल-गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। हैरिस ने कहा, मैंने यह कई बार कहा है, लेकिन इसे दोहराना जरूरी है। इजराइल को अपना बचाव करने का अधिकार है और वह ऐसा किस तरीके से करता है, यह मायने रखता है। हमास एक क्रूर आतंकवादी संगठन है। हमास ने सात अक्टूबर को 44 अमेरिकियों सहित 1,200 निर्दोष लोगों की हत्या कर इस युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने कहा, हमास ने यौन हिंसा के भयानक कृत्य किए हैं और 250 लोगों को बंधक बनाया। ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जो गाजा में बंदी बने हुए हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ अपनी बैठक के दौरान गाजा में बड़ी संख्या में निर्दोष आम नागरिकों की मौत होने समेत मानवीय पीड़ा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैंने वहां की भयावह मानवीय स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। वहां 20 लाख से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा और पांच लाख लोग गंभीर स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पिछले नौ महीने में गाजा में जो कुछ हुआ है, वह विनाशकारी है। हैरिस ने कहा कि युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि समझौते के पहले चरण में पूर्ण युद्धविराम होगा, जिसके तहत गाजा के आबादी वाले केंद्रों से इजराइली सेना की वापसी होगी और दूसरे चरण में इजराइली सेना गाजा से पूरी तरह से पीछे हट जाएगी तथा इससे शत्रुता का स्थाई अंत होगा।

उन्होंने कहा, इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है और यह इस तरह से समाप्त होना चाहिए कि इजराइल सुरक्षित हो, सभी बंधकों को रिहा किया जाए, गाजा में फलस्तीनियों की पीड़ा समाप्त हो और फलस्तीनी स्वतंत्रता, गरिमा एवं आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। इस समझौते को लेकर वार्ता में आशाजनक प्रगति हुई है। हैरिस ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि इस समझौते को करने का समय आ गया है। जो लोग युद्धविराम और शांति चाहते हैं, मैं उन्हें देख रही हूं और सुन रही हूं। आइए, हम यह समझौता करें ताकि हम युद्ध समाप्त कर सकें, बंधकों को घर वापस लाया जा सके और फलस्तीनियों को अत्यावश्यक राहत प्रदान की जा सके।

श्रीलंका में 21 सितंबर को होगा राष्ट्रपति पद का चुनाव

कोलंबो। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव आगामी 21 सितंबर को होंगे। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। इसी के साथ देश में महीनों से जारी इन अटकलों पर विराम लग गया कि निर्वतमान राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे का कार्यकाल बढ़ाने के लिए चुनाव की तारीख आगे खिसका दी जाएगी। सरकारी गजट संख्या 2394/51 शुक्रवार को जारी की गई, जिसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद-31 (3) के तहत मतदान 21 सितंबर को होगा, जबकि 15 अगस्त को नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का शेष कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिन्हें आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने पर 2022 के मध्य में इस्तीफा देना पड़ा था। नवंबर 2019 में जब पिछला राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तब राजपक्षे ने लगभग सात लाख मतों से जीत दर्ज की थी।

दरअसल, वर्ष 1948 के बाद से सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में 2022 की शुरुआत में लाखों लोग तत्कालीन राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। राजपक्षे को नौ जुलाई 2022 को देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसके बाद संसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को उनका उत्तराधिकारी चुना था। विक्रमसिंघे ने श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से बेलआउट पैकेज हासिल करने में सफलता पाई। भारत ने भी 2022 की पहली तिमाही में श्रीलंका को चार अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, जिससे आर्थिक संकट के बीच भोजन और आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान किया गया। विक्रमसिंघे सुधारों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। उन्होंने श्रीलंका को दिवालियापन से बाहर निकालने का संकल्प लिया है।

सूर्यकुमार और गंभीर के नए युग में दबदबा बरकरार रखने के लिए उतरेगी भारतीय टीम

भाषा। पालेकल (श्रीलंका)

भारतः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज।
श्रीलंकाः दिनेश चांदीमल, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), वानिंदु हसरंगा, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, चामिंदु विक्रमसिंघे, बिनुरा फर्नांडो, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना, डुनिथ वेलालगे।

गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की नवनियुक्त कोच और कप्तान की जोड़ी के साथ भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाली तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में अपनी विशेष छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। दो बार के विश्व कप विजेता गंभीर मुख्य कोच के रूप में जबकि टी20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार खेल के इस छोटे प्रारूप में कप्तान के रूप में अपनी नई पारी शुरू करेंगे। गंभीर आईपीएल में कप्तान और मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में काफी सफल रहे हैं। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे जिनके कोच रहते हुए भारत ने अच्छी सफलताएं हासिल की थी। द्रविड़ के मुख्य कोच रहते हुए भारत ने आईसीसी प्रतियोगिताओं में तीनों प्रारूप के फाइनल में जगह बनाई तथा गंभीर को अब इन सफलताओं को नए मुकाम पर पहुंचाना होगा।

सूर्यकुमार को कप्तान बनाना थोड़ा हैरानी भरा फैसला रहा क्योंकि रोहित शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद हार्दिक पंड्या को इस पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। चयन समिति ने सूर्यकुमार के कप्तान के रूप में कम अनुभव को नजरअंदाज करके उन्हें टीम की कमान सौंपी है।

अगला टी20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा तथा चयनकर्ताओं के पास उसके लिए टीम तैयार करने के लिए अभी काफी समय है। भारतीय टीम में यह बदलाव पिछले महीने विश्व कप जीतने तथा रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आया है। भारतीय टीम जब परिवर्तन के दौर से गुजर रही है तब सीमित ओवरों की टीम के उप कप्तान शुभमन गिल इसे अपनी जगह पक्की करने के अवसर के रूप में देख रहे होंगे। केवल वही नहीं यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और यहां तक कि रियान पराग जैसे अन्य खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहेंगे

अक्षर पटेल टीम में जडेजा की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके अलावा भारत के पास हार्दिक, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर के रूप में अच्छे ऑलराउंडर भी मौजूद हैं। जसप्रीत बुमराह को इस दौरे से विश्राम दिया गया है तथा उनकी अनुपस्थिति में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज यहां की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाकर टीम में अपनी जगह मजबूत करना चाहेंगे। जहां तक श्रीलंका की बात है तो वह तेज गेंदबाजी विभाग में कमजोर नजर आता है क्योंकि उसके दो अनुभवी गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा (ब्रोंकाइटिस और श्वसन संक्रमण) और नुवान तुषारा (उंगली में फ्रैक्चर) श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका को टीम में लिया गया है।

श्रीलंका के टी20 विश्व कप में जल्दी बाहर होने के बाद कप्तान वानिंदु हसरंगा, कोच क्रिस सिल्वरवुड और सलाहकार कोच महेला जयवर्धने ने अपना पद छोड़ दिया था। श्रीलंका ने सनथ जयसूर्या को अंतरिम कोच नियुक्त किया है जिन्होंने अपनी टीम को भारत के स्टार खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिए कहा है लेकिन वह अपनी टीम की कमजोरी से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं।

भारत की तरह श्रीलंका भी नए दौर की शुरुआत करेगा। उसने कप्तानी की जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज चरिथ असलांका को सौंपी है। श्रीलंका घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाकर जीत हासिल करना चाहेगा। उसके पास कई अनुभवी खिलाड़ी है जिनमें पूर्व कप्तान दासुन शनाका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल शामिल हैं।

मुझे नेतृत्व करना अच्छा लगता है, मैंने अलग-अलग कप्तानों से काफी कुछ सीखा है: सूर्यकुमार

पालेकल (श्रीलंका)। भारतीय टी20 टीम के नवनियुक्त कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उन्होंने मैदान पर नेतृत्व करने का पूरा लुत्फ उठाया है तथा पिछले कई वर्षों में अलग-अलग कप्तानों की अगुवाई में खेलते हुए उन्होंने काफी कुछ सीखा है। भारतीय टीम के विश्व चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा ने सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था। इसके बाद उनकी जगह सूर्यकुमार को कप्तान ने किया गया। उन्हे हार्दिक पंड्या पर प्राथमिकता दी गई जिन्हे पहले टी20 टीम की कप्तानी का दावेदार माना जा रहा था।सूर्यकुमार कप्तान के रूप में अपनी शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाली तीन मैच की टी20 श्रृंखला से करेंगे।मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने बीसीसीआई टीवी से कहा, भले ही मै कप्तान नही था लेकिन मैंने हमेशा मैदान पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका का लुत्फ उठाया है। मैंने हमेशा अलग-अलग कप्तानो से काफी कुछ सीखा है। यह अच्छा एहसास और बड़ी जिम्मेदारी है। नए कप्तान सूर्यकुमार और नए मुख्य कोच गौतम गंभीर की मौजूदगी मे भारतीय टी20 टीम नए दौर की शुरुआत करेगी। सूर्यकुमार कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की तरफ से 2014 मे गंभीर की अगुवाई मे इंडियन प्रीमियर लीग मे खेल चुके है और इन दोनो के आपस मे काफी अच्छे संबंध है। सूर्यकुमार ने कहा, यह रिश्ता काफी खास है क्योकि मै 2014 मे केकेआर की तरफ से उनके नेतृत्व मे खेल चुका हूं। यह विशेष था क्योकि वही से मुझे मौके मिले थे। हमारा रिश्ता अब भी मजबूत है। उन्होने कहा, वह (गंभीर) जानते है कि मै कैसे काम करता हूं और जब मै अभ्यास सत्र मे आता हूं तो मेरी मानसिकता क्या होती है। मै यह भी जानता हूं कि वह कोच के रूप मे कैसे काम करने की कोशिश करते है। यह सब हमारे बीच के प्यारे रिश्ते से जुड़ा है और मै यह देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं कि यह कैसे आगे बढ़ता है। सूर्यकुमार ने कहा कि एक कप्तान के रूप मे वह विनम्र बने रहना चाहते है क्योकि वह क्रिकेट को सिर्फ एक खेल के रूप मे देखते है, न कि जीवन के रूप मे।

गंभीर टीम में नए विचार लाएंगे

दुबई। (भाषा) भारत के पूर्व कप्तान रवि शास्त्री ने राष्ट्रीय टीम के नए कोच गौतम गंभीर के सफल होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि वह एक समकालीन कोच हैं जिन्होंने अपेक्षाकृत परिपक्व और सुलझी हुई टीम की बागडोर संभाली है। भारत के पूर्व कोच शास्त्री का मानना है कि 42 वर्षीय गंभीर अपनी नई भूमिका में तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि वह कई खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं और उनका मार्गदर्शन कर चुके हैं। वह पहले से ही टीम करीब हैं।वामहस्त सलामी बल्लेबाज रहे गंभीर ने इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मेंटोर (मार्गदर्शक) की भूमिका निभाई है। शास्त्री ने आईसीसी रीव्यू के नवीनतम एपिसोड में कहा, वह (गंभीर) समकालीन हैं, आईपीएल में उनका सत्र बहुत अच्छा रहा था। मुझे लगता है कि वह सही उम्र है जहां वह युवा है, वह नए विचारों के साथ आएगा। वह आईपीएल टीमों का हिस्सा रहा है ऐसे में खासकर सफेद गेंद प्रारूप के ज्यादातर खिलाड़ियों को जानता हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वह टीम में नयापन लेकर आएगा। उन्होंने कहा, हम गौतम को जानते है, उसे अनुशासन पसंद है। उसके भी अपने विचार होंगे।

भारतीय हॉकी टीम पदक की प्रबल दावेदार बस अपना स्वाभाविक खेल दिखाएं : हरेंद्र सिंह

नई दिल्ली (भाषा)। कैरियर की शुरूआत से अब तक के उनके सफर को करीब से देखने वाले अनुभवी कोच हरेंद्र सिंह का मानना है कि भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में पदक की प्रबल दावेदार है। उनकी टीम को एक ही सलाह है, बस अपना स्वाभाविक खेल दिखाओ। अप्रैल 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बनने के बाद भाषा को दिए पहले इंटरव्यू में हरेंद्र ने कहा , मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि अपना स्वाभाविक खेल दिखाओ। भारतीय टीम पदक जीतने में सक्षम है। मैं पदक के रंग को लेकर कयास नहीं लगाऊंगा लेकिन पदक मिलेगा और यह मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं। उन्होंने कहा , भारत के पास अच्छी फॉरवर्ड लाइन है , शानदार मिडफील्डर और गोलकीपर पी आर श्रीजेश के रूप में भारतीय हॉकी की दीवार है। इसके अलावा हरमनप्रीत जैसा कूल कप्तान है। अमेरिका की पुरूष टीम के मुख्य कोच रहे 55 वर्ष के हरेंद्र ने कहा , क्रेग फुल्टोन शानदार कोच हैं और ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं। उन्हें पता है कि चैम्पियन टीम बनने के लिए क्या चाहिए और दबाव के हालात से कैसे निपटना है। उन्हें यूरोपीय और भारतीय हॉकी का काफी अनुभव है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हरेंद्र 2000 सिडनी ओलंपिक, 2005 जूनियर विश्व कप, 2006 विश्व कप, 2006 एशियाई खेल, 2009 एशिया कप और 2010 पुरूष हॉकी विश्व कप में विभिन्न भूमिकाओं में भारत की सीनियर और जूनियर टीमों के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं। वह 2016 में लखनऊ में जूनियर विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कोच थे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत 2016 की जूनियर टीम का हिस्सा थे।

SBI भारतीय स्टेट बैंक,
होम लोन सेंटर-2, रामा कॉम्प्लैक्स, सोहना रोड, बादशाहपुर, गुड़गाँव-122016

(नियम-8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक, होम लोन सेंटर-2, बादशाहपुर गुड़गांव शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार श्री नवीन कुमार और निधि को एक मांग नोटिस दिनांक **05.01.2024 को जारी** किया था जिसमें उल्लेखित राशि **रू 6,20,857/- (रु. छह लाख बीस हजार आठ सौ सत्तावन मात्र) और दिनांक 05.01.2024 से और भविष्य का ब्याज, लागत इत्यादि सहित** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **25.07.2024** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, होम लोन सेंटर-2, बादशाहपुर गुड़गांव के प्रभार वास्ते राशि रू 6,20,857/- (रु. छह लाख बीस हजार आठ सौ सत्तावन मात्र) और दिनांक 05.01.2024 से भविष्य का ब्याज, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्राथमिक प्रतिभूतिः सम्पत्ति पर मालिकाना हकः श्रीमती निधि पत्नी श्री नवीन
बंधक मकानः खसरा नं. 25/11/20, बिक्री बिलेख नं. 21058, दिनांकित 06.01.2006 (मकान नं. 689/22) शिवाजी पार्क, गुड़गाँव, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, चौहद्दीः
पूरब में – 10फीट रास्ता — पश्चिम में – अज्ञात मालिक
दक्षिण में – अज्ञात मालिक — पश्चिम में – अन्य मालिक का प्लॉट

दिनांकः 25.07.2024 स्थानः गुरूग्राम — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
विवेक विहार शाखा

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 का एक्ट 54) के प्रवर्तन के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विवेक विहार, दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत उधारकर्ता श्री नफीस अहमद एवं श्री हसमत अली, को एक मांग सूचना दिनांक 12.04.2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 8,11,579.54 (रु. आठ लाख ग्यारह हजार पाँच सौ उनारी और पैसे चौवन मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये हैं इसलिये एतद्वारा उधारकर्ता और गारंटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 20.07.2024 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विवेक विहार, दिल्ली के प्रभार वास्ते राशि रू 8,11,579.54 और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति एमआईजी फ्लैट नं. जी-1, क्षेत्रफल 720 वर्ग फीट, प्लॉट नं. जी-139 पर निर्मित, खसरा नं. 1076/5/2/887 में से, दिलशाद एक्सटेंशन नं. 1, गाँव झिलमील ताहीरपुर के क्षेत्र में, इलाका, शाहदरा, दिल्ली-110095 में स्थित, चौहद्दीः
पूरब में – भवन नं. जी-138 — पश्चिम में – भवन नं. जी-140
उत्तर में – रोड — दक्षिण में – मेन रोड न. 70

दिनांकः 20.07.2024, स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

उद्घाटन समारोह में एथलीट परेड में हिस्सा लेगा 78 सदस्यीय भारतीय दल

भाषा। पेरिस

पेरिस ओलंपिक

पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान शुकवार को पीवी सिंधू और अचंत शरत कमल की अगुआई वाला भारतीय दल एथलीट परेड में हिस्सा लेगा जिसमें 12 प्रतिस्पर्धाओं के 78 एथलीट और अधिकारी शामिल होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने कहा कि जिन सभी खिलाड़ियों ने खुद को उद्घाटन समारोह के लिए उपलब्ध कराया है, वे परेड का हिस्सा होंगे।आईओए ने कहा, आईओए अध्यक्ष पीटी ऊषा और दल प्रमुख गगन नारंग ने एथलीट परेड में दल की संरचना में खिलाड़ियों को शीर्ष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, कई खिलाड़ियों की शनिवार को प्रतिस्पर्धा है और आईओए ने उनकी तैयारियों को प्राथमिकता देने और उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेने के फैसले का सम्मान किया है। ध्वजवाहक सिंधू और शरत कमल के अलावा अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में तीरंदाज दीपिका कुमारी, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना शामिल हैं। नौकाचालक बलराज पंवार की शनिवार सुबह रेस है तो वह एथलीट परेड का हिस्सा नहीं बनेंगे। ट्रैक एवं फील्ड, भारोत्तोलन और कुश्ती की टीम अभी तक पेरिस नहीं पहुंची हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का भी शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है तो केवल तीन रिजर्व खिलाड़ी ही समारोह में शामिल होंगे। भारत का 117 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है जिसमें 47 महिलाएं हैं। ओलंपिक इतिहास में पहली दफा उद्घाटन समारोह स्टेडियम में नहीं हो रहा बल्कि यहां सीन नदी के किनारे पर होगा। 90 नौकाओं में 6,500 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे।

सबसे युवा भारतीय अधिकारी होंगे साइ अशोक

नई दिल्ली। भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज के साइ अशोक पेरिस ओलंपिक मे भारत के सबसे युवा अधिकारी होगे जिन्हे शुक्रवार से शुरू हो रहे खेलो मे शैफ़ डी जज बनाया गया है। 32 वर्ष के अशोक 1904 के बाद चौथे भारतीय है जो ओलंपिक मे अधिकारी होगे। वह विश्व चैम्पियनशिप स्पर्धा मे बतौर खिलाड़ी और अधिकारी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति है। पुणे के सैन्य खेल संस्थान मे मुक्केबाजी प्रशासक के तौर पर काम करने वाले अशोक विश्व सैन्य मुक्केबाजी परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय भी रहे।

30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल			समेकित		
		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
		30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1.	जारी प्रचालन से कुल आय	10,850.37	10,888.23	45,815.37	11,279.59	11,257.60	46,913.12
2.	जारी प्रचालन से कर पूर्व निवल लाभ (विनियामक स्थगन खाता शेष सहित (निवल कर))	4,231.93	4,041.54	18,009.46	4,603.22	4,218.30	18,513.95
3.	जारी प्रचालन से कर पश्चात् निवल लाभ	3,412.15	3,484.58	15,377.48	3,723.92	3,597.16	15,573.16
4.	बंद प्रचालन से कर पश्चात् निवल लाभ	-	58.07	97.13	-	-	-
5.	अवधि हेतु कर पश्चात् निवल लाभ	3,412.15	3,542.65	15,474.61	3,723.92	3,597.16	15,573.16
6.	कर के बाद निवल लाभ और अन्य व्यापक आय को मिलाकर कुल व्यापक आय	3,457.06	3,475.31	15,241.72	3,768.40	3,529.50	15,338.55
7.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य : ₹ 10/- प्रत्येक)	9,300.60	6,975.45	9,300.60	9,300.60	6,975.45	9,300.60
8.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) तुलनपत्र में दर्शाए गए रूप में	81,023.51	79,344.04	77,566.45	81,612.77	79,581.07	77,844.51
9.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	5,509.28	7,834.43	5,509.28	5,509.28	7,834.43	5,509.28
10.	निवल मूल्य	90,324.11	86,319.49	86,867.05	90,913.37	86,556.52	87,145.11
11.	कुल ऋण	1,23,465.20	1,23,717.15	1,23,448.62	1,23,465.20	1,23,717.15	1,23,448.62
12.	ऋण इक्विटी अनुपात	1.37	1.43	1.42	1.36	1.43	1.42
13.	जारी और बंद प्रचालन से प्रति इक्विटी शेयर अर्जन विनियामक की स्थगन खाता शेष में संचलन सहित (प्रति शेयर अंकित मूल्य : ₹ 10/-) : मूल और तनुकृत (₹)	3.67	3.81	16.64	4.00	3.87	16.74
14.	जारी और बंद प्रचालन से प्रति इक्विटी शेयर अर्जन विनियामक की स्थगन खाता शेष में संचलन छोड़कर (प्रति शेयर अंकित मूल्य : ₹ 10/-) : मूल और तनुकृत (₹)	3.73	4.18	17.25	4.07	4.24	17.36
15.	बॉन्ड शोधन आरक्षित	2,589.49	3,834.73	2,921.02	2,589.49	3,834.73	2,921.02
16.	ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	1.57	1.73	1.65	1.67	1.77	1.69
17.	ब्याज सेवा व्याप्ति अनुपात	4.00	4.15	4.10	4.39	4.33	4.27

टिप्पणियाँ : 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट **https://www.powergrid.in** के निवेशक खण्ड में तथा बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **https://www.bseindia.com** और **https://www.nseindia.com** के कॉर्पोरेट खण्ड में उपलब्ध है।
2. जहां आवश्यक है, वहां पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते और **पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** की ओर से
हस्ता./-
जी. रविशंकर, निदेशक (वित्त)
DIN: 08816101

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 26 जुलाई, 2024

पावरग्रिड POWERGRID
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001
सीआईएन : L40101DL1989GOI038121
हमें फालो करें
www.powergrid.in
एक महारत्न पीएसयू

महिला मुक्केबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद : विजेंदर

नई दिल्ली। (भाषा) भारत के एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता पुरुष मुक्केबाज विजेंदर सिंह को लगता है कि पेरिस ओलंपिक में देश की पदक की संभावनाएं महिला मुक्केबाजों के प्रदर्शन पर निर्भर होंगी और उन्हें उम्मीद है कि निकहत जरीन की अगुआई वाली टीम कम से कम दो पोडियम स्थान हासिल करेगी। जरीन (50 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), जैस्मिन लम्बोरिया (57 किग्रा) और तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा) भारतीय महिला टीम में शामिल हैं जबकि अमित पंघाल (51 किग्रा) और पदार्पण कर रहे निशांत देव (71 किग्रा) पेरिस के लिए क्वालीफाई करने वाले दो पुरुष मुक्केबाज हैं। पीटीआई संपादकों के साथ यहां समाचार एजेंसी के मुख्यालय में बातचीत के दौरान 38 वर्षीय विजेंदर ने कहा कि उन्हें महिला मुक्केबाजों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। बीजिंग ओलंपिक 2008 के कांस्य पदक विजेता और भाजपा नेता विजेंदर ने कहा, पुरुष मुक्केबाजों के बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं जानता लेकिन मैंने महिला मुक्केबाजों के बारे में जो पढ़ा है, उससे उम्मीद जगती है कि लड़कियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी, मुझे उम्मीद है कि हमें एक या दो पदक मिलेंगे।

भारत के 12 साल के पदक सूखे को खत्म करने को तैयार है निशानेबाजी दल

शेटौरॉक्स (फ्रांस)।(भाषा) ओलंपिक में पदार्पण करने वाले निशानेबाजों से भरी टीम पिछले प्रदर्शन के बोझ से मुक्त होकर शुक्रवार को फ्रांस के शेटौरॉक्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में होने वाली परीक्षा में सफल होने का लक्ष्य बनाएगी। भारत ने अभी तक निशानेबाजी में कुल चार ओलंपिक पदक जीते हैं लेकिन पिछले दो ओलंपिक में खाता खाली रहा जिससे रिकॉर्ड 21 सदस्यीय भारतीय दल पर उम्मीदों का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ (एनआरएआई) टीम चुनने के लिए मौजूदा फॉर्म को तरजीह दी है और उसे उम्मीद है कि इस बार वे यहां पदक जीतेंगे। इसलिए ही कोटा विजेताओं को भी ट्रायल में उतारा गया जिसमें कम अनुभवी संदीप सिंह ने 2022 के विश्व चैम्पियन रुद्रांक्ष पाटिल को पछाड़ दिया जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए कोटा हासिल किया था। पाटिल ने एनआरएआई को पत्र लिखकर ट्रायल में बरकरार रखने की बात रखी, लेकिन महासंघ अपने फैसले पर अड़ा रहा। मनु भाकर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अंजुम मौदगिल और इलावेनिल वलारिवान को छोड़कर अन्य सभी निशानेबाज पहली बार ओलंपिक मंच का अनुभव करेंगे।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड,ए-8, सेक्टर-7, जिला-गौतमबुद्ध नगर, नोएडा (उ.प्र.)-201301, दूरभाष-01202470700 से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-205 द्वितीय मंज़िल, प्रताप भवन, 5 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष:011-69342500।